Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का १७ वां दिवस [संख्या १४

शुक्रवार, दिनांक १२ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११. ५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३१३

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३१४

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३१५

श्री मोहनराज ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३१६

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रामकिशन ।

नीम का थाना के भूतपूर्व एस. डी. ओ. के विरुद्ध जांच

३१७. श्री **रामकिशन** (वैर) [श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) द्वारा पूछा गया] : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नीम-का-थाना के भूतपूर्व एस. डी. ओ. श्री ताराचन्द के विरुद्ध जो जांच चल रही थी उसमें क्या कार्यवाही हुई?

(२) क्या यह वाका है कि श्री ताराचन्द के विरुद्ध ४६७ ता० हि० अथवा ता० हि० की किसी अन्य धारा के तहत फर्जी

Page No 2

(श्री रामकिशन)

दस्तावेज बनाने के संबंध में मुकदमा चलाने की बात सरकार सोच रही है ?

(३) अब तक मुकदमा दायर न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या पुलिस ने कोई प्रारंभिक जांच की है ? अगर हां, तो उसमें पुलिस के किस अफसर ने कब क्या रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की है और सरकार ने उसमें अब तक क्या किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : इस प्रश्न का उत्तर कल दे देंगे ।

प्रश्न संख्या ३१८

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३१९

श्री कृष्णकुमार गोयल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३२०

श्री भैरोंसिह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत):

प्रश्न संख्या ३२०

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : आपको वे अख्त्यार दे गए हैं क्या ? फिर वे आएंगे, दुबारा पूछेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अख्तयार तो नहीं है, लेकिन नहीं तो वह फिर लैप्स हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष : ये सारे प्रश्न फिर से ले लेंगे यदि समय रह जायगा तो ।

प्रश्न संख्या ३२१

श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रानानन्द अग्रवाल ।

अलवर शहर की स्कीम नं० २ में मीठे पानी की व्यवस्था

३२२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की स्कीम नं० २ के एरिया में पानी की जो नई टंकी बनाई गई है उसका पानी कुछ खारा है और भारी है जिससे वह पीने और नहाने तथा दाल वगैरह बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता ?

(२) क्या यह सही है कि अलवर शहर की वह जनता, जिसको यह पानी सप्लाई

Page No 3

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किया जा रहा है, बहुत परेशान है और उसकी ओर से असिस्टेन्ट इन्जीनियर वाटर वर्क्स को शिकायत की गई है ?

(३) इस क्षेत्र में इस खारे और भारी पानी को बन्द करके मीठा और हल्का पानी सप्लाई करने के लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है और वह प्रबन्ध कब तक हो जावेगा ?

उप-मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) ऐसी बात नहीं है। पानी पीने, नहाने आदि के लिए उपयुक्त है ।

(२) सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई परन्तु हां यह बात ठीक है कि इस सम्बन्ध में उस क्षेत्र के निवासियों को शिकायत असिस्टेन्ट इन्जीनियर वाटर वर्क्स को प्राप्त हुई थी । इस पर इस पानी का केमीकल एनेलिसिस कराया गया और मनुष्यों के पीने के लिए उपयुक्त पाया गया।

(३) चूंकि यह पानी मनुष्यों के पीने के लिए उपयुक्त है, अतः ऐसी स्थिति में दूसरा प्रबन्ध करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस पानी की केमीकल एनेलिसिस कराई गई थी और उसमें यह हार्ड वाटर पाया गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां, कुछ अंश तक हार्ड वाटर है लेकिन राजस्थान में बहुत सी जगह हार्ड वाटर है, लेकिन यह पानी पीने के लिए उपयुक्त है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि अलवर के दूसरे भाग में वहां पर इस वाटर वर्क्स से पानी सप्लाई होता है, वहां के वाटर की क्वालिटी सोफ्ट है और उसका जायका भी मीठा है ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : दोनों में अंतर हो सकता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अंतर हो सकता है, या है ? वहां पानी जो पहले से वाटर वर्क्स है उसमें से पानी मीठा और सोफ्ट आता था, अभी एक दूसरी टंकी बनाई गई है, दूसरा कुंआ खुदवाया गया है, उसमें से कुछ का पानी हार्ड है और पानी का जायका खारा है । मंत्राणीजी का कहना सही नहीं है कि वह खारा नहीं है क्योंकि मुझे स्वयं परिचय है, मैं उसी एरिया में रहता हूँ, उसका पानी इस्तेमाल करता हूँ इसलिए केवल कुछ रेडटेपिस्ट की रिपोर्ट्स को आधार न बनाए और माननीय सदस्यों की बात पर यकीन करें । इसलिए जहां दूसरी जगहों पर अच्छा पानी उपलब्ध नहीं हो वहां पर हार्ड वाटर है और गलत जगह पर कुएं खुदवाए गए, उनको बंद किया जाए और दूसरे कुएं से सप्लाई किया जाय तो मीठा पानी मिल सकता है इसमें सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जैसे कि मैंने

Page No 4

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

निवेदन किया उस पानी का एग्ज़ामिनेशन करवाया गया था और वह पीने के लिए उपयुक्त है। लेकिन फिर भी जैसे आप कह रहे हैं मैं पुनः जानकारी करूंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले भी इस सदन में यह बात आई है कि माननीय सदस्यों की बात को कुछ वज़न दिया जाना चाहिये, मैं उसी क्षेत्र में रहता हूँ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसलिए मैंने निवेदन किया कि फिर से जानकारी की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि वह पानी हार्ड पाया और दूसरे हिस्से में अच्छा पानी उपलब्ध है तो क्या सरकार आश्वासन देगी कि उस पानी को जो ख़राब है उसको बंद करके अच्छा पानी सप्लाई कर देगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : हाइपोथेटीकल आश्वासन तो मैं नहीं दे सकती; जांच करा लेने पर जो उपयुक्त होगा किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें हाई-पोथेटीकल की क्या बात है ? मैंने कहा, वहां पानी खारा है। वे कहते हैं कि एनेलिसिस में भी हार्ड पाया गया। शहर के दूसरे हिस्से में अच्छा मिल रहा है तो फिर आश्वासन देने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया ने कहा है कि जांच करा कर कह सकती हैं कि कितना पानी है और इन्जीनियर्स ही कहेंगे। पानी उपलब्ध है तो सामान्य तौर से उनको असुविधा नहीं होनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह भी कहने के लिए तैयार नहीं हैं।

प्रश्न संख्या ३२३

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

गाड़ियों एवं ठेलों पर टैक्स, जालौर

३२४. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि नगरपालिका जालौर ने काश्तकारों की गाड़िया व ठेलों पर नगरपालिका क्षेत्र में आने का टैक्स लगाया है ?

(२) क्या यह सच है कि उपरोक्त टैक्सों को माफ करने का मामला नगरपालिका जालौर द्वारा सरकार के समक्ष भेजा गया है ? अगर हां, तो सरकार उपरोक्त टैक्स माफी का निर्णय कब तक कर देगी ?

(३) क्या यह सच है कि उपरोक्त

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

टैक्स लगाने से जालौर की अनाज मंडी समाप्त हो गई है, और इससे जालौर नगरवासियों को बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार काश्तकारों एवं नगरवासियों के हित में उपरोक्त टैक्स शीघ्र माफ करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं । (२) व (३) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : नगरपालिका जालौर क्षेत्र में काश्तकार रहते हैं, पड़ौस में खेती करते हैं और वहां से अपना सामान नगरपालिका में लाते हैं, तो उस पर टैक्स लगता है । क्या टैक्स नहीं लगता है ?

श्री दौलतराम सारण : आपने सामान के लिए नहीं पूछा था । जनाब आपने गाड़ियों और ठेलों के लिए पूछा कि उस पर टैक्स लगाया है तो उत्तर में यह कहा गया कि नहीं लगाया गया ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सामान लेकर आते हैं ठेलों और गाड़ियों में नहीं तो किसमें लावेंगे । जो कुछ भी पूछा है उसका ही बता दीजिये । गाड़ी और ठेलों में सामान लेकर आते हैं तो ओक्ट्रॉय लगता है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : सामान पर ऑक्ट्रोय लगता है ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सैर करने के लिए थोड़े ही आते हैं किसान !

श्री रघुनाथ बिश्नोई : राज्य सरकार के सामने यह प्रस्ताव आया है कि तीन हजार के लगभग इससे आमदनी है और वहां इस कारण से बड़ी अच्छी मंडी थी वह उजड़ गयी है, किसान लोग सामान नहीं लाते हैं और आस-पास के गांवों में देते हैं और इस कारण लोग मंडी में आना छोड़ रहे हैं ।

श्री दौलतराम सारण : यह एक विचारधारा है । नगरपालिका ने प्रस्ताव भेजा । राज्य सरकार ने उस पर दुबारा स्पष्टीकरण कराया कि आमदनी पर क्या फर्क पड़ेगा ? वह अब आया है और सरकार के विचाराधीन है । ५ हजार और कुछ रुपयों का नगरपालिका को इससे घाटा रहेगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ५ हजार का नहीं है । कलेक्टर ने जवाब भेज दिया कि तीन हजार की आमदनी होगी । लोगों को बड़ी भारी असुविधा हो रही है । बड़ी मंडी है और वह खराब हो गई है । मंडी में अनाज नहीं आ सकता । राज्य सरकार जल्दी निर्णय करे तो अच्छा है ।

श्री दलपतसिंह : कब से विचाराधीन है ?

श्री दौलतराम सारण : कुछ ही अर्से से । नगरपालिका ने ११-१२-६४ को प्रस्ताव किया । १२-१२-६४ को हमारे पास भेजा । विभाग की ओर से उस पर स्पष्टीकरण चाहा गया जिसका स्पष्टीकरण १७-२-६५ को वापिस प्राप्त हुआ ।

Page No 6

(श्री दौलतराम सारण)

उन्होंने लिखा कि हमारी पांच हजार के रुपये अनुमानित आय कम होगी। दूध से ५००) रुपये जलाने की लकड़ी से ५००) रुपये व देशी चमड़ा २५००) कुल ५६५०) रुपये एस्टीमेटेड है। यह विचाराधीन है और इस पर फैसला लिया जावेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दो साल से विचाराधीन है। नगरपालिका ने प्रस्ताव भेजा है कि यह छोटी आमदनी है और हम इसको छोड़ देंगे।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैंने तारीखें बतला दी हैं। दो साल का प्रश्न ही नहीं उठता। फरवरी में पत्र आया है और उस पर निर्णय होने वाला है। ऐसी ताकीद क्या है?

श्री रघुनाथसिंह बिश्नोई : दो साल से है। स्पष्टीकरण तो फरवरी में आया है।

श्री दौलतराम सारण : ऐसा नहीं है। १२-१२-६४ को ही प्रस्ताव आया है। फिर उस पर स्पष्टीकरण चाहा और वह फरवरी में आया है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

जयपुर में शक्कर व गेहूं की वितरण व्यवस्था

३२५. श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि जयपुर शहर में राशन की दूकानों पर शक्कर व गेहूं की वितरण व्यवस्था ठीक ठीक नहीं है?

(२) यदि हां, तो इसके लिए क्या उचित व्यवस्था की जा रही है?

उप-मंत्री, खाद्य (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) कोई अव्यवस्था नहीं है। (२) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या यह सही है कि सरकार की ओर से ज्यादातर शहर में दूकानें खुली हुई हैं वहां पर अनाज और चीनी नहीं मिल रही है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट से जनवरी में कोटा देर से मिला था, इसलिए वितरण में देर हुई थी। कोई अव्यवस्था नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या गेहूं उपलब्ध है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या जयपुर शहर में सरकारी दूकानें खुली हुई हैं, वहां गेहूं उपलब्ध है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : जालूपुरा में लोग १५ दिन से जा रहे हैं और उनको

Page No 7

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

कोई गेहूं नहीं मिल रहा है । यह दिक्कत इसलिए आ रही है कि वहां पर चीनी और अनाज समय पर नहीं पहुंचता है और सैंकड़ों लोग इक्ट्ठे हो जाते हैं, लेकिन खाली आना पड़ता है । जब जाते हैं बड़ी भीड़ रहती है। जालूपुरा में अभी भी गेहूं नहीं है, आप जांच करा लीजिए ।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : हो सकता है कि कोटा से अधिक आदमी पहुंच जायं, इसलिए कमी महसूस की गई हो । जितना जहां का कोटा है समय समय पर दिया जाता है ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : पन्द्रह दिन से बराबर अनाज नहीं मिल रहा है। कोटा कम है तो बढ़ा दिया जाय । जिनके पास राशनकार्ड्स हैं वे लोग क्या करेंगे ? जिनको दूकान जो अलॉट की गई है उसी से राशन शक्कर मिलती है। कोई प्रतिबन्ध होना चाहिये ।

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जालूपुरा में अनाज की कमी की बात कही । हमारे पास जालूपुरा के लोगों की कोई शिकायत नहीं आई है इसलिए जानकारी नहीं । अब आपने कहा है कि गेहूं नहीं मिलता, हम इसको देख लेंगे । नहीं है तो भिजवा देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : किसी राशन होल्डर को कोई दूकान निश्चित हुई है उस दूकान से उसको राशन लेना पड़ेगा । किसी दूसरी दूकान से राशन ले सकता है, ऐसी व्यवस्था है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

शारीरिक दृष्टि से लाचार व्यक्तियों को राजकीय सेवा में स्थान

३२६. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) [श्री केदारनाथ (गंगानगर) द्वारा पूछा गया] : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भारत सरकार के गृह विभाग के नोटिफिकेशन नं० एक २०।२६। ५७ आर पी. एस. दिनांक १५ जनवरी, ५८ के जरिये शारीरिक दृष्टि से हेन्डीकेप्ड व्यक्तियों को राजकीय सेवाओं में रहने सम्बन्धी नीति को इंगित किया गया है ? अगर हां, तो राज्य सरकार उपरोक्त नोटिफिकेशन में उल्लिखित नीति को क्रियान्विति किस प्रकार करवा रही है ?

(२) इस प्रकार कितने व्यक्तियों को उपरोक्त कमी के आधार पर बीकानेर जिले में पंचायत समिति सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किया ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां । इस सम्बन्ध में

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

राज्य सरकार द्वारा सन् १९६० में प्रसारित आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कोई नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि दुर्गादास अध्यापक का सिलेक्शन इसलिए नहीं किया गया कि वह फिजिकली हेन्डीकेप्ड था?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, दुर्गादास को इसीलिए नहीं किया गया था क्योंकि वह फिजिकली अनफिट था।

श्री केदारनाथ : इस सर्कूलर में यह कहा गया है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सर्कूलर में डेथ के लिए है। फिजिकल अनफिट इसलिए नहीं किया। सन् ६३ में सरकार ने यह फैसला कर लिया कि ऐसे लोगों को भी रखने में कोई रुकावट नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार में बहरे लोग रखे जा सकते है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां।

If he is otherwise physically fit to perfoım the duty......

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : स्वास्थ्य सम्बन्धी, हाथ-पांव का टूट जाना, यह तो शारीरिक है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस काम के लिये वह पोस्टिंग चाहता है उस काम के लिऐ फिजिकली फिट है या नहीं। मेडिकल बोर्ड बैठता है, वह उसकी जांच करके यह रिपोर्ट सर्टीफाई कर देता है कि जिस पोस्ट के लिए इसकी तकरूर होने वाली है उसके लिए यह फिजिकली फिट है काम करने के लिए तो उसको लिया जाता है।

प्रश्न संख्या ३२७

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३२८

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

श्री जोधसिंह चौहान।

राशनकार्डों के लिये प्रार्थना--पत्र

३२९. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या खाद्य मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) उदयपुर नगर के कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र शक्कर के राशन कार्ड बनवाने के लिपे पैंडिग है और कब से ?

Page No 9

(श्री जोधसिंह चौहान)

(२) क्या यह सही है कि कई जो कर्मचारी तबादले पर उदयपुर आते हैं उनको महीनों तक उनके शक्कर के राशन कार्ड नहीं मिलते हैं ?

(३) राशन कार्ड बनवाये जाने में अधिक से अधिक कितना समय लगना वाजिब है ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) उदयपुर नगर के कोई प्रार्थना-पत्र शक्कर राशन कार्ड बनवाने के लिये पैन्डिंग नहीं है।

(२) जी नहीं।

(३) अधिक से अधिक १५ दिन का समय लगना पर्याप्त है।

श्री जोधसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, महीने भर दर्ख्वास्तें पैन्डिंग पड़ी रहती हैं। कई लोग मेरे पास आये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक ही दर्ख्वास्त पैन्डिंग नहीं है। माननीय सदस्य को मैं सूचना के आधार पर ही निवेदन कर रहा हूं कि एक भी दर्ख्वास्त इस समय पैन्डिंग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री जोधसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, कई लोग मेरे पास आये हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह अहम सवाल है इसलिए मुझे इसको पूछने की आज्ञा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : Yes.

विदेशी अनाज का वितरण

३३०. **श्री रामकिशन** (वैर) [श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राज्य में जनवरी, ६४ से अब तक कितने टन विदेशी अनाज मंगाया गया है ?

(२) मंगाया गया विदेशी अनाज शहरी क्षेत्रों में कितना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितना दिया गया है ?

(३) राज्य में छिपे हुए अनाज को निकालने के लिये कहां-कहां छापे मारे गये हैं और इन छापों में सरकार को कितना अनाज मिला है ?

(४) क्या राज्य से चोरी छिपे अनाज बाहर जाता हुआ पकड़ा गया है ? यदि हां, तो कितना ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) राज्य में जनवरी ६४ से जनवरी ६५ तक लगभग ४,५०,००० टन गेहूं मंगाया गया।

(२) शहरी क्षेत्र से लगभग २,७३,०६४.५७४ टन व ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग १,५१,१५६.२२६ टन दिया गया है।

Page No 10

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(३) राज्य में छिपे हुए अनाज के लिए लगभग सभी जिलों में छापे मारे गये जिनमें लगभग १०६२.०८६.५०० टन अनाज मिला।

(४) हां। लगभग ४८५.६६३.५०० अनाज पकड़ा गया है।

श्री नत्थीसिंह : ये जो आपने आंकड़े दिये हैं किस महीने से किस महीने तक के दिये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जनवरी ६४ से जनवरी ६५ तक।

श्री नत्थीसिंह : ग्रामीण क्षेत्रों से इस प्रकार की शिकायत आती रहने पर भी कि हमें अनाज नहीं दिया जा रहा है दूकानें बन्द कर दी गईं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह ठीक बात है। जब से हमारा कोटा १५ हजार टन और दस हजार टन रह गया है उस वजह से गेहूं न होने की वजह से गांवों में सब जगह नहीं दे सके। फसल खरीफ की आ चुकी है, रबी की आने वाली है, गेहूं की हालत में काफी परिवर्तन आया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : डिस्ट्रिक्ट वाइज़ पोपुलेशन के आधार पर कोटा मुकर्रर करके आया था या किस तरह ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक अर्बन एरियाज़ का प्रश्न है वहां इस गेहूं का वितरण आबादी के लिहाज से और शहरों में प्रति व्यक्ति के हिसाब से कोटा अलॉट करते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह आपका १५ से १० हजार टन कब से हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मार्च के महीने का दस हजार टन होगा।

श्री भैरोंसिंह : यह कोटा कम होने के क्या कारण है ? राज्य सरकार ने कितना मांगा और कितना दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें राज्य सरकार के मांग करने का प्रश्न नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, पिछले महिनों में अमेरिका में लेबर स्ट्राइक की वजह से हमारे यहां अनाज नहीं पहुंच सका, उसकी वजह से सारे देश की पोज़ीशन में काफी परिवर्तन आया है। इस कारण जितनी स्टेट्स को कोटा अलॉट करते थे उसमें सब में कमी की गई। उसी के अनुसार अपने यहां भी कम किया गया। अभी कुछ दिनों से स्थिति सुधार पर है, काफी अनाज आ रहा है। हम अब बफर स्टॉक बनाने की भी स्थिति में आ सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार हर माह जितनी रिक्वायरमेन्ट्स होती हैं उसी के आधार पर इन्डेन्ट भेजती होगी ?

Page No 11

श्री नाथूराम मिर्धा : रिक्वायरमेन्ट्स का इन्डेन्ट भेजना पिछले दो-तीन महीनों से नहीं रहा। रिक्वायरमेंट्स के बारे में पहले ही सब स्टेट्स का तय हो चुका था वह मिलता रहा है। स्टेट्स की मांग ज्यादा रही है इसलिये इन्डेन्ट्स भेजने की स्थिति नहीं रही, इसलिये जितना वे दे सकते थे दिया है और आगे भी देंगे।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार ने यह तो मांग की होगी कि इतना टन मिलना चाहिये उस हिसाब से कितना कम मिला ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान को पिछले दो महीने में १५ हजार टन और मार्च में दस हजार टन मिला है। जहां पहले हमारे पास पचास हजार टन बराबर आता रहा है वे अगर उसको कायम रख सकते तो वे उतना अनाज हमें दे सकते थे और हमारे भावों में सुधार हो सकता था। लेकिन परि-स्थिति ऐसी आ गई, जिसमें इम्पोर्ट्स में दिक्कत हो गई, इसमें भारत सरकार की मजबूरी है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार पचास हजार टन की मांग करती रही है और फरवरी और मार्च में १५ हजार और दस हजार टन मिला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मांग का सवाल नहीं है। केन्द्रीय सरकार अपनी स्थिति के अनुसार देती रही है। जो उनकी स्थिति से बाहर की बात थी उसमें वे क्या कर सकते थे, वैसी स्थिति में हमारी भी लगातार मांग करने से क्या हो सकता था ? हम फिर भी समय-समय पर कहते रहे हैं कि पन्द्रह हजार टन में काफी मुसीबतें आ रही हैं; दस हजार टन में और ज्यादा मुसीबतें होंगी। समय पर मिनिस्टर लेवल तक इस संबंध में बातचीत होती रही है।

श्री भैरोंसिंह : पहले जब हमें पचास हजार टन का कोटा मिलता था, अब दस हजार टन हो गया तो मैं जानना चाहता हूँ, आपने किस-किस महीने में कितनी-कितनी मांग की थी। कहीं हमने यह मांग तो कम नहीं की ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर तो स्पष्ट आ चुका है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हम इसके बारे में हाइएस्ट लेवल तक कहते आये हैं जो हमारी स्थिति थी वह बराबर रखते आये हैं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आप यह बताने की कृपा करेंगे, कोटा केवल हमारी स्टेट के लिए भी कम किया गया या दूसरी स्टेट्स में भी कम किया गया; यदि किया गया तो कितने प्रतिशत कम किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : करीब-करीब चालीस प्रतिशत कोटा काटा है। यह मुझे जानकारी है।

प्रश्न संख्या ३३१

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

चम्बल की मुख्य नहर पर सोरखंड ब्रीच

३३२. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

(१) चम्बल की दांई मुख्य नहर पर सोरखंड ब्रीच कब व क्यों हुआ ?

(२) इसकी मरम्मत पर कब-कब, कितना-कितना व्यय हुआ ?

(३) क्या इस संबंध में कोई टैक्निकल रिपोर्ट भी आई है ? अगर हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) पहला ब्रीच १२ दिसम्बर, १९६० और दूसरा १६ जनवरी, सन् १९६४ को हुआ। ब्रीच संबंधी रिपोर्ट की कॉपी संलग्न है।

(२) पहले ब्रीच को ठीक करवाने में लगभग १,१५,००० रु० १९६०-६१ में और दूसरे पर लगभग ८२,००० रु० १९६४-६५ में खर्च हुआ। पहली रकम में नहर की पाल को सुदृढ़ करने का खर्च भी शामिल है।

(३) जी हां, रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्णकुमार गोयल : पहला जब ब्रीच हुआ उसके संबन्ध में इन्क्वायरी या जांच नहीं करवाई गई ?

श्री दौलतराम सारण : विभागीय अधिकारियों ने जांच की थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जांच करने वाले कौन अधिकारी थे और कौन सी तारीख को जांच की थी ?

श्री दौलतराम सारण : आपको जो रिपोर्ट दी है उसके अन्दर सब विवरण है एक्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर ने जांच की थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कौन थे एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर ?

श्री दौलतराम सारण : नाम मुझे पता नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ६०-६१ के अन्दर ब्रीच हुआ उसके बाद में ६४ में ब्रीच हुआ; दोनों बार मरम्मत में लाखों रुपया खर्च हुआ। यह जो रिपोर्ट है वह सैकन्ड ब्रीच के बाद की है। आपने पहले ब्रीच की जांच करवाई उसमें किस कारण से ब्रीच हुआ और वह जांच किसने की थी, उनकी जांच के क्या परिणाम थे ?

श्री दौलतराम सारण : आपने अगर रिपोर्ट पढ़ी होती तो यह आपको कहने की नौबत नहीं आती। ब्रीच क्यों हुआ उसका कारण उसमें बताया हुआ है सैलाइन सोइल में है इसलिये ब्रीच हुआ। टैक्निकल जांच

(श्री दौलतराम सारण)

दुबारा करवाई गई उसमें उसको ठीक नहीं माना गया । उससे यह परिणाम निकला कि नीचे कोई नेचुरल सुराख रह गया जिसके कारण यह ब्रीच हुआ है । नई नहर जो होती है उसमें पानी रिसता है उसमें ब्रीच होना स्वाभाविक है । कभी-कभी प्राकृतिक रूप से सुराख रह जाते हैं उससे भी हो जाता है । इसलिये पहले भी ब्रीच को ठीक किया गया और दूसरे को भी ठीक कराया गया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आरम्भ के अन्दर जो ब्रीच हुआ उसका मेन रीज़न क्या मानते हैं ? पहली रिपोर्ट में विभागीय अधिकारियों ने यह लिखा सोइल में सीलन की वजह से ब्रीच हुआ है । दूसरी बार टैक्निकल एक्सपर्ट्स उस रिपोर्ट का खंडन करते हैं । वे कहते हैं कि नीचे से सीपेज हो गया है तो आखिर में वास्तविक रूप से क्या माना जाय ? पहले आपके अधिकारियों द्वारा जांच हुई थी वह ठीक थी या बाद में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जांच का जो परिणाम था वह आपको पढ़ कर बता दिया है; सोइल की खराबी ही ज्यादा मुख्य कारण है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, नहर बनायी जाती है उस समय उसके आसपास में किस प्रकार की मिट्टी डाली जाय, उसको किस प्रकार की मिट्टी से निर्माण करवाया जाय, यह सब अधिकारी देखते हैं । वे इस बात को अच्छी तरह से जांच नहीं करते कि किस प्रकार की मिट्टी डालने से बांध टिका रहेगा या नहीं ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह बिल्कुल ठीक बात है कि जिस सोइल का कन्स्ट्रक्शन जिस पोर्शन में कर रहे हों वहां उसकी सूटेबिलिटी को ध्यान में रखकर ही उस सोइल को वहां काम में लाया जाता है । पर कहीं पर, एक नहर है, अमुक कैपेसिटी पर चलने वाली नहर पर जैसी सोइल अवेलेबल है, वहां उसको लगाना भी पसन्द करते हैं, बजाय इसके कि वहां कहीं दूर से सोइल लाकर डाली जाय, जो कम्पेरेटिवली लाभ कम करे और कॉस्ट ज्यादा बढ़ा दे, तो इस कॉस्ट को ध्यान में रख कर वहां की मिट्टी लगाने का रिस्क भी लेते हैं और यह रिस्क उस कॉस्ट के मुकाबले में कहीं कहीं लाभदायक भी होती है । तो यह ओन दी स्पॉट जो इन्जीनियर और टैक्निशियन काम करते हैं उनका डिस्क्रीशन है । उससे कभी लाभ भी होता है, कभी नुकसान की भी सम्भावना रहती है, क्योंकि यह वे रिस्क लेते हैं । तो इसमें एक-दो पर्सेन्ट गलत भी निकल जावे तो इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जाना चाहिये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह आपका फर्माना ठीक है कि एस्टीमेट करते हैं कैलकुलेशन करते हैं; खर्चे आदि को, डिस्टेन्स वगैरह को और कम खर्च करने के उद्देश्य से थोड़ा रिस्क भी ले लेते हैं । पर यह मुझे नहीं समझ में आता कि रिस्क लें तो थोड़ा बहुत लें; दो-दो, तीन-तीन लाख का रिस्क कैसे ले जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आपका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। पर मौके पर काम करने वाले आदमी पर भी भरोसा किया जाना चाहिये, इतना डिस्क्रीशन उस को दिया जाना चाहिये। उनका उद्देश्य इस रिस्क के पीछे मैलाफाइडी नहीं होता। तो हमें इस सीमा तक उसको डिस्क्रीशन एक्सर्साइज़ करने देना चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेलाफाइडी और बोनाफाइडी का प्रश्न नहीं है यहां व न मैंने किसी पर कोई मोटिव इम्प्यूट किया है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब हम खर्चा करते हैं, एक्सपर्ट अपोइन्ट करते हैं, हाई सैलेरी दे रहे हैं, आखिर यह सब किस लिए ? लापरवाही से काम कर जाते हैं, अच्छी तरह से सोइल को देखते नहीं। और रिस्क लेने का नाम उसको दे देते हैं। दो-तीन लाख रुपये की रिस्क की कोई आवश्यकता नहीं होती वहां, यह तो लापरवाही है कोरी। अगर मिट्टी जो ली जा रही है और वह ठीक नहीं है तो कॉस्ट को कम करने की रिस्क पर वे न चलें। इस प्रकार की आप इन्जीनियरों को हिदायत दे दें। यह रिस्क अच्छी नहीं है। आरम्भ में मैंने कहा था कोटा डैम के बारे में भी। मैं उनके ज्ञान को चैलेन्ज नहीं करता। पर कॉमन सैंस को भी एप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है।

प्रश्न संख्या ३३३

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३३४

श्री भीमसेन

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

तहसील सांचौर के नैयड़ क्षेत्र में सिंचाई

३३५. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) :- क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि चीतलवाना ग्राम तहसील सांचौर में सिंचाई विभाग द्वारा एक कच्चा बांध बांधने पर इस वर्ष कई गांवों में नदी का पानी फैल कर सांचौर का नैयड़ क्षेत्र इनन्डेट हुआ है ? अगर हां, तो ऐसे कितने ग्राम हैं जिनमें पानी फैला है और गेहूं की काश्त होगी ? कुल इनन्डेट क्षेत्र का क्षेत्रफल बताने की कृपा करें।

(२) क्या यह सच है कि सांचोर के नैयड़ क्षेत्र के कुछ गांवों में पहले नदी आने पर इनन्डेट होते थे जो इस साल नहीं हो पाये ? अगर हां, तो ऐसे कितने गांव हैं, कृपया गांवों की सूची एवं क्षेत्रफल सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। ऐसे क्षेत्रों के बारे में सरकार भविष्य में क्या योजना बनायेगी, जिससे जमीन रेली जाकर काश्त हो सके ?

Page No 15

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(३) क्या यह सच है कि पंचायत समिति सांचोर द्वारा तीन छोटे छोटे बान्ध चीतलवाना, होती गांव एवं ढूढवा में बांधे गये थे परन्तु पानी से टूट गये ? अगर हां, तो उनके टूटने के क्या कारण थे ? क्या साइट्स सिलेक्ट करने में कुछ त्रुटि रह गई थी या काम अधूरे रह गये थे ? क्या सरकार भविष्य में सांचौर के क्षेत्र में पूरी नदी सर्वे करके सारे बन्धे बनाने का काम अपने सिंचाई विभाग द्वारा कराना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो अपूर्ण कार्य कब तक पूरा करा दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या यह सच कि गत साल के सरकार के खर्च को देखते हुए पैदावार के हिसाब से लूनी इनन्डेशन स्कीम सबसे इकोनोमिक साबित होगी ? और हां, तो क्या सरकार सिंचाई विभाग की एक पर्मानेन्ड पोस्ट चीतलवाना में क्रीएट करने का शीघ्र निर्णय लेगी ?

(५) क्या यह सच है कि इस साल इनन्डेशन होने के बाद भी काफी पानी नदी में बह कर बेकार चला गया ? अगर हां, तो क्या इतना थोड़ा पानी होते हुए भी अगर सारी स्कीमें बन गई होतीं तो क्या सारा नैयड़ क्षेत्र इतने पानी से इनन्डेट हो जाता ? अगर हां, तो क्या सरकार अगली वर्षा तक दूसरे सारे बन्धे बनवाना उपयुक्त समझेगी ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, ६ ग्रामों की कुछ भूमि पानी से इनन्डेट हुई थी। क्षेत्रफल की सूचना का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है।

(२) जी हां, रतनपुरा आदि दो गांवों पर बुरा प्रभाव पड़ा बतलाते हैं। गांवों की सूची व क्षेत्रफल की सूचना का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है।

(३) छोटे छोटे बन्धों का जो पंचायत समिति द्वारा बनाये गये थे टूटने का सुनने में आया था। पूर्ण जानकारी पंचायत समिति से सम्बन्धित है। सरकार का ऐसा विचार है। सर्वे आदि का कार्यक्रम शीघ्र प्रारम्भ किया जावेगा एवं सर्वेक्षण के पश्चात् ही कहा जा सकेगा कि कितने बन्धे बन पावेंगे।

(४) लूनी इनन्डेशन स्कीम से लाभ के बारे में योजना के तख्मीने आदि बन जाने के पश्चात् ही कुछ कहा जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार स्टाफ लगाया जावेगा।

(५) इस प्रकार के आंकड़े विभाग के पास नहीं हैं। अगली वर्षा तक सारे बन्धों का बनाना सम्भव नहीं हो सकेगा। कुछ बन्धों की सर्वे हो जाने की आशा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सूची तो ली जा सकती थी। सूची प्राप्त करने की आपने कोशिश भी की या नहीं ? या की तो मिली नहीं, यह है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिनकी डिटेल जानना चाहते हैं उनकी गिरदावरी हुई नहीं है। गिरदावरी के एस्टीमेट तैयार हो जाने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के बाद ही राजस्व विभाग के पास भी पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी । इस बीच में जो अनुमान लगाये गये हैं उनके अनुसार कह सकते हैं कि ४०-४५ हजार बीघा में फसल हुई है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस हिसाब से दूसरे प्रश्न में जो कहा गया उसके बारे में राज्य सरकार क्या सोच रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में, डिटेल्ड सर्वे के बारे में इन्जीनियर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इफेक्ट को टाला जा सकता है । कच्चे डैम के बांधने की बात भी सोची जा रही है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : चीतलवाना, होती गांव एवं डूढवा पर बांध बनाये, काफी पानी भी आया; पर छोटी सी गलती से बांध टूट गये । गोमती की कांकड़ पर राज्य सरकार सर्वे करके बांध बनावे तो यह भी काम में आ सकता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पंचायत समिति के सदस्य आप भी हैं । आप भी सुझाव दे देते अगर गलती पर थे तो । अब आप जानकारी दे रहे हैं । दूसरी जगह बनवाने की टैक्निकल लोग उसकी भी जानकारी कर लेंगे । आप अपने सुझाव भेज दें ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : भेज चुका हूं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो जांच हो जावेगी ।

प्रश्न संख्या ३३६

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ३३७

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

साबी नदी पर बांध

३३८. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार की अलवर जिले में साबी नदी पर बांध बांधने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

(२) क्या यह सही है कि इस नदी पर बान्ध बांधने की योजना द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी थी ? यदि हां, तो उसको अमली रूप न देने का क्या कारण रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में इस नदी में बाढ़ के भारी प्रकोप के कारण केन्द्रीय जल एवं विद्युत बोर्ड ने इस योजना को प्राथमिकता दे देने पर बल दिया है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, इस योजना का सर्वेक्षण सम्पूर्ण कर लिया गया है तथा भारत सरकार की स्वीकृति हेतु पेश की जा चुकी है। अब कुछ तकनीकी छान-बीन के उत्तरों के लिए वापिस आई है उसे आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त वापिस भेजा जा रहा है।

(२) जी हां, इस योजना पर सर्वेक्षण किया जा रहा था और तख्मीना भी बनाया गया है। भारत सरकार व योजना आयोग की स्वीकृति न होने की वजह से इसको अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

(३) जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो अभी इसका प्रारूप बनाया गया है वह उस प्रारूप से बिल्कुल भिन्न है क्या जो पहले बनाया गया था ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : डिटेल में तो मैं नहीं कह सकता, पर भिन्न हो सकता है। पुराने समय में अलग फैक्टर्स रहे होंगे, आज स्वाभाविक है, भिन्न फैक्टर्स रहे होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले किस जगह पानी रोक कर बांधने की योजना थी और अब किस जगह ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने अर्ज किया न कि पहले जो फैक्टर्स थे उनमें नए फैक्टर्स भी जुड़ हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही इन्वेस्टीगेशन करने वाले विभाग के लोगों ने उस स्कीम को नया रूप दिया है। यह काफी बड़ी स्कीम हैं। मीडियम प्रोजेक्ट हैं। इसके पहले तो सरकार एग्री भी नहीं कर रही थी क्योंकि यह उचित रिटर्न नहीं दे सकती थी। पर यह बाढ़ का ही परिणाम था जिसके कारण यह बनी और पंचायत सरकार भारत सरकार और राजस्थान सरकार इन सबकी मिली-जुली बैठक में इसको माना गया है कि साबी पर बान्ध बनाया जावे। फ्लड कन्ट्रोल की दृष्टि से लिया जावे।

तो, यह सारा प्रारूप बनाकर सी. पी. डब्ल्यू. सी. के सामने दिया है और वहां से फिर एग्जामिन करके फिर प्लानिंग कमीशन में मामला जाकर चौथी योजना में इसको हाथ में लिया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पानी रोकने के लिए कौन सा स्थान तय किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो ऑफ हैण्ड नहीं कह सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है।

श्री नाथूराम मिर्धा : करीब ६८ लाख।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले भी ७५ लाख का था। फिर आप तो इसे बढ़ी हुई प्लान बता रहे हैं। पहली दूसरी योजना में ७५ लाख का था। अब इसको आप और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भी बढ़ा हुआ बताते हैं; तो क्या यह ६७ लाख ही है या अधिक है! अगर अधिक नहीं है तो फिर बढ़ी हुई प्लान कैसे हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये टैक्नीकल मामले हैं, कौनसी चीज में क्या परिवर्तन आते हैं, यह टैक्निकल पर्सन ही बता सकते हैं। ६७ लाख कह दीजिए, ७५ लाख कह दीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मन्त्री महोदय, इसे टैक्निकल न समझें। यह तो एक साधारण सी कॉमन सैंस की बात है कि ७५ लाख पहले थी। तो उसके बाद आज मंहगाई बढ़ी है। भाव हर चीज के बढ़े हैं। मजूरी मंहगी हुई है तो अगर यह बड़ी प्लान है पहले से तो हर हालत में इसकी लागत भी बढ़ी हुई होनी चाहिए। अब इस प्रारूप में कितना खर्च होगा, यह तो आपको ठीक ठीक बताना चाहिए। जनता आखिर यह जानना चाहती है कि वह किस जगह बनने वाली है, कितना उसमें व्यय होगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : अजमेरीपुरा गांव है उसके पास है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास सूचना आई कि उसका स्वरूप पहले से बहुत बड़ा है; रिवाइज्ड एस्टीमेट १७४ लाख के हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी टैक्निकल एक्सपर्ट से आपने अक्ल लड़ाई तो कोई बात नई निकली न।

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह चौहान।

मिडल इनकम ग्रुप हाउसिंग लोन देने के आधार

३३६. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या मंत्री, टाउन प्लानिंग विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि श्री जाकिर हुसेन ठेकेदार, उदयपुर वाले को स्वीकृत मिडिल इनकम ग्रुप लोन के अन्तर्गत दी हुई रकम का सही उपयोग नहीं किये जाने पर राज्य सरकार ने उसको रकम जमा कराने का नोटिस दिया और जमीन नीलाम करने का निर्णय लिया ?

(२) क्या यह सही है कि पुनः इसको हाउसिंग लोन दिया गया जब कि वेटिंग लिस्ट की श्रेणी में इनका नाम सम्मिलित नहीं था ?

(३) वर्ष १९६३ में मिडल इनकम ग्रुप में दिये गये लोन में से हाउसिंग एकाउन्ट्स क्लर्क तथा ए०डी०एम० को किस आधार पर लोन देने में प्राथमिकता दी गई है ?

उप-मंत्री, टाउन प्लानिंग (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) बकाया लोन की किश्त इनको दी गई, इनका नाम वेटिंग लिस्ट में क्रम संख्या १ पर अंकित था।

(श्री परसराम मदेरणा)

(३) हाउसिंग अकाउन्ट्स क्लर्क व ए०डी०एम० को लोन देने में प्राथमिकता नहीं दी गई है।

श्री जोरसिंह चौहान : आपने पहले का उत्तर 'जी हां' में दिया है; आपने कार्यवाही क्या की ?

श्री परसराम मदेरणा : जो रकम दी उन्होंने दो महीने के अन्दर अन्दर पहली किश्त देने की तारीख से उन्हें काम शुरू कर देना चाहिए था, वह काम दो महीने की अवधि में शुरू नहीं किया और उसके बाद में काम शुरू किया।

श्री जोरसिंह चौहान : क्या अब भी वह रकम उसी काम में लगा दी गई है, क्या सरकार ने इसकी जांच की है ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार ने जांच की है और जो किश्तें उनको दी गई हैं मकान बनाने के लिए वह उन्होंने उस मकान के कन्सट्रक्शन में लगा दी।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

गंज से कस्बा नदबई जाने वाली सड़क का सर्वे

३१३. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जो सड़क गंज से कस्बा नदबई को जाती है उसका सर्वे नगरपालिका द्वारा करवाया जा चुका है ?

(२) क्या यह सही है कि आवश्यक धनराशि की कमी के कारण यह सड़क नहीं बनाई गई है ?

(३) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के लिए कुछ प्रतिशत रुपया स्वायत्त शासन विभाग देता है ? अगर हां, तो कितना ?

श्री सांवलियाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको पूछना नहीं चाहता हूं क्योंकि प्रश्न इस विभाग से संबंध नहीं रखता। यह पी०डब्ल्यू०डी० से संबंध रखता है।

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्री से पूछना नहीं चाहते। क्या मंत्री महोदय जवाब देना चाहेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : हैं ही नहीं।

प्रश्न संख्या ३१४

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३१५

श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

Page No 20

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

जालोर वाटर वर्क्स की पानी की दरें

३१६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा २८५ के अन्तर्गत जालौर के जिलाधीश श्री मिश्रा द्वारा प्रेषित कोई रेफरेन्स राज्य सरकार को जालौर में पानी की दरें बढ़ाने के सम्बन्ध में मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को इस रेफरेन्स के बावजूद जालौर कस्बे में पानी की दरें दुगुनी कर दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि जालौर में जो वाटर वर्क्स हैं उसे नगरपालिका के अधिकार में से ले लेने की जिला अधिकारियों की सिफारिश सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

(४) क्या यह वाटर वर्क्स मुनाफे में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य की अन्य जिला केन्द्रों पर स्थित नगरपालिकाओं को भी वाटर वर्क्स हस्तान्तरित करने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) राज्य सरकार ने उसे खारिज कर दिया है ।

(२) राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुसार की गई है ।

(३) यह सही नहीं है ।

(४) यह वाटर वर्क्स मुनाफे में चल रहा है । अन्य जिला केन्द्रों पर स्थित वाटर वर्क्स नगरपालिकाओं को हस्तान्तरित करने का अब तक कोई इरादा नहीं है जब तक कि राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण ब्याज सहित वापिस न हो जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

मलेरिया विभाग के दफ्तर का स्थानान्तरण

३१८. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जालौर और सिरोही जिले के मलेरिया विभाग का मुख्य दफ्तर जालौर में था जिसे माउन्ट आबू पर बदल दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : जी हां । जालौर और सिरोही जिले के मलेरिया विभाग का मुख्यालय २०

Page No 21

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

मार्च, १९६२ तक जालौर में ही था। लेकिन प्रशासनिक एवं जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से इसे अब सिरोही स्थानान्तरित कर दिया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: किस कारण से?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : प्रशासनिक एवं जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पहले माउन्ट आबू था अब वापिस सिरोही आ गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो आबू जाने का क्या कारण था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने कहा है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जालौर से नज़दीक पड़ता था, वहां से क्यों हटाया गया ? सब सहूलियतें थीं वहां। जालौर में रखने से क्या तकलीफ थी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : गुजरात से जो मिला हुआ एरिया है, जहां जहां मलेरिया का प्रकोप है उसकी दृष्टि से अब सिरोही में रखा गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैदान से हटा कर आप पहाड़ पर रख दें और कर्मचारियों को असुविधायें हों, ऐसी जगह क्यों रखा गया था।

श्री दलपतसिंह (आबू) : जालोर और सिरोही और आबू इन तीनों के सिरोही बीच में पड़ता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वहां आबू पर केवल व्यक्तिगत कारणों से किया गया है जिसके कारण वहां कर्मचारियों को काफी असुविधायें होती थीं। एक डाक्टर की मिसेज़ वहां पर काम कर रही थीं और वे दोनों वहां पर रहना चाहते थे इसलिए वहां रखा गया था।

श्री दलपतसिंह : किसी की मिसेज़ नहीं रहतीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपकी मिसेज़ तो रहती हैं शायद वहां।

श्री दलपतसिंह : मैंने आपकी बात सुनी नहीं, नहीं तो मैं आपको अच्छा जवाब देता।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

मकान बनाने के लिए ऋण

३१९. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या मुख्य मंत्री यह उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि वर्तमान कलेक्टर कोटा, श्री राजकुमार, आई०ए०एस० ने मकान बनवाने के लिए जयपुर में ऋण

Page No 22

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लिया है ? अगर हां, तो कब कब, कितना कितना ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त अधिकारी ने मकान कृषि भूमि पर बनाया है जब कि भूमि भी उन स्वयं के नाम नहीं है ?

(३) उक्त मकान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र किसके द्वारा कब प्रस्तुत हुआ ?

(४) क्या मकान पर लिया गया ऋण चुका दिया गया है ? अगर नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

(५) क्या यह सत्य है कि उक्त अधिकारी ने त्याग-पत्र प्रस्तुत कर दिया है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (१) जी हां, श्री राजकुमार ने माह फरवरी, १९६३ में ३५,००० रु० मकान बम्बई में खरीदने के लिए ऋण लिया था बाद में तारीख १४-११-६३ को उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया कि वे उस रकम को यहीं पर मकान बनाने में लगाना चाहते हैं।

(२) मकान कृषि भूमि पर बनाया गया है जो अभी अधूरा है किन्तु अब भूमि स्वयं श्री राजकुमार के नाम है।

(३) ऐसे प्रमाण-पत्र का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(४) ऋण नहीं चुकाया गया है किन्तु सरकार इस ऋण को श्री राजकुमार से वसूली करने का फैसला शीघ्र लेगी। यह मामला विचाराधीन है ?

(५) त्याग-पत्र दिया था, किन्तु श्री राजकुमार ने उसे वापिस लेने का आवेदन पत्र दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सच है कि मकान बनाने के लिए ऋण देने से पूर्व यह तसल्ली कर ली जाती है कि जिसके लिए ऋण मांगा जा रहा है उसके लिए जमीन खरीद ली गई है और जमीन का पट्टा देखा जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्होंने बने हुए मकान को खरीदने के लिये ऋण लिया था और बम्बई में खरीदने के लिए लिया था इसलिए उस आधार पर यह ऋण शुरू में स्वीकृत हुआ था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इसके बाद जब सरकार को यह मालूम हुआ कि जयपुर में ही वह अपना मकान बनाना चाहते हैं तो उस समय सरकार ने उचित नहीं समझा कि जिस मकान को जयपुर में बनाना चाहते हैं उसके लिए उनके पास प्लाट हैं या नहीं यहां ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस वक्त इनके १०,००० रुपये की एक किश्त रिटेन करने के लिए कहा गया जो कदाचित इसी प्रयोजन के लिए थी कि वह जमीन और मकान बनाने का कार्य शुरू करें।

Page No 23

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि बम्बई में मकान खरीदने के लिए ऋण दिया गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या नियमों के अनुसार बाहर मकान खरीदने के लिए प्रावधान है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आल इन्डिया सर्विसेज़ के एम्पलॉई हैं । आई० ए० एस० हैं और उनके लिए ऐसा प्रावधान है कि वह या तो जहां पर सर्विस में इस समय हैं वहां पर मकान बनायें या उस जगह बनायें जहां का वह रेज़ीडेन्ट हो या उस जगह जहां कि रिटायर होने के बाद बसना चाहते हैं । इस तरह से उसको ३ ऑप्शन्स हैं । तो इन सब तीनों में से एक ऑप्शन बम्बई में मकान बना हुआ खरीदने के लिए लोन का ऑप्शन दिया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि इन्होंने एग्रीकल्चर लैण्ड के ऊपर यह मकान बनाया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां, यह बात सच है कि इन्होंने एग्रीकल्चर लैण्ड पर बनाना शुरु किया । ज्यों ही सरकार के नोटिस में आया कलेक्टर ने इसके विपरीत दफा ९१ की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी और इन्जेक्शन भी शुरू कर दिया कि जिनसे इनके मकान का काम अधूरा पड़ा हुआ है और रोक दिया गया है सरकार के द्वारा ।

श्री भैरोंसिंह : बम्बई में मकान के लिए जो लोन लिया था उसका उपयोग हुआ या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वही लोन यह है । बाद में उन्होंने यह जाहिर किया कि बम्बई में जिस डील को यह करने वाले थे वह डील फाइनेलाइज़ नहीं हो सकी इसलिए इन्होंने इरादा बदलकर यहीं मकान बनाने की बात सोची ।

श्री भैरोंसिंह : क्या डील फाइनेलाइज़ होने से पहले रूल्स के अनुसार लोन स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बना हुआ मकान खरीदने के लिए और उसके लिए उस आदमी ने लिखा कि इतने हजार में खरीद ली है इसलिए रुपया दिया जाये, ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बना हुआ मकान खरीदने के लिए उनको स्वीकृति दी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या स्टे ऑर्डर के बावजूद भी उन्होंने एग्रीकल्चर लैण्ड के ऊपर मकान बना लिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार नहीं बना, अधूरा है ।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने अपने त्यागपत्र में क्या कारण दिखाये थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह :

क्रय विक्रय संघ द्वारा आयात किए गए गुड़ के वितरण एवं दर सम्बन्धी शर्तें

३२०. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राज्य सरकार तथा राजस्थान क्रय विक्रय संघ के बीच राज्य में गुड़ के आयात के लिये कोई लिखित समझौता हुआ था ? यदि हां, तो कब और इस समझौते पर किस किस के हस्ताक्षर हैं ? समझौते की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। समझौता नहीं हुआ, तो क्यों ?

(२) समझौते के अभाव में क्रय विक्रय संघ पर आरम्भ में गुड़ के आयात, वितरण एवं दर (भाव) के संबंध में क्या-क्या शर्तें लागू की गई थीं और उसमें इसके पश्चात् कब कब और क्या संशोधन किया गया और क्यों ? कृपया इस संबंधी समस्त आदेशों की एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) राजस्थान सरकार ने राजस्थान क्रय विक्रय संघ को गुड़ के आयात करने हेतु दिनांक २०-११-६३ को अधिकृत किया था जिसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) राजस्थान सरकार एवं संघ के बीच गुड़ के आयात, वितरण एवं दर के संबंध में जो शर्तें हुईं उनकी प्रतिलिपियां सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई हैं।

(सूचियें विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार और क्रय-विक्रय संघ के बीच कोई एग्रीमेंट भी हुआ था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार का एग्रीमेंट करने का कोई विचार था ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां। विचार था और विचार दोनों की सलाह से मीटिंग होकर एक ड्राफ्ट भी हो गया था और वह उनके पास दस्तखत करने के लिये भेजा गया था।

श्री भैरोंसिंह : उस वक्त दस्तख्त हुए कि नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दस्तख्त होकर आये नहीं।

श्री भैरोंसिंह : काम खत्म हो गया और एग्रीमेंट पर दस्तखत अब होंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बातचीत से तय हो गया कि इस तरह से काम देंगे और उनके

(श्री नाथूराम मिर्धा)

को इस शर्त पर काम करना पड़ेगा, सारी बातें एग्रीमेंट की दोनों से सलाह लेकर लॉ डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट बाद में किया और फाइनल होने के बाद में उनके पास गया।

श्री भैरोंसिंह : यह कब फाइनल हुआ था आपका ड्राफ्ट ?

श्री नाथूराम मिर्धा : काम सौंपा गया था उसके पहले सारी बातचीत तय हो गई थी और काम सौंपने के बाद एक महीने के बाद लॉ डिपार्टमेंट ने फाइनल करके भेजा।

श्री भैरोंसिंह : लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा एग्रीमेंट फाइनल हो गया था तो उनके हस्ताक्षर अब तक क्यों नहीं हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे खयाल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी और दस्तखत करने के लिए भेजा था वह आ जायेगा दस्तखत होकर।

प्रश्न संख्या ३२१

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३२२

श्री सम्पितिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३२७।

श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३२८।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३३१।

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

सिंचाई योजनाएं

३३३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर) : [श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) के द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान राज्य में कौन सी ऐसी बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं जिनसे निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि हो चुकी है ?

(२) इन योजनाओं में से कौनसी ऐसी हैं जो अभी तक भी निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रही हैं और उसका क्या कारण है ?

(३) इन योजनाओं में कुल कितनी धनराशि लग चुकी है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) भाखरा एवं चम्बल के प्रथम चरण की योजनाओं से निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि हुई है।

(२) प्रश्न नहीं उठता है ।

(३) भाखरा में २०३६.३२ लाख राजस्थान के कार्यों पर । चम्बल प्रथम चरण पर १६०७.५६ लाख राजस्थान के कार्यों पर ।

प्रश्न संख्या ३३४ ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३३६ ।

श्री मोहनराज ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३३७ ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सिकराय में पशु-चिकित्सालय का अभाव

३१४. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय—पु०) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिकराय में पशु चिकित्सालय न होने से वहां के पशु-मालिकों को अपने पशु लेकर दौसा या महुआ जाना पड़ता है । जिससे उक्त क्षेत्र के किसानों को काफी कठिनाई उठानी पड़ती है ?

(२) क्या सरकार अब पंचायत समिति सिकराय में एक पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

१. जी नहीं । सिकराय में पशु चिकित्सालय है, अतः कठिनाई का प्रश्न ही नहीं उठता ।

२. प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम बेड़ा में अस्पताल भवन का निर्माण

३१५. श्री **मोहनराज** (बाली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बाली पंचायत समिति का प्राइमरी हैल्थ सेंटर बेड़ा नामक ग्राम में स्थित है और वहां स्थानीय जनता ने सारे भवन की इमारत बनवाई है जिसका उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक १४-७-५६ को किया था ?

Page No 27

(श्री मोहनराज)

(२) क्या यह सही है कि तत्पश्चात सन् १९५९ में प्राइमरी हैल्थ सेंटर का भवन बनाने हेतु ६० हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी और संचालक, चिकित्सा विभाग ने जरिये पत्र सं० ७६३ ता० २४-८-५९ को स्वीकृति की सूचना देते हुए रु० ४०,००० विभाग (सार्वजनिक निर्माण) को इसके निर्माणार्थ दिये जाने की सूचना भी जारी की गई थी ?

(३) क्या यह सही है कि इस सूचना प्राप्ति के तुरन्त बाद ही संचालक, चिकित्सा विभाग को पत्र द्वारा एवं तत्पश्चात् पंचायत समिति, बाली के प्रस्ताव द्वारा सूचित किया गया कि इस समिति में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भवन व स्टाफ क्वार्टर्स आदि सब तैयार हैं, कोई खर्चा न किया जाय ?

(४) क्या यह भी सही है कि बावजूद इन सब के भी ग्राम बेड़ा में प्राइमरी हैल्थ सेंटर के भवन के बिल्कुल निकट ही रु० ४०,००० की लागत का नया अस्पताल भवन सरकार ने बनवा दिया जो कि आज बिल्कुल बेकार व खाली पड़ा है ?

(५) क्या सरकार ने इस बात की जांच करवाई है कि किसकी गल्ती से वह व्यर्थ खर्च हुआ ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

भूमि-अवाप्ति की कार्यवाही

३२१. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी नगरपालिका के द्वारा खसरा नं० ८१९ ८२०, ८२१, ८२२, ८२३।१, ८१८।१, जो करीब १२-१३ बीघा है और ए० सी० सी० कम्पनी के खाते में दर्ज है, एक्वायर करने हेतु प्रस्ताव ३४ दिनांक २८-५-५७ को पास किया गया और कलेक्टर बूंदी को संबंधित अधिकारियों को भेज कर भूमि-अवाप्ति करने की कार्यवाही करने को लिखा था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भूमि लाखेरी नगर के बीच में है और पड़त रहती है और किसी भी कार्य में नहीं ली जाती है ?

(३) क्या यह सही है कि नगरपालिका के पास अन्य भूमि नहीं होने से वह उक्त भूमि में बालबाड़ी, पार्क व बच्चों के खेल-कूद के मैदान के लिए अति आवश्यक समझती है और उसे प्राप्त करना चाहती है ?

(४) क्या यह सही है कि नगरपालिका ने करीब २१ बार प्रार्थना-पत्र देकर भूमि को अवाप्त करने हेतु लिखा है ? यदि हां, तो सन् ५७ से अब तक इस अवाप्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) नगरपालिका की आबादी से दूर है। कुछ जगह कच्चे बाड़े बन चुके हैं। कुछ जमीन खाली पड़ी है और कुछ में ए० सी० सी० की रेल्वे लाइन निकली हुई है।

(३) यह सही नहीं है। नगरपालिका

(स्वायत्त शासन मंत्री)

की सीमा में पूर्व ही बच्चों के खेल-कूद के दो स्थान मौजूद हैं ।

(४) यह सही है । अवाप्ति संबंधी कार्यवाही जिलाधीश व पालिका के बीच चलती रही । अब पालिका को इस भूमि की आवश्यकता नहीं है ।

नारायण सागर बंध

३२३. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नारायण सागर बांध (विजय नगर) कब बना ? इस पर कितनी लागत लगी ? इसका कार्य पूरा होने के बाद सिंचाई कब शुरू हुई और कितने एकड़ की सिंचाई हुई ? इस बांध से अनुमानतः कितने एकड़ सिंचाई होनी थी ?

(२) क्या यह सच है कि यह बांध फूट गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों फूटा ? क्या यह ठीक करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सच है कि वहां की मिट्टी बड़ी खराब है और जो मिट्टी बांध पर डाली गई है वह ठीक नहीं है ?

(४) क्या यह सच है कि आज तक उस मिट्टी पर कोई वृक्ष पैदा नहीं हुआ, न घास ही पैदा हुई है ?

(५) क्या उस बांध को बनाने के पहले यहां की मिट्टी की जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(६) क्या सरकार अब भी उस बांध की मिट्टी की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) बांध का कार्य अभी पूर्ण होना बाकी है । अब तक इस योजना पर ४०,८६,-५५५ रू० ५२ नये पैसे व्यय हुए, इस प्रोजेक्ट से सन् ६२–६३ में सिंचाई शुरू हुई और प्रति वर्ष करीब ३०० एकड़ भूमि सिंचित हुई है । बांध के पूर्ण विकसित होने पर इससे ५४०० एकड़ क्षेत्र सिंचित होगा ।

(२) जी हां, जुलाई ६२ में । मरम्मत का काम कुछ का पूरा हो गया है और शेष अब पूरा किया जा रहा है ।

(३) हां, उस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर मिट्टी खराब है । बांध पर डाली गई मिट्टी ठीक है ।

(४) जी हां, जहां मिट्टी ज्यादा खराब है ।

(५) जी हां, मिट्टी की जांच की प्रति-लिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No 29

ग्राम बरखेड़ा, तहसील सांगोद का बांध

३२७. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बरखेड़ा तहसील सांगोद में घोड़ा-दह-खाल पर बांधा गया सिंचाई बांध इतना ऊँचा बंध गया है कि उसके कारण बरसात का पानी किनारों की सीमा में नहीं रह कर खेतों में फैल जाता है, जिससे इस गांव में कटाव बढ़ गया है ?

(२) ग्राम बरखेड़ा में सिंचाई के साधन उपलब्ध रखते हुए क्या सरकार बंधे की ऊँचाई कम करने का विचार करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां, ऐसा पता चला है। किन्तु, इसका सम्बन्ध राजस्व विभाग से है क्योंकि कार्य उसी विभाग से करवाया था।

(२) इसकी कार्यवाही पंचायत समिति द्वारा चालू कराने हेतु लिखा गया है।

तहसील देवगढ़ में खांडसारी की जगह गुड़िया शक्कर का वितरण

३२८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ तहसील में दिवाली के त्यौहार पर वितरित करने के लिये जो अतिरिक्त शक्कर भेजी गई वह खांडसारी के नाम से दी गई ?

(२) क्या यह भी सही है कि वास्तव में वह खांडसारी न होकर गुड़िया शक्कर थी और इतनी घटिया किस्म की होने पर भी बढ़िया शक्कर के बराबर के भाव रु० १.३४ प्रति किलो के हिसाब से दी गई ? क्या यह सही है कि वास्तव में उसका भाव मुश्किल से ६० पैसे प्रति किलो का है ?

(३) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच की कोई है ?

उत्तर

(१) देवगढ़ तहसील में दीपावली के त्यौहार पर एक्स्ट्रा वितरण करने के लिए खंडसारी दी गई थी।

(२) जो खंडसारी केन्द्रीय सरकार द्वारा एलॉट की गई वही उत्तर प्रदेश से मंगाई जाकर मूल्यांकन कर वितरित की जाती है।

(३) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत पेश नहीं हुई है।

कोटा डिविजन में डकैतियां

३२९. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 30

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(१) कोटा डिविज़न में गत ३ वर्षो में कुल कितने डाके कहां, किस किस गांव में डाले गये हैं और कुल कितनी सम्पत्ति लूटी गई है तथा कितने व्यक्तियों का अपहरण डाकुओं द्वारा किया गया है ?

(२) गत नवम्बर, ६३ में सीसवाली सायथल डाके के बाद किन किन गांवों में कौन से गिरोह के डकैतों ने डाके डाले एवं कितने व्यक्ति की हत्या की गई है ?

उत्तर

(१) कोटा डिविज़न में सन् १९६२, १९६३ तथा १९६४ में कुल १८ डकैतियां हुईं जिनमें, रु० ६५,४२२— पैसे के कुल मूल्य की सम्पत्ति लूटी गई इनमें कुल आठ व्यक्ति डाकुओं द्वारा भगाये गये जो सभी वापिस आ गये हैं वे १८ डकैतियां निम्न लिखित स्थान पर हुई—

जिला बूंदी	१: ग्राम नमाना ।
जिला झालावाड़	१: मोहम्मदपुरा ।
	२: गंगधार रोड ।
जिला कोटा:	१: बराना
	२: खेड़ली मेडाला
	४: ज़ाखनी ।
	४: सदोकडा (शोकन्दा)
	५: खटका
	६: चोराखेड़ी ।
	७: ग्राम लहरूनी ।
	८: ग्राम बाढ़ोली ।
	९: ग्राम सीसवाली
	१०: " रायथल ।
	११: " कीरपुरिया ।
	१२: " लक्ष्मीपुरिया ।
	१३: " सहरोल ।
	१४: " जंगेल जलवारा ।
	१५: " सनवाड़ा ।

(२) सीसवाली और रायथल ग्राम की डकैती के पश्चात् कुल ७ डाके पड़े जिनमें न तो कोई ग्रामीण मारा गया, न कोई भगाया गया। ये डाके निम्न स्थानों पर उनके नाम के आगे बताये हुये दल द्वारा डाले गये—

जिला झालावाड़—१)	गंगाधार रोड ।	अज्ञात व्यक्तियों द्वारा
जिला बूंदी—१)	नमाना	स्थानीय गिरोही द्वारा
जिला कोटा—१)	कीरपुरिया ।	कन्जरों द्वारा
२)	लक्ष्मीपुरा	मध्य प्रदेश के बनजारों द्वारा जो बाद में नामजद हुये ।
३)	सहरोल	माना शिकारी दल के द्वारा
४)	जंगल लवाड़ा	एम्बेसी के सिपाहियों द्वारा
५)	खनवाड़ा ।	माना शिकारी दल के द्वारा

गंगाशहर व भीनासर जल-प्रदाय योजना

३३४. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

(श्री भीमसेन)

क्या जन स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गंगाशहर व भीनासर नगरपालिका सम्मिलित जल प्रदाय योजना के एस्टीमेट्स तैयार किये जाकर मुख्य अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या २४१६८ दिनांक २४-७-६४ द्वारा राज्य सरकार को भेजे गये हैं ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

इस योजना की स्वीकृति भारत सरकार से आ चुकी है और इसको शासकीय स्वीकृति देदी गई है (इस विभाग की पत्र संख्या नं. एफ ४ (७६) एम पी एच। ६४ दिनांक ८-३-६५ जारी कर दी है)

गोलेराव तालाब से सिंचाई

३३६. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम नाड़ोल पंचायत समिति देसूरी के निकट स्थित गोलेराव नामक तालाब को सिंचाई के लिए उपयुक्त समझकर उसकी मरम्मत करने व खुदाई करने के लिए कुछ समय पूर्व समाज कल्याण विभाग की सिंचाई शाखा ने सर्वे करवाया था ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यह तालाब उस क्षेत्र के लिए सिंचाई हेतु और कुओं में पानी का स्तर ऊपर लाने में अत्यन्त उपयोगी होना पाया गया है ?

(३) क्या सरकार उक्त बान्ध की पूरी मरम्मत करवाकर उस कम पानी वाले क्षेत्र में सिंचाई की कमी पूरी करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावनाएं हैं ?

उत्तर

सिकराय डिस्पसरी की इमारत

३३७. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय-सु.): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सिकराय में जो डिस्पेन्सरी चल रही है वह एक किराये के मकान में चल रही है जो पूर्णतया उपयुक्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां कोई नई इमारत बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी हां; किराये के भवन में चल रही है जो कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त ही है। फिलहाल धनाभाव के अभाव में डिस्पेन्सरी के लिए नई इमारत बनवाना संभव नहीं है।

(११.५५ म. पू.)

अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी संघ के महामंत्री श्री मानसिंह द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर नॉनगज़ेटेड पुलिस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मानसिंह भूख हड़ताल पर हैं और उनकी मांगों के सम्बन्ध में गृहमंत्री को एक लम्बे अर्से से एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया हुआ है, और उसके बावजूद लम्बे अर्से के अन्दर उसका जवाब नहीं मिलने की वजह से उन्होंने आज से तीन दिन पहले भूख हड़ताल प्रारम्भ की है। इस सिलसिले में अपनी विधान सभा में कई दफा उनके संगठन की मान्यता के सम्बन्ध में, उनकी मांगों के सम्बन्ध में, इस प्रकार के प्रश्न आये और मंत्री महोदय, ने भी उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया, परन्तु उस सिलसिले में अभी तक कुछ नहीं हुआ।

दूसरा यह और हो रहा है कि एक संगठन जिसके अन्दर कुछ लोग काम करते हैं उसमें से कई लोगों को तो जो कि इसके अधिकारी हैं उनको या तो ट्रान्सफर कर दिया गया है और कई लोगों को सर्विस से हटा दिया गया है। जहां तक सर्विस से हटाने का सवाल है या ट्रान्सफर का सवाल है साधारण कर्मचारियों को जो कि थोड़ा-बहुत संगठन में काम करते हैं और संगठन के किसी पद, अध्यक्ष, मंत्री या और कोई पदाधिकारी होते हैं उनका दूसरे स्थान पर ट्रान्सफर नहीं किया जाता है, परन्तु उनके संगठन में जो भी कॉन्स्टेबल्स या दूसरे छोटे-मोटे व्यक्ति उसमें अगुआ होकर काम करते हैं तो इसकी वजह से उनका ट्रान्सफर कर दिया गया है। ऐसे ट्रान्सफर्स जो हुए हैं मैं आपके सामने बताऊं कि जो भी कर्मचारी; जैसे महेन्द्रकुमार...

श्री अध्यक्ष : एक आम बहस में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : सारे पदाधिकारियों के ट्रान्सफर हो रहे हैं और उनका विक्टीमाइज़ेशन हो रहा है। उनके खाने का ख्याल नहीं होता है, उनकी मंहगाई का ख्याल नहीं होता है, दूसरी बातों का ख्याल नहीं होता है। यह एक प्रश्न बुनियादी है, सरकार को अपनी तरफ से इस पर कहना चाहिए। यह अधिवेशन में ये मांगें आती हैं क्योंकि सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं होने की वजह से, बार बार उनकी बातों को समाप्त करने की वजह से यह परिस्थिति पैदा होती है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये मैं माननीय गृह मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस सिलसिले में जो भी सरकार की नीति हो कि वाकई वे मान्यता देना चाहते हैं और किस तरह से देना चाहते हैं उस सिलसिले में जो भी हो वह बतायें। वे लोग भूख हड़ताल पर जाने का फैसला कर चुके हैं। उनको बकाया देना है पहले का, ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हैं जिनको पैसा नहीं दिया, उनको झगड़े में रखा और इस तरीके से उनको हैरान कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आज इस मंहगाई के युग में बड़ा भारी अन्याय है। आखिर वे सरकारी कर्मचारी हैं

Page No 33

(श्री मुरलीधर व्यास)

और ऐसी जगह पर काम करते हैं कि हर प्रकार से बड़ी से बड़ी सेवा करनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि गृहमंत्री इस सिलसिले में जो कुछ भी उनकी डिमाण्ड्स हैं, जो भी स्थिति है उसके बारे में सदन में अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करें ताकि सदन के सब सदस्यों को सरकार की नीति के सम्बन्ध में जान सकें और उनकी बात को भी जान सकें और अपनी बात को भी रख सकें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इसी भूख हड़ताल के सम्बन्ध में आज एक स्थगन–प्रस्ताव की सूचना आपको भेजी थी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले ३ दिन से सैनिक श्री मानसिंह जो कि नॉन-गजेटेड पुलिस कर्मचारियों के महामन्त्री हैं वे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे भूख-हड़ताल पर अचानक ही नहीं बैठ गये। उस भूख-हड़ताल पर बैठने से पहले उन्होंने अपने पुत्रों द्वारा सरकार को नोटिस देकर, अधिकारियों को बार बार लिखकर अपनी मांगें पेश की हैं और जब सरकार की ओर से कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला तब मजबूर होकर पिछले तीन दिन से भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मांगें भी कोई इस प्रकार की नहीं हैं कि जो अजीब हों। इसी सदन में पिछले वर्ष इसी बजट अधिवेशन के अवसर पर उन्होंने अपने संगठन को मान्यता प्राप्त कराने के लिए मांग की थी। उस समय भी इसी सदन के समक्ष भूख हड़ताल की गई थी और इसी सदन में उप-मंत्री, गृह विभाग ने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी ही रिकॉग्नाइज़ेशन इस संगठन को दे देंगे, लेकिन एक वर्ष बीत गया और बार बार उनके द्वारा लिखा जा चुका और अभी तक कोई मान्यता उनके संगठन को नहीं दी गई, बल्कि सरकार की ओर से उनके संगठन को तोड़ने–फोड़ने और उसको इस तरीके से डिस्टर्ब करने की बराबर कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जो पुलिस कर्मचारियों की मांगें हैं, जो उन्होंने अपने मांग-पत्र में रखी हैं वे ११ मांगें हैं। उन मांगों में एक मांग यह भी है कि जो सन् ४८ से लेकर ५३ तक ए० एस० आई० पुलिस कर्मचारी थे और जिनका पद सरकार ने खुद ने मुकर्रर किया था, जिनका ग्रेड सरकार ने मुकर्रर किया था ५५-२-६५ का। उन लोगों को बूंदी के जिले में ऐसे ए० एस० आई० पुलिस कर्मचारियों का पेमेन्ट उसका हो गया, झालावाड़ में हो गया, कोटा में बिल बने हुए हैं, हैं, लेकिन और राजस्थान में दसों जिले ऐसे हैं जिनका ऐसे कर्मचारियों का मामला अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है और उन लोगों को पेमेन्ट होने की बात नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, इस जमाने में जब कि इतनी मंहगाई है और लोगों को जो मौजूदा तनख्वाह मिल रही है उससे उनका पेट नहीं भर पाता है और लोग अपना मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिए आन्दोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वहां सरकार का इतना उदासीनता पूर्वक रवैया है कि १२–१२ और १५-१५ वर्ष जब से आजादी शुरू हुई है तब से लोगों का वेतन और भत्ता बकाया पड़ा रहे, उनके बारे में सरकार कुछ भी न करे, खुद ये श्री मानसिंहजी जो कि महामंत्री हैं वे असर रखते हैं, उनके खुद का अपना उसी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जमाने का वेतन ५३ से पहले का बकाया है, उन्होंने सैंकड़ों चिट्ठियां लिखी हैं और बार बार लिखकर पुलिस को कहा है, उनके लिखने के बावजूद कोई जबाब पुलिस विभाग की ओर से नहीं दिया जा रहा है। आखिर, मजबूर होकर भूख हड़ताल पर उनको बैठना पड़ा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार स्पष्ट तौर से बताये कि क्या दिक्कत है इस बात की घोषणा करने में उनको ? माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर मौजूद हैं।

(१२.०० मध्यान्ह)

जब हाई कोर्ट से मुकदमा लड़ा, उसका फैसला हुआ कि उनको संगठन बनाने का अधिकार है; फिर आपको उनसे बातचीत करने में क्या आपत्ति है और उनके संगठन को रिकॉग्नाइज करने में क्या आपत्ति है ? उनको पेमेन्ट जल्दी से जल्दी क्यों नहीं किये जाते ? यह सारे जिलों में फैल रहा है और १४ तारीख को सारे पुलिस कर्मचारियों ने अनशन करने का तय किया है। आप इस बारे में कोई कदम नहीं उठायेंगे तो अशान्ति फैलेगी और राज्य व्यवस्था बिगड़ेगी, इसलिये इस बारे में सरकार फौरन कदम उठावे। आज ही आप घोषणा करें कि हम पेमेन्ट करेंगे, इसके लिये निश्चित अवधि मुकर्रर करें और कमेटी मुकर्रर करें और छानबीन करके एक्सपीडीशियस तरीके से यह कार्य कराया जाय। दूसरी बात सर्विस कंडीशन के बारे में है, इसका भी जल्दी फैसला होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं एक मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि इस पर कोई बहस हो। आप बहुत संक्षेप में कहें।

श्री भैरोंसिंह : बहुत संक्षेप में। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पहले भी कई बार इस विषय को लेकर चर्चा हुई और पिछली मर्तबा सरकार ने एक आश्वासन दिया था उनके संगठन को मान्यता देने के प्रश्न में। मैं यह मानकर चलता हूं कि पुलिस विभाग एक सुरक्षा का विभाग है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहां तक मेरा और मेरे दल का सवाल है, मैं इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में किसी किस्म का ट्रेड यूनियेनिज़्म पैदा हो, इसको मैं पसन्द नहीं करता। लेकिन साथ साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि वे अपने ग्रीवान्सेज़ सरकार के सामने सामूहिक रूप से रख सकें उसके लिये इस प्रकार के एसोसियेशन के रूप में उनको मान्यता दी जाय और उसके पश्चात् राजस्थान नॉन गजेटेड कर्मचारी संघ की तरफ से उनके लिये जितना प्रतिनिधित्व किया जाय उस पर सरकार तत्काल कार्यवाही करे। आज जो स्थिति बन रही है उसका मुख्य कारण यह है कि पुलिस के सिपाही वर्ग अपने आपको इस स्तर पर मानते हैं कि एस. पी. और सिपाही में मानव और ईश्वर के बीच में जितना फर्क है उसी प्रकार का ट्रीटमेन्ट चल रहा है। इनके ग्रिविन्सेज़ सुनने के लिये सरकार ने कमेटीज़ की व्यवस्था की थी;

(श्री भैरोंसिंह)

एसोसियेशन और सेमिनार इस प्रकार की व्यवस्था थी लेकिन मैं समझता हूं किसी भी जिले में पुलिस के सिपाहियों के ग्रीवान्सेज़ सुनने के लिये जो सरकार ने व्यवस्था की थी उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि छोटे छोटे लोगों के स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में करने में संकोच नहीं होता जिसकी कि मुमानियत है। सिपाहियों को टी. ए., डी. ए. देने की व्यवस्था बराबर नहीं हो रही है, उनके वेतन का फिक्सेशन हो जाय, इसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। दूसरे कर्मचारियों को जो सुविधा दी है वह पुलिस कर्मचारियों को भी मिल जाय, इसके लिये भी व्यवस्था नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों में असंतोष है। उनको जो कर्त्तव्य निभाना है उसको निभाने में कई बार उनको संकोच होता है। इस परिणाम का असर अन्ततोगत्वा जनता पर पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यूनियन या एसोसियेशन जिस प्रकार भी चाहे उसके लिये शीघ्र निर्णय लिया जाय ताकि ट्रेड यूनियनिज्म पनप न पावे और राइट स्टेप लें, इसकी व्यवस्था करें। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के समस्त जिला अधिकारियों से जानकारी लें कि कितने स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में हुए हैं, कितना एरियर उनका ड्यू है और कितनी सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिये वे नहीं प्राप्त हैं। वे अपना स्टेटमेन्ट सही रूप में देने की कोशिश करें तो समस्या का समाधान हो सकता है लेकिन सरकार की मंशा समाधान करने की नहीं है तो पुलिस में असंतोष फैलेगा जो हम सब के लिए बुरा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास और श्री रामानन्द अग्रवाल ने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है इस हड़ताल के संबंध में जिसका उल्लेख अभी किया गया। इन दोनों को स्वीकार नहीं किया गया है और अभी माननीय सदस्यों ने जो इस संबंध में समस्याएं उठाई हैं, विचार रखे हैं, संभव है मुख्य मंत्रीजी अपने भाषण में इनके बारे में कल स्पष्टीकरण कर सकें।

श्री रामानंद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न सरकारी कर्मचारियों को मीटिंग में न जाने के संबंध में सरकार ने एक सर्क्यूलर इशू किया था उस बारे में मैंने रखा था। विधि मंत्रीजी को इसका स्पष्टीकरण करना था...........

श्री अध्यक्ष : इस पर स्पष्टीकरण हो चुका है। बहस के दौरान उत्तर दिया जा चुका था।

(१२.०५ म० प०)

आय-व्ययक, १९६५–६६ पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री मथुरेशबिहारी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष के लिये माननीय वित्त मंत्रीजी ने सदन

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

के अन्दर ४५ मिनट में सुन्दर भाषा में भूमिका बनाते हुए जब बजट प्रस्तुत किया और आखिर में हमको अवगत कराया कि इस आगामी वर्षो के अन्दर बजाय राहत के, वजाय टैक्सों में कमी होने के हमारे राजस्थान की जनता पर कुछ टैक्सों का भार लादा जायगा और वह इसलिये कि ६ करोड़ रू० का घाटा है उसकी पूर्ति की जाय और उसकी पूर्ति के लिये कुछ बजट योजना में, सरकारी पूँजी खाते से और १ करोड़ ५५ लाख रुपयों के टैक्सेज बढ़ा कर यह घाटा पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। मैंने इस बजट को गौर से देखा और गये तीन दिनों से इस पर होने वाली चर्चा को भी सुना। इसको देख कर मुझे एक आश्चर्य हुआ कि वित्त मंत्री महोदय ने हमारे ऊपर जो कमी का बजट और बाद में उस कमी की पूर्ति करके ११ लाख का सरप्लस बताते हुए आंकड़ों का भुलावा दिया उससे मैं यह नहीं समझ सका और उस बजट में कहीं यह चीज नहीं आई कि राज्य में जो विभाग के अन्दर आपकी जो बकाया बहुत बड़ी तादाद में, करोड़ों रुपयों की तादाद में चल रही है उसको वसूल करके घाटे को पूरा कर दिया जायेगा इस तरह का एक भी शब्द बजट भाषण में मुझे देखने को नहीं मिला। अब दूसरे विभागों की स्थिति का तो क्या प्रकाश डालें लेकिन वित्त मंत्रीजी के स्वयं के विभाग जो उनके तत्वावधान में कार्य करते हैं; उनके बकाया की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको और जनता को देख कर आश्चर्य होगा कि आज टैक्सेशन विभाग की १,६७,५८,५१३ रुपये की बकाया है और इसी तरह एक्साइज विभाग की ३७,४६,७२३ की बकाया है। आज जब १५५ लाख रुपयों का टैक्स लगाने का प्रश्न आया तो उसकी भूमिका बनाई जाय और उसकी आवश्यकता बताई जाय कि कुछ इलाकों में अकाल पड़ गया, कुछ ५) रु० कर्मचारियों के भत्ते व अलाउन्स देने के लिये अधिक खर्च आ गया, इसलिये हमको अधिक टैक्सों की जरूरत है। लेकिन आपने इस बात को नजरंदाज किया, आपने अपने विभाग और अपने आपको इस तरह पेश नहीं किया कि आपके विभाग में १ करोड़ ६७ लाख की बकाया पड़ी है उसको वसूल कर लिया जायगा।

आप तीन वर्षों से बजट पेश कर रहे हैं और बकाया की यह स्थिति चल रही है, लेकिन किसी भी बजट भाषण में आपने यह नहीं बताया कि जो इतने करोड़ की बकाया खाली आपके विभाग में है उसमें से कितने परसेन्ट आपने वसूली की। यदि आप इसकी प्रगति को बताते तो आपकी एफिशियेन्सी का दिग्दर्शन होता। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि आप अपने ही विभाग को संगठित नहीं कर सके और वसूली नहीं कर सके। यह हालत आपके विभाग की है फिर आप चाहते हैं कि टैक्स का भार जनता पर और लाद डालें? मैं इसके साथ यह भी बताऊंगा कि आज बकाया का यह हाल है, आपके वित्त विभाग का यह हाल है, आज अन्य विभाग जैसे इन्डस्ट्रीज विभाग में लाखों-करोड़ों रुपयों की बकाया है। वहां के फिगर्स नहीं दिये जाते और आपके विभाग के पास में फिगर्स नहीं हैं क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट और पी. ए. सी की रिपोर्ट से मालूम होता है कि

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

उनको, ऑडिट वालों को और पी. ए. सी. को उन्होंने फिगर्स नहीं दिये हैं कि उनके विभाग में कितनी बकाया है यह दूसरे विभागों का हाल है।

इसी तरह से आप देखिये कि पंचायत की तरफ से और सहकारी विभाग की तरफ से दिये जाने वाले लोन्स एण्ड एडवान्सेज़ की राजस्थान में क्या स्थिति है ? इसके फिगर्स को देखा जाय तो अचम्भा होता है और दुख भी होता है। आप, राजस्थान की खरी कमाई से होने वाली आमदनी है उससे पैसा किस हल्के तरीके से इन लोन्स एण्ड एडवाण्सेज में आप दे देते हैं और उसकी वसूली के लिए कोई स्टेप आपकी तरफ से नहीं लिये जाते हैं। जब आपको इसके बारे में कहा जाता है तो आप यह कह देते हैं कि इसकी वसूली के लिए, जो पैसेन्जर टैक्स और दूसरे टैक्स की बकाया है, वित्त विभाग की तरफ से कानून के अन्तर्गत ये स्टैप लिये गये हैं और पचास लाख की लिमिट फिक्स कर दी है और अब हम उम्मीद करते हैं कि वसूली जल्दी हो जायगी। यह कई वर्षों के बाद में सदन में कह कर आप अपने को सान्त्वना देना चाहते हैं और इस तरह के रिप्लाई दूसरी जगह भी देते हैं। आज अगर ऑडिट रिपोर्ट को, और पी. ए. सी. और एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट्स को देखा जाय तो आपको इसका सही नक्शा मिलेगा कि राजस्थान के अन्दर सरकार की बकाया की क्या पोज़ीशन चल रही है, लोन्स एण्ड एडवान्सेज़ की क्या पोजीशन चल रही है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर लोन्स एण्ड एडवान्सेज़ के रीप्रेमेन्ट का कोई सवाल नहीं है, जो बकाया है उसको कहीं पर तो राइट ऑफ कर दिया गया है और कहीं पर वसूली करली जाती हैं तो ब्याज नहीं लिया गया है। इसके एक एक मसले को मैं सदन में दोहराऊँ तो उसमें सदन का समय ज़ाया जायेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कि वित्त मंत्रीजी को शायद ऑडिट रिपोर्ट और पी. ए. सी. व एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट्स को देखने का मौका नहीं मिला या उनको देखने का समय नहीं मिला। उन रिपोर्ट्स को यदि आप देख लें तो इन सबकी पोज़ीशन आपके समक्ष साफ हो सकती है।

मैं इसके साथ ही आपको बतलाऊं कि आपके यहां पैसेन्जर टैक्स के लिए.........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह भी मजबूरी है फाइनेन्स मिनिस्टर की।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : करीब दस लाख रुपया पैसेन्जर टैक्स का राजस्थान में बकाया है और इस दस लाख में से एक पार्टी के अन्दर ६३ हजार रुपया बकाया है। पैसेन्जर्स टैक्स का इतना रुपये पार्टी में बकाया है............

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ६५ हजार बाकी हैं पैसेन्जर्स टैक्स के।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : ६३ हजार रुपये एक पार्टी के अन्दर बकाया है, यह आपके फिगर्स बताते हैं, और वह पार्टी है जाकिर हुसैन गुलाम अब्बास, यह आपके लिये.........

Page No 38

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : आप कौन से साल के फिगर्स बता रहे हैं ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : १-४-६४ तक का जो आपका रिप्लाई है, उसके ये फिगर्स हैं। उसके मुताबिक यह पोजीशन है कि यह १-४-६४ के फिगर्स दिये हुए हैं और एक पार्टी के अन्दर ६३ हजार रुपये बाकी हैं पैसेन्जर टैक्स। उसके लिए कई मर्तबा सदन के अन्दर प्रश्न आये हैं लेकिन इसको दरगुजर कर दिया जाता है और नज़र अन्दाज कर दिया जाता है। १९६२ के अन्दर आपने यह कहा था कि मैं जल्दी इसकी वसूली करने के लिए कोशिश करूंगा लेकिन १-४-६४ तक का आपका साफ रिप्लाई है, उसमें ये फिगर्स बकाया के दिखाये गये हैं। आप आखिर उस व्यक्ति के अन्दर इतने इन्ट्रेस्टेटड क्यों हैं ? उससे इस बकाया को वसूल करने प्रश्न पर इतने गंभीर क्यों नहीं है ? उसके बजाय आपने छोटे छोटे टैक्स जनता के ऊपर लगा कर १ करोड़ ५५ लाख रुपया वसूल करने का प्रावधान करके जनता के अन्दर क्षोभ उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। मैं यह कहूंगा कि यह प्रशंसनीय कार्य नहीं है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री-जी को अपने विभाग को टाइट करके अपने विभाग को दूसरे विभागों के समक्ष एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। आपके विभाग में बकाया की इतनी बड़ी भारी तादाद नहीं रहनी चाहिए और जो थोड़ी बहुत रहे भी तो उसके कारण होने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप दूसरे विभागों से और दूसरे व्यक्तियों से क्या उम्मीद करेंगे, जब आपके स्वयं के विभाग में १ करोड़ ६७ लाख रुपया बकाया में चल रहा है।

इसके बाद में मैं आपके सामने एक और भी मसला अर्ज करूंगा कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार आपके इस एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन के अलावा और जो विभाग हैं, उन विभागों की बकाया के जो फिगर्स हैं, वह ११४६.६१ लाख रुपया और विभागों की बकाया का कुल टोटल बताया है। आपके एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन का १ करोड़ ६७ लाख बकाया है और दूसरे विभागों का ११४६.६१ रुपया बकाया है—सन् १९६३ के आखिर तक; यह पोजीशन है और १-४-६४ के आपके बकाया के यह फिगर्स हैं मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी इतनी बकाया है और आप जब अपनी वित्तीय स्थिति को इतना कमजोर मानते हैं कि आपने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से रुपया ले रखा है, कर्ज ले रखा है, और तरह भी कर्ज ले रखा है कि उसके ब्याज के रूप में आपको करोड़ों रुपया अदा करना पड़ता है, लेकिन आप इस बकाया की वसूली करके उस ब्याज को नहीं बचा सकते हैं। उस पार्टी से आप रुपया छोड़ कर ब्याज भी वसूल नहीं कर सकते हैं और जब वसूल करते हैं तो केवल रुपया ही वसूल करते हैं। आप जो रुपया लेते हैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट से और दूसरी से, उसका ब्याज देते हैं और जिन पार्टी से आप अपना रुपया वसूल करते हैं उनसे आप ब्याज नहीं लेते हैं और कभी कभी तो इतनी तादाद में जो रुपया है, वह करोड़ों रुपया भी बकाया में छोड़ कर चलते हैं।

इसके अलावा और भी दयनीय स्थिति मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज राज-

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

स्थान के अन्दर ४९,२४९.८७ रुपया तो केवल मिसएप्रोप्रियेशन आपके कर्मचारियों के द्वारा हुआ है। उस मिसएप्रोप्रियेशन की रकम भी इतनी बड़ी भारी तादाद में है और उसकी वसूली का कोई सवाल नहीं है। आप उनके ऊपर केसेज़ चलाते हैं या नहीं चलाते हैं लेकिन उस रकम की वसूली का क्या हुआ ? यदि पहले की स्थिति को देखा जाय तो पहले कर्मचारियों के खिलाफ केस दायर हो या न हो, पहले उस रकम की वसूली के लिए प्रयत्न किए जाते थे। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट की यह भी एक अजीब बात है कि जो मिसएप्रोप्रियेटेड रकम है उसको आप उनकी सिक्योरिटी से, उनकी प्रोपर्टी से वसूल करने का प्रयत्न नहीं करते हैं और जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाती है तो आप बता देते हैं कि इतने लाख रुपए का मिस-एप्रोप्रियेशन हुआ है।

इसके अलावा एक और अजीब बात देखने को मिलेगी कि इस सरकार के द्वारा काफी रुपया दिया जाता है, ग्रान्ट इन एड और लोन्स के रूप में दिया जाता है, वह किन कामों के लिये दिया जाता है ? वह किसी सार्वजनिक कार्य को बता कर दिया जाता है। लेकिन उन पार्टीज ने वह काम किया या नहीं—इसकी जानकारी करने का कोई साधन आपके पास नहीं है। आप कहते हैं कि ऑडिट होता है, लेकिन आपके जो ऑडिटर्स हैं जिनके ऊपर एक एक विभाग में चार चार लाख रुपया खर्च होता है, इन ऑडिट पार्टीज़ पर इतना खर्चा करना पड़ता है। वे ऑडिट पार्टीज़ क्या करती हैं। वे केवल यह देखते हैं कि एन्ट्री है या नहीं, वाउचर हैं या नहीं,उनकी रसीदें हैं या नहीं, उसकी मंजूरी है या नहीं और इनको देख कर ऑडिट खत्म हो जाता है और ऑडिट रिपोर्ट्स आ जाती हैं। उन ऑडिटर्स से इसके लिए पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि यह हमारा फंक्शन नहीं है। अब जितना रुपया मंजूर हुआ था, उसकी रसीद आयी या नहीं, वह रुपया मंजूर हुआ या नहीं—इसके लिए कहा जाता है कि यूटीलाइज़ेशन सर्टीफीकेट दें। उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप केवल रसीद और मंजूरी का मिलान करने के लिए दूसरी एजेंसी रखते हैं लेकिन उसके यूटीलाइज़ेशन के लिए उसी विभाग की एजेंसी को रखते है। उसी विभाग का हेड या दूसरे ऑफिसर्स यूटीलाइज़ेशन सर्टीफीकेट दे दें तो उस रुपये को उसमें खर्च हुआ मान लिया जाता है। मैं आपकी मार्फत अध्यक्ष महोदय, सरकार से अर्ज करूंगा कि आज आप अपनी स्थिति को, इस सम्बन्ध की स्थिति को देखना चाहते हैं कि आपने जो रुपया वाकई जिस काम के लिए दिया।वह उस काम में लगा या नहीं उस रुपये से जो सामान आया वह सही दर आया या नहीं—इसको देखने के लिए जब तक आप दूसरी एजेंसी नहीं बनायेंगे तब तक कोई इस समस्या का निराकरण होने वाला नहीं है क्योंकि उन्हीं विभागों के आदमी यूटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट दे देते हैं।

इसके साथ ही यह भी अचम्भे की बात है कि आज सरकार के सामने यूटीलाज़ेशन सर्टीफिकेट आते नहीं हैं और इसलिए राजस्थान के अन्दर• १-४-६४ तक ६,२४.३६ लाख रुपया ऐसा पड़ा हुआ है जिसके यूटीलाइज़ेशन सर्टीफिकेट नहीं आये हैं। उन विभागों के द्वारा जो पैसा खर्च हो गया, उसका ऑडिट हो गया और ऑडिट रिपोर्ट

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

हो गई, लेकिन आज तक यूटीलाज़ शन सर्टीफिकेट नहीं है। आप इन सारी बातों को देखते हैं ? मैं समझता हूं कि आपको इन बातों को देखने का मौका नहीं मिलता है, वित्त मंत्री महोदय, ये आपकी रिपोर्ट्स, आपके फिगर्स—जो हमें सप्लाई किये जाते हैं—उनमें यह स्थिति मौजूद है लेकिन आपको उसकी फिक्र नहीं होती है। आप देखिए, यह नान-यूटीलाइज़ेशन की स्थिति क्यों है ? किन अधिकारियों की वजह से ऐसा हुआ ? उन अधिकारियों को किस तरह पीनेलाइज़ किया गया या नहीं किया गया ? उन अधिकारियों से यह रुपया वसूल क्यों नहीं किया गया ? यह सारी स्थिति इस बकाया और नान-यूटीलाइज़ेशन के सम्बन्ध में चलती है।

इसके बाद माननीय अध्यक्षजी, मैं अर्ज करूंगा कि वित्त मंत्री ने सदन को भुलावे में डाल दिया कि हमारे ६ करोड़ रुपयों का घाटा है और खर्चे का जो बजट दिया उसमें आपने ४.७५ लाख रुपया राजस्थान कैनाल के मद नं० ४१ में दिखा रखा है। एक तरफ आप ४ करोड़ ७५ लाख रुपया खर्चे का बताते हैं और उसी खर्चे को बता कर ६ करोड़ का घाटा दिखाते हैं। एक तरफ आप अपने ही भाषण में यह कहते जाते हैं कि राजस्थान कैनाल का खर्चा सारा का सारा सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया और उसका भार राजस्थान सरकार पर नहीं रहेगा उसके कारण खुशी मनाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप राजस्थान कैनाल का खर्चा बताते हैं। यदि आपके सामने यह स्थिति थी और आज भी मैं समझता हूं कि वही स्थिति है तो आप खर्चे के मद में ४.७५ लाख रुपया क्यों दिखाते हैं? आप यह कहेंगे कि हमने तो दिखा दिया था। जिस समय मिल जाएगा तो हम खर्चे खाते में डाल देंगे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब सेन्टर ने राजस्थान कैनाल की जिम्मेदारी अपने पर ले ली तो आपने फिर इसको घाटा किस प्रकार दिखाया ? यह तो फिर घाटा नहीं रहता। इसके अलावा आपने कहा कि बाकी के खर्चे की पूर्ति के लिए १ करोड़ ५५ लाख रुपया टैक्सेज लगा कर मीट आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं यह कहूंगा कि आपने यह कम दिखा कर पूंजी खाते से मीट आउट करने की बात रखी है इसकी आवश्यकता नहीं रहती है और जब इसकी आवश्यकता नहीं रहती है तो टैक्सेज़ नये लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इन आंकड़ों को देखते हुए, मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने टैक्स लगाने की आवश्यकता बतलाई है, यह एक भुलावा मात्र ही है और इसकी कोई नहीं। मैं यह कहूंगा कि यदि आप इस बकाया को राजस्थान कैनाल की रकम को एडजस्ट कर लेते हैं तो बाकी १.५५ लाख के नए टैक्सेज़ लगाये जावें, यह जरूरी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि एक तरफ आपने सरकारी कर्मचारियों के पांच रुपए बढ़ाये और एक तरफ अकाल हो जाने से आपने एक तस्वीर हमारे सामने रखी है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आपकी यह नीति थी तो आपको एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को सेपरेट करने की क्या जरूरत थी ? इनको

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

अलग अलग करने से करीब २५ परसेन्ट का खर्चा बढ़ गया। जिसको आपने सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट से पास कराया था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतने वर्षो तक आपका काम किस तरह से चलता था। जब कि अब आप इसको अलग अलग कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि इसको अलग अलग करने से २५ परसेन्ट आपके खर्चे में बढ़ोतरी होगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप पहले कहते थे कि अलग अलग करना चाहिए।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : आपके सामने यह मांग की जावे कि उसका औचित्य बताया जावे। मगर मैं इसके औचित्य पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसके बारे में इतनी बात जरूर अर्ज करूंगा कि आज इसके लिए पंजाब ने एक्सपेरीमेन्ट किया है उसकी मिसाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पंजाब ने हाल ही में, जहां पर एक्साइज एण्ड टैक्सेशन शामिल था, सेपरेट किया और फिर पंजाब गवर्नमेंट ने यह तय किया कि इसको अलग रखना उचित नहीं, इसको फिर से शामिल कर दिया जावे। जब एक जगह इसके लिये एक्सपेरिमेंट हो गया और इसके सेपरेशन को गलत माना गया तो हमारी सरकार ऐसे समय में जब वह अपने आपको घाटे में बताती है, उस वक्त आप इसको सेपरेट करके २५ प्रतिशत खर्चा बढ़ाते हैं और जनता से यह चाहते हैं कि टैक्स दें, यह तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

इसके बाद, चूंकि समय का अभाव है, मैं इस बात को आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ कि जहां पर पॉलिसी मेटर का प्रश्न आता है, तो वित्त मंत्री के भाषण में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि सरकार की पॉलिसी के कारण कोई नुकसान हुआ या सरकार की ढिलाई के कारण कमी रही। इसका दिग्दर्शन कहीं नहीं है, आपने उसकी तो सराहना ही की है; केवल यह कहा है कि प्रकृति के कोप से अकाल पड़ गया और ५ रुपये मंहगाई कर्मचारियों को देने पड़े इसलिये नये टैक्सों की जरूरत पड़ी। इसलिये इनको फोरन ही पास कर दिया जावे। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि आज आप विभागों में देखें तो आपको मालूम होगा कि नये नये विभाग खोलने की नीति बिल्कुल अलग है। कोई बात किसी के आइडिया में आई, किसी ऑफिसर की मर्जी आती है, नये नये स्कीम और आइडिया उसके दिमाग में आए, विभाग खोल दिये जाते हैं। आप एनीमल हस्बेन्डरी और इन्डस्ट्री विभाग को देखें तो आपको अजीब तस्वीर दिखाई देगी। आप देखेंगे कि इनमें २७-२७ शाखाएं खोल दी जाती हैं। रिसर्च के लिये अलग अधिकारी, अलग स्टाफ, मकान अलग; चाहे काम वहां पर कुछ भी हो या नहीं। किसी ने नया आइडिया दिया उसके अनुसार कार्य शुरू कर दिया जाता है। यह एक तरह की अजीब बीमारी चल गई है। नया आइडिया दिया कि नया विभाग खोल दिया जाता है। बेगर्स हौउस

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

खोल दिये जाते हैं, वहां स्टेनलेस स्टील के बर्तन रख दिये जावें। ४०० रु० माहवार का मकान किराये पर ले लिया जाता है। चाहे वहां पर कोई भी ब्रेडर नहीं आए। आज आपके सामने वित्त मंत्रीजी यह अवश्य कहेंगे कि इकोनोमी की आवश्यकता नहीं। यदि इसकी स्क्रीनिंग बड़ी बन जावे तो मालूम होगा। एस्टीमेट और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में आपको यह देखने को मिलेगा कि बहुत से अनावश्यक विभाग खोल दिये जाते हैं और अनावश्यक खर्चा किया जाता है।

इसके अलावा माननीय अध्यक्षजी, एक माननीय सदस्या ने अपने डिस्ट्रिक्ट को निग्लेक्ट करने के सम्बन्ध में विचार रखे। मैं आपके द्वारा यह बताना देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जयपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ सौतेला बर्ताव क्यों कर रखा है? यह बिल्कुल साफ है कि हमारी सरकार ने जयपुर डिस्ट्रिक्ट को कम्प्लीटलीं निगलेक्ट कर रखा है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिये यदि मौजूदा बजट में देखें तो कोई नई सड़क के निर्माण की बात नहीं है। कोई भी मांग की जाती है तो कहा जाता है कि अर्थाभाव के कारण। ईरिगेशन के लिये भी कोई स्कीम नहीं। दूसरी जगह कई प्रकार की स्कीमें बनाई जाती है, लेकिन जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा बांध जमवा रामगढ़ था जिससे १५ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी, उसको न मालूम किस पॉलिसी के नाते बन्द कर दिया। जमुआं रामगढ़ का बन्धा है जिससे जयपुर शहर को पानी दिया जाता है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या आप जयपुर को उससे पानी देना नहीं चाहते?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपने उसको किस प्रकार से बन्द किया। इससे १५ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। इसके लिये आपने आस-पास के गांवों के जिला परिषदों और पंचों की मीटिंग बुलाई और उनसे सुझाव लिये। जयपुर से दौसा तक जहां नहर जाती है उसको बिजली की अलग लाइन दी जावे और उसके लिये ४ लाख रुपयों का लोन दिया जावे। आपने यह स्कीम निकाली, उसकी कम्प्लायेन्स हुई। किसानों को तीन लाख रुपये दे दिये गये, उसको एक साल हो गया है। किसानों को एन्जिन के लिये लोन दिया गया ताकि कुओं पर बिजली पहुंचाई जाए। मगर वहां पर बिजली नहीं पहुंचाई गई। मैं यह कहूँगा कि यह ३ लाख रुपया बेकार गया और लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। छोटी छोटी लाइनों पर और भी कार्य हो रहे हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां एक बांध से १५ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी, तीन चार तहसीलें साथ साथ फायदा उठाती थी, वहां लोगों को ३ लाख रुपये लोन दिये जाते हैं और उनका उपयोग करने का मौका नहीं; आखिर आप उन काश्तकारों से इन्स्टालमेंट्स लेंगे, ब्याज लेंगे, वे मशीनें ला नहीं सकते, अगर लाये भी हैं तो लगा नहीं सकते क्योंकि आप उनकी बिजली नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से वह ३ लाख रुपया बेकार जा रहा है और काश्तकार बर्बाद हो रहे हैं, राहुग्रास

Page No 43

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

के बांध पर ५ लाख रुपया लगाया पर उस बांध को राइट ऑफ कर दिया, दूसरे बांध जो पहले से चालू थे उनको बन्द कर दिया। नये बांध बनाने के लिये आपने कोई कदम नहीं उठाया, मैंने सदन में कई बार रिड़ा चान्देरे के बन्ध की उपयोगिता बताई, उसकी सर्वे हो चुकी, जयपुर स्टेट के समय से उस बांध के बनाने की योजना थी, एक नदी को रोकना है इस बान्ध को बनाने के लिये और इससे काफी सिंचाई हो सकती है, पर आपने उस बांध को बंधाने के लिये आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, इस तरह आप जयपुर डिस्ट्रिक्ट के सार्वजनिक हित के कार्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं; क्योंकि यहां से आप नहीं आये, आपके लोग नहीं आये, विरोधी आये हैं। यही मूल कारण है कि आप यहां से नहीं आ सकते, आप अपनी दृष्टि को इतना सूक्ष्म रखते हैं कि जहां आप रहते हैं या आपके मिलने वाले रहते हैं, आप वहीं का ख्याल रखते हैं और इन्हीं जगहों में बिजली लगाते हैं, सड़कें बनाते हैं और दूसरे कार्य कराते हैं।

अब मैं थोड़ा जयपुर जिले में शिक्षा विभाग के कार्य के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। दौसा में डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग के लिये चन्दा करके हम लोगों ने २५ हजार रुपया दिया, यह २५ हजार रुपया दिया ४ वर्ष हो गये, पर अभी तक दौसा में डिग्री कॉलेज के लिये कोई बिल्डिंग आपने नहीं बनाई है, जो २५ हजार रुपया आपने लिया उसका ब्याज देने का या वह रुपया वापिस देने का कोई सवाल नहीं है। हर साल के बजट में आशा की जाती है। मिडल स्कूल की बिल्डिंग में डिग्री कॉलेज चल रहा है, पर आपने अभी तक डिग्री कॉलेज के लिये बिल्डिंग नहीं बनाई है। जब जब भी आपसे, पूछा जाता है तो उत्तर मिलता है कि अर्थाभाव है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गर्ल्स एजुकेशन के लिये मैं निवेदन करू कि हमारे वहां पूरी ८ तहसीलों में, पूरी पार्लियामेंटरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में एक भी गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है, उसके लिये मांग की जाती है तो अर्थाभाव का नाम लेकर इन्कार कर देते हैं। एक तरफ शिक्षा को प्रोत्साहन देने का दम भरते हैं और दूसरी तरफ गर्ल्स मिडल स्कूल के लिये, गर्ल्स कॉलेज के लिये मांग करते हैं तो अर्थाभाव का नाम लेकर टाल देते हैं। अब तो आपने यह नियम बना दिया है कि १३ हजार रुपया दो। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की बातें करके हमें मनवाना चाहते हैं कि शिक्षा का बजट प्रगति कर रहा है। जयपुर जिले के सार्वजनिक हित के कार्यों के सम्बन्ध में आपका रवैया बड़ा अन्यायपूर्ण रहा है; गर्ल्स हाई स्कूल खोलने के लिये मांग करते हैं, उसको आप पूरा नहीं करते, डिग्री कालेज की बिल्डिंग की मांग करते हैं और उसके लिये २५ हजार रुपया भी दे देते हैं तो भी आप डिग्री कॉलेज के लिये बिल्डिंग नहीं बनाना चाहते, बन्ध बनाने के लिये हमारे जिले के लिये आपके पास रकम नहीं है। जयपुर जिले के लिये इस प्रकार का रवैया जो आपने अख्तयार कर रखा है वह उचित नहीं है।

Page No 44

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में भारी रुपया खर्च होता है, मैं पूछता हूँ कि किस मद में खर्च कर रहे हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : जयपुर में एक भी मद में कमी बता दीजिये, राजस्थान के सारे जिलों से ज्यादा रुपया जयपुर डिस्ट्रिक्ट में खर्च होता है। बजट उठा कर देख लीजिये।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैंने बजट उठा कर देखा है। जो बजट पहले का है, उनकी पूर्ति के लिये रकमें दी हैं, नई स्कीमों के लिये--सड़कों, बांधों, हाई स्कूलों, कॉलेजों की बिल्डिंगों के मुतल्लिक एक पैसे का भी प्रावधान इसमें नहीं किया गया है।

समयाभाव के कारण मैं विशेष न कह कर इतना ही अर्ज करूंगा कि आज आप जयपुर जिले की जिस प्रकार अवहेलना करने पर उतरे हुए हैं, उसकी मिसालें आज सबके सामने हैं, हाई कोर्ट बैंच की मांग करते हैं, पर इतना अर्सा हो गया आपने उसे पूरा नहीं किया, रेवेन्यू बोर्ड की सीट की मांग करते हैं उसे आप पूरी करने वाले नहीं हैं, और जगहों पर अपीज़मेंट पॉलिसी के तार पर मेडिकल कॉलेज दूसरे डिविज़नों में खोल रहे हैं लेकिन यहां एक बैंच हाई कोर्ट की नहीं दे सकते, उसी तरह रेवेन्यू बोर्ड की सीट नहीं बढ़ा सकते। यह प्रेस्टिज पोइन्ट आपका हो गया है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करूंगा कि सरकार ने जयपुर को निग्लेक्ट करने की नीति बना रखी है, केवल थोथी सांत्वना देकर यहां के सार्वजनिक हित के कार्यों को खत्म कर देना चाहते हैं; यह आपकी अच्छी नीति नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री याज्ञनिक !

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज पहला मौका है कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने कार्यकाल में एक संतुलित बजट पेश किया है। इस बजट के अन्दर आपने कुछ राहतों की घोषणा की है जिसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। एक ओर ओल्ड एज पेंशन के अन्दर ५ रुपये की वृद्धि की है, दूसरी तरफ बेसहारा अपाहिज, अन्धे और अपंगों को २० रुपये की पेन्शन देने की घोषणा की है। इस तरह लड़कियों की शिक्षा की दिशा में सहायता प्राप्त स्कूलों व कॉलेजों को जो अनुदान दिया जाता है अन्दर फीस की रकम नहीं गिनने की घोषणा की है। इन सबके लिये वित्त मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं।

लेकिन इसके साथ आपने कुछ और घोषणाएं भी की हैं। कुछ टैक्सेज़ लगाए हैं; उन टैक्सेज़ का मैं विरोध करता हूं। मैं टैक्सेज़ के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस तरह के टैक्सेज़ वित्त मंत्री महोदय ने लगाए हैं, जैसे कि दवाइयों पर सेल्स टैक्स में २ प्रति-

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

शत वृद्धि की है वह ठीक नहीं है। एक वेलफेयर स्टेट का कर्तव्य है कि वह कम से कम जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री दे, पर इसके बदले यह घोषणा की गई कि दवाइयों पर टैक्स ज्यादा लगेगा तो मुझे दुख हुआ। इस तरह एन्टरटेनमेंट टैक्स ऊंचे क्लासेज़ पर लगाया उसमें तो हर्ज नहीं; लेकिन छोटे क्लासेज़ पर टैक्स लगाया वह ठीक नहीं किया। एक गरीब दुःखी आदमी पांच दस दिन में सिनेमा देखने जाता है तो उस पर यह टैक्स भारी पड़ेगा। इस तरह के जो टैक्सेज़ लगाए हैं उनका मैं विरोध करता हूं।

इसके साथ साथ मैंने कुछ भाषण विरोधी पक्ष वालों के सुने। एक सदस्य ने हमारी योजनाओं को महत्वकांक्षी बताया, तो महत्वाकांक्षी का वे क्या अर्थ लगाते हैं? अगर हमें आगे बढ़ना है तो आशा रखनी पड़ेगी और अगर मरना है तो हम संतोष कर लें। संतोष का दूसरा नाम मौत है। राजस्थान की जनता मरना नहीं चाहती, आगे बढ़ना चाहती है और उन्हें तो सरकार से शिकायत है कि वह योजना को और क्यों नहीं बढ़ाती है? हम चाहते हैं कि टैक्स का पूरा उपयोग हो और फिजूलखर्ची न हो।

अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हमारा राजस्थान अन्य स्टेट्स के मुकाबले में बहुत पिछड़ा है। इन्होंने राजस्थान का कम्पेरिज़न किया—केरल, वेस्ट बंगाल और गुजरात से। पर वह सदस्य यह भूल गये कि आज से १७ साल पहले राजस्थान की क्या दशा थी। राजस्थान छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। यहां स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे और गिरी हुई दशा थी। १७ साल में राजस्थान बहुत बदला है। जब दूसरी स्टेट्स से हम मुकाबला करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि वे कितनी पुरानी जमी हुई स्टेट्स हैं। अहमदाबाद में पहली मिल १०० वर्ष पहले खुली थी। तो राजस्थान में भी १७ साल में सरकार ने काफी काम किया है और हम कह सकते हैं कि राजस्थान में काफी काम हुआ है और राजस्थान का किसान खुशहाल है। आज से १७ साल पहले राजस्थान में जो किसान को बेगार करना पड़ता था, वह खत्म हो गया। आज जमीन का मालिक किसान है। गांव गांव में स्कूल खुले हैं। हमारी ही तहसील में आज ४ अस्पताल और २ हायर सेकन्ड्री, ८ मिडल और ६० प्राइमरी स्कूल हैं। तो सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने सिरोही जिले की समस्याओं पर कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि सिरोही जिले में सिरोही शहर में कॉलेज है। आज से ४ साल पहले जिले की जनता ने साइंस ब्लॉक के लिए ५० हजार रुपये इकट्ठे करके सरकार को दिए और सरकार ने उतने ही रुपये खर्च करने का आश्वासन दिया और स्कूल की मंजूरी भी आ गई लेकिन आज तक वहां सरकार ने पैसा खर्च नहीं किया। साइंस क्लासेज़ के लिए कमरे अपर्याप्त हैं और विद्यार्थियों और प्रोफेसर्स को परेशानी है। तो मेरा शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि इस साल वे साइंस ब्लॉक पूरा कर दें।

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

सिरोही जिले की शिवगंज तहसील के अन्दर एक सूकड़ी नदी है। इस नदी पर सरकार ने इनन्डेशन बांध बनाया सिंचाई के लिए, लेकिन उसका उल्टा असर पड़ा है। उस बांध के बन जाने से जो जमीन नीचे थी वहां रेत पड़ गयी और हजारों बीघा जमीन खराब हो गई। वह नदी जोयला गांव के बीच में होकर जाती है और हर साल बाढ़ में किनारे के कई मकान बह जाते हैं। इसके लिए भी मंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया, पर आज तक कुछ नहीं किया गया। तो इनन्डेशन डैम को बदल कर स्टोरेज डैम बनायें।

रोहिड़ा गांव के अन्दर एक हायर सैकन्डरी स्कूल है। उस गांव के ३० मील के अन्दर किसी स्कूल में साइंस ब्लॉक नहीं है, न ही विज्ञान कक्षाएं चलती हैं। उस गांव के गर्ल्स स्कूल—दूसरे स्कूल अस्पताल आदि की बिल्डिंग्ज़ सब जनता ने बनवा कर दी हैं। वहां साइंस का ब्लॉक बनना जरूरी है। वहां आदिवासी क्षेत्र भी है। इसके लिए भी मंत्री महोदय से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक ओर तो हम इतना पैसा शहरों पर खर्च करते हैं और वहां पर लोगों ने ३ लाख रुपये की बिल्डिंग्ज़ दी हैं। तो वहां कम से कम इसी साल साइंस ब्लॉक बना कर इसी वर्ष से विज्ञान कक्षाएं तो खोली जायं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के प्रश्न पर आता हूं। रोहिड़ा--सरूपगंज एक ऐसा एरिया है जहां खेती का लोड मिल सकता है। सरूपगंज मंडी है और वहां पर इंडस्ट्रीज़ लगने का स्कोप है। रोहिड़ा बड़ी आबादी का कस्बा है और उसके पास में दूसरे कस्बे हैं। वहां १०००० की आबादी है और वहां कई इंडस्ट्रीज़ खुल सकती हैं और लोड मिल सकता है। वहां पर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। एक ११ लाख रुपये के प्रोजेक्ट की स्कीम बनी थी पर हुआ कुछ नहीं। तो कम से कम उस रोहिड़ा सरूपगंज एरिया के अन्दर बिजली लाकर उनको राहत दें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं वन विभाग पर आता हूं। जितने घोटाले वन विभाग में चलते हैं उतने शायद कहीं नहीं चलते। यह सरकार की नीति है कि जहां पंचायतें घास लेना चाहती है वहां उनको औसत रेट पर बीड़ दे दिये जायं पर हमारे वहां डी. एफ. ओ. साहब की झाड़ोली पंचायत से नाराजगी है इसलिये वहां के घास बीलर बीड़ को पंचायत को औसत रेट पर नहीं दिया और नीलाम कर दिया, पंचायत ने डी. एफ. ओ. साहब से मांगा, पर उसे नहीं देकर नीलाम कर दिया। लिखा-पढ़ी की तो मंत्री महोदय कहते हैं कि अब तो नीलाम हो गया, अब नहीं दे सकते। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, मन्त्री महोदय से कि जिस अफसर ने इस तरह का काम किया है कम से कम उसको तो सजा मिलनी चाहिये। पर मैं जानता हूं मन्त्री महोदय इसके लिये कुछ नहीं करेंगे।

इसी तरह पिंडवाड़ा में अम्बिका वन श्रमिक सहकारी समिति है। सरकार की यह भी पॉलिसी है कि जितने कूप दिये जायं सहकारी समितियों को दिये जायं। उस

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

सहकारी समिति ने लिखकर दिया, पर कन्ज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स ने नीलाम कर दिया, ३७ हजार की उसकी कीमत हो गई। वह सहकारी समिति बेकार है।

अब एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। मन्त्री महोदय से मैंने निवेदन किया कि मेडीसिन्स पर टैक्स लगाया है, एन्टरटेनमेंट पर टैक्स है, ये टैक्स नहीं होने चाहिये, इन टैक्ससेज़ को नहीं लेना चाहिये। इसके अलावा एक और निवेदन करूंगा कि गत वर्ष आश्वासन दिया था कि सरचार्ज खत्म करेंगे, उसे खत्म नहीं किया गया है, वेलफेअर स्टेट में यह एक ब्लोट है, यह खत्म होना चाहिये।

फूड ग्रेन्स पर टैक्स है, यह टैक्स भी गरीब जनता के लिये मुश्किल पड़ता है। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि कम से कम इस टैक्स को वापिस ले ले।

एक बात और कहूंगा, खातेदारों की जमीनों में कूएं हैं, उनको ट्रान्स्फर करने के लिये कीमत रखी है, यह गैर वाजिब है। आज पचास २ सालों से जो किसान उन कूओं पर काबिज हैं उनसे किस तरह से आप कीमत ले सकेंगे?

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये)

श्री अध्यक्ष : श्री जावन्दसिंह।

※**श्री जावन्दसिंह** (करणपुर): अध्यक्ष महोदय, जो बजट आया है, उस पर कहना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अगर आज्ञा हो तो मैं अनुवाद करता जाऊं।

श्री जावन्दसिंह : दो साल से पानी की बहुत कमी हो रही है। इसी कारण से ही बाहर से अनाज लाकर यहां सप्लाई किया जाता है। जब पानी की कमी नहीं थी तो यह जिला सारे राजस्थान को अनाज सप्लाई करता था। गंग कैनाल की सालाना बन्धी दिसम्बर के आखिर में या जनवरी के पहिले हफ्ते होनी चाहिये। मैं करीब तीन साल से इस बात की चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन अभी तक भी इस सालाना बन्धी की पहिले वाली बात ही चली आ रही है कि सालाना बन्धी फरवरी या मार्च में करते हैं। इससे जमींदार को बहुत भारी नुकसान होता है। इसकी वजह यह है कि सर्दियों में, दिसम्बर-जनवरी में, जब फसल छोटी होती है तब तो सालाना बन्धी नहीं होती है, लेकिन बाद में फरवरी-मार्च में जब फसल को पानी की जरूरत होती है तो सालाना बन्धी कर दी जाती है, उससे जमींदार को बहुत नुकसान पहुंचता है। जो नहर करीब ३५ वर्ष से चल रही है उस नहर में अब इस वक्त ठोकर लगाने की क्या जरूरत पड़ी? जो यह ठोकरें लगाई गई हैं, वे बहुत गलत तरीके से लगाई गई है, इन ठोकरों को लगानेकी जरूरत नहीं थी; फिर भी ये ठोकरें लगाई गई जो किसी गलत वजह से लगाई गई। इसका कारण

※ पंजाबी भाषा में दिये गये मूल भाषण का माननीय सदस्य से लिखित में प्राप्त हिंदी अनुवाद।

(श्री जावन्दसिंह)

तो मंत्री महोदय खुद ही समझ सकते हैं। एक छोटी नहर जिसका नाम 'औ' माइनर है और जो 'एफ' नहर से निकलती है उसमें ये ठोकरें लगाई गई है। ठोकरों के नजदीक वाले जो मोगे हैं वे टेल वालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): मोगे पक्के सीमेन्ट के बनने के बाद यह हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके दिमाग में यह नहीं बैठेगा। मोगे तो पहले से ही पक्के थे।

श्री जावन्दसिंह : बड़े दुःख की बात तो यह है कि हमारा पानी जहां से आता है, हरी के हैड से, वहां हमारा कोई अफसर नहीं है। वहां हमारे किसी अफसर का होना बहुत जरूरी है जो वहां से हमारा वाजिब हक हमें दिलवा सके।

पानी जो हमें २७ सौ क्यूसेक्स मिलना चाहिये था उसके बजाय सिर्फ ८ सौ क्यूसेक्स पानी ही मिला।

राजस्थान केनाल की जमीन व पानी होते हुए भी जमींदारों को काश्त करने को नहीं दी जा रही है, जगह जगह जमींदार जमीन को लिए भटकते फिर रहे हैं, सरकार का पानी भी फालतू जा रहा है, उसको कोई संभालने वाला नहीं है और जमीन भी लाखों बीघा खाली पड़ी है। अगर जमींदारों को काश्त करने के लिए दी जाय तो खाद्य की समस्या तो हल हो जाय; अनाज बाहर से लाने की क्यों जरूरत पड़े? हमारे यहां ही अनाज काफी तादाद में पैदा हो सकता है। इस साल हाड़ी की फसल पानी न मिलने के कारण बिल्कुल खराब हो गई, उसकी कम से कम आधी मालगुजारी तो माफ होनी चाहिए। मालगुजारी तो क्या देंगे, जबकि काश्तकारों ने जो महंगा बीज ७०), ८०) रु. क्विन्टल के भाव का डाला है वह भी पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि मालगुजारी इस साल आधी से ज्यादा नहीं ली जानी चाहिए।

बिजली विभाग वाले अफसर खेतीवाड़ी के लिए कहीं भी बिजली नहीं दे रहे हैं तो फिर खेत का उत्पादन कैसे बढ़े और जब कि कारखानेदारों को जगह जगह पर बिजली दी जा रही है। मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि खेतीबाड़ी के लिए पहिले बिजली दी जानी चाहिए और कारखानेदारों को बाद में।

बोर्डर एरिया की हिफाजत के लिए पक्की सड़क होना जरूरी है, लेकिन अभी तक बोर्डर के नजदीक कहीं भी पक्की सड़क नहीं बनी है। इसके अलावा करनपुर से रायसिंहनगर तक सड़क पक्की होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सड़क बहुत पुरानी हो गई है और इसमें जगह जगह काफी गड्ढे पड़ गए हैं। अगर हमारे मिनिस्टर कभी इस तरफ दौरा करें तो उस रास्ते की हालत का पता उनको लग सकता है कि रास्ते की क्या हालत है? इसलिए करनपुर से रायसिंहनगर को जाने वाली इस सड़क का पक्का होना व ठीक होना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर महोदय इस पर जरूर अमल करेंगे।

Page No 49

(श्री जावन्दसिंह)

जंगल के रहने वाले जानवर जिनको चील कहते है, एक चील के बच्ची थी और एक चील के एक बच्चा था, उन दोनों ने आपस में रिश्ता कर लिया। जिस चील का बच्चा था उसने बच्ची वाली चील से कहा कि इनकी शादी करे तो बच्ची वाली चील बोली इस वक्त मेरे पास दहेज वगैरह नहीं है, कुछ अर्सा ठहर कर शादी करें ताकि शादी पर बच्ची को देने के लिये मेरे पास कुछ हो जाय। तो बच्चे वाली कहने लगी कि अभी तक कुछ नहीं हुआ तो फिर अब थोड़े अर्से में कैसे हो जायगा ? बच्ची वाली चील बोली जो इस वक्त गद्दी पर राजा बैठा है वो जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और न दौरा वगैरह करता है सिर्फ अपने ऐशो-आराम में रहता है। अगर यही राजा एक-दो साल और रह गया तो जब जंगल ही जंगल, उजाड़ ही उजाड़ हो जायगी, फिर हम शादी कर सकेंगे और दहेज में देने के लिए सब इलाकों में उजाड़ हो जाएगी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर हमारी मौजूदा मिनिस्टरी का यही रवैया रहा तो गंग कैनाल का सारा इलाका उजाड़ हो जायगा।

कुछ माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय......

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आप तो बाद में ही बोल लेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : हमारा भाषण सुनकर कुछ कहते तो अच्छा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी सदन के सदस्य की हैसि-यत से बोल रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरे बोलने के बाद एक बार फिर तकलीफ करनी पड़ गी आपको।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के सिलसिले में सामान्य वाद विवाद चल रहा है। मैं लगातार पिछले चार दिन से इस वाद-विवाद को सुन रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रजातन्त्र में यह सदन जो कि आम जनता की भावनाओं का एक रिफ्लेक्शन है और जो भावनायें जनता की इस प्रान्त में काम कर रही है उनको जो कुछ मैं मेरे तरीके से महसूस करता हूं, मेरे इधर-उधर आने-जाने के दौरों के सिल-सिले में, मुझे ऐसा एहसास होता है कि उन भावनाओं का सही रिफ्लेक्शन जो इन मान-नीय सदस्यों को करना चाहिए वह सही रिफ्लेक्शन मुझे यहां पर प्रतिबिम्बित होता हुआ नजर नहीं आता।

मैं आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हमको इस प्रान्त की और देश की समस्याओं पर गम्भीरता के साथ विचार करके जिन दिशाओं में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी तरह कुछ रचनात्मक दृष्टिकोण से अपने सुझाव द्वारा विचार हमको रखना पड़ेगा। हम जिन दिशाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं जिसका कि मैंने काफी जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बहस के सिलसिले में किया था। मैं उन बड़े मुद्दों का इस समय जिक्र नहीं करूंगा।

(१.०० म. प.)

हमारा लक्ष्य समाजवाद की ओर बढ़ने का है। सदन के माननीय सदस्यों ने इस बजट के अन्दर जो बड़े मुद्दे हैं जिनका जिक्र वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में किया है, जिसका रिफलेक्शन बजट के इन पोथों में रिफलेक्शन के तौर पर रखा गया है, जिनकी चर्चा विस्तार से मांगों पर बहस के दौरान करेंगे। उन पर कॉम्प्रीहेन्सिव व कम्प्लीट व्यू लिये बिना कुछ इधर-उधर की बातें पकड़ कर माननीय सदस्य इस तरीके से रखना चाहते हैं। जहां पर कम ध्यान देने की आवश्यकता है वहां उनके कहने के अनुसार ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस पर भी अच्छे सुझाव दिये जा सकते थे उन सुझावों की कमी को मैं महसूस करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। उसी का उल्लेख इसमें किया गया है, वह हम देश का उत्पादन बढ़ाकर ही कर सकते हैं। योजनाओं के आधार पर प्रोडक्शन में बढ़ोत्तरी करें; कृषि, गृह उद्योग, बड़े उद्योग के क्षेत्र हैं, पशु-पालन इनके जरिये जो उत्पादन क्षमता है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिये रिसोर्सेज की आवश्यकता है, वह हम जुटा पाये हैं। हमारी योजना में इस वर्ष में जितना इरादा रखते हैं उसके बारे में कुछ जिक्र किया गया है। मैं समझता हूं, इस बारे में सदन ने कॉम्प्रीहेन्सिव व्यू लिये बिना छोटी छोटी बातों में ज्यादा उलझते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस राजस्थान के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में राजस्थान को हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों से तुलना करने की कोशिश की है उन्होंने राजस्थान के लिये यह कहा कि यह राजस्थान सरकार जो इस बजट के जरिये दावा करती है कि हम काफी आगे बढ़े हैं उनका दावा सही नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्त; बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, यू. पी. आदि प्रान्तों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के अन्दर कुछ अमुक एरियाज़ के अन्दर इतने टीचर्स, इतने स्टुडेन्टस हैं, उसके मुकाबले राजस्थान में बहुत कमी है। राजस्थान में टेक्सेज का भार अन्य प्रान्तों की अपेक्षा ज्यादा है। पर-केपिटा यहां टैक्स ज्यादा हैं। पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेन्ट किया गया जिसका परिणाम आना चाहिये वह नहीं आ रहा है। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है, राजस्थान अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से मैं इस बात का दावा नहीं करता, फिर भी राजस्थान का एक पुराना इतिहास रहा है। हमें इन सबको उसकी बैंक ग्राउन्ड में देखना होगा। १६४६ से पहले राजस्थान नाम की कोई चीज नहीं थी। ४६ में राजस्थान बना, उसके बाद में भी कई स्टेजेज में जाकर इसका एकीकरण हुआ। राजस्थान में ५६ में जाकर अजमेर का विलीनीकरण हुआ। उसका मुकाबला हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों से जो कई वर्षों से, चाहे वे अंग्रेजों की हकूमत में रहे हों उसके अलावा पिछले दो सौ वर्षों से उनका अपना स्टेन्डर्ड था। उनकी मशीनरी थी काम करने की। वे सदा से आगे बढ़ते रहे थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आज राजस्थान ने उन राज्यों की श्रेणी में जो बहुत ऊंचे हैं और न राजस्थान सबसे पिछड़े हुए राज्यों में आता है; राजस्थान कई मामलों में सब राज्यों के सीरीज के बीच में आता है, तो किसी में नीचे से तीन-चार स्टेट्स के ऊपर ही आता है; अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग श्रेणी में आता है। किसी में बीच में आता है। यह दृष्टिकोण आपको मिलेगा। यह राजस्थान की पिछली दस-बारह साल की तस्वीर है जो मैंने आपके सामने रखी है। हम अपने प्रान्त को सुन्दर और मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर हम यहां की पर--केपिटा इनकम को तेज गति से बढ़ाना चाहते हैं तो हमको योजनाओं पर ज्यादा धन खर्च करना होगा और ज्यादा उत्पादन करके पर-केपिटा इनकम बढ़ा सकते हैं।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, राजस्थान की पर--केपिटा इनकम को और तेज गति से बढ़ाने के लिये, ऑल इन्डिया एवरेज तक लाने के लिये बड़े पैमाने पर योजनायें बनानी पड़ेंगी। मुझे इस बात की खुशी है कि वे योजनाओं में विश्वास रखते हैं और उनका मानना है कि योजनायें बड़ी बननी चाहिये और उनको पूरा किया जाना चाहिये। अगर हम सही मायने में ऑल इन्डिया एवरेज या उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो यही रास्ता हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें योजनाओं को बड़ी बनाने के लिये साधनों की गुंजाइश पैदा करनी होगी। साधनों के बारे में चर्चा करते हुए जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना दृष्टिकोण रखा। इस साल के बजट में वित्त मंत्री महोदय ने जो कुछ टेक्सेशन के सिलसिले में प्रस्ताव रखे उक्त प्रस्ताव के बारे में मैं समझता हूं; किसी न किसी रूप में हर माननीय सदस्य ने उन टेक्सेज का विरोध किया है। उनका कहना है कि राजस्थान की जनता अब टेक्सों के भार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विचार सदन के माननीय सदस्यों का हो सकता है। अगर माननीय सदस्य गंभीरता से इस पर विचार करें, यह तो सुझाव जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया कि भारत सरकार को कहना चाहिये कि राजस्थान की जनता की शक्ति नहीं कि इस प्रकार कर भार को वहन कर सके, इसलिये सेन्टर को हमें ज्यादा पैसा देना चाहिये; कोई भी जिम्मेवार सदस्य जो प्रान्त की तरक्की करना चाहते हैं वह यह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नहीं चाहेगा कि हम अपनी तरक्की के लिये दूसरों के भरोसे रहें। हम तो कुछ करने को तैयार नहीं और उसके लिये दूसरों से मदद मांगने जायं! आज हमारा देश एक है। हमारी केन्द्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी है, वह हमें हमारे विकास में मदद करे। केन्द्रीय सरकार अपनी तरफ से हमारी मदद करती है वह सारे राज्य के बेस को मानकर। उनके पास संविधान के अन्तर्गत जो भी गुंजाइश है वे साधन हमें उपलब्ध कराती है। उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को अपनी योजनाओं के लिये जिस किसी प्रकार भी धन की कमी को पूरा करवाती है, एक योजना के पूरी होने के बाद फाइनेन्स कमीशन बैठता है। वहां जितनी धन की कमी होती है उसकी चर्चायें की जाती हैं। फाइनेन्स कमीशन, डेफीसिट होता है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। उसके अलावा भी समय समय पर योजनाओं में जिनका आधार देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होता है प्लान सीलिंग के अलावा भी मदद देता है। खास तौर से कृषि के मामले में, सिंचाई के मामले में केन्द्रीय सरकार ने हमारी तीसरी योजना के लक्ष्य के अलावा इन मदों के अन्दर सहायता दी है, मदद दी है, क्योंकि देश के लिये यह जरूरी था। सिर्फ यह कहना कि राजस्थान सरकार केन्द्र से यह कहे कि राजस्थान की जनता में अब कर भार वहन करने की शक्ति नहीं और परबारा रुपया आ जाय और टैक्स न लगये जायं, और पर-केपिटा इनकम भी बढ़ती जाय, यह नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की दलीलें न केन्द्रीय सरकार सुन सकती है, न उन पर गौर कर सकती है और न गौर किया जाना सारे देश की हालत को देखते हुए वाजिब है। इसलिये हमें हमारा काम करना होगा। हम कितना क्या कर सकते हैं, यह हमें सोचना चाहिये।

तीसरी योजना में हमने तय किया है कि इसे पूरा करने के लिये हम १३२ करोड़ रुपया नये टैक्सों के जरिये जुटावेंगे और जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा है कि जो कुछ टैक्स पिछले चार सालों में लगाये हैं उनसे जितने टैक्सों की टोटल रकम इस योजना के पांच सालों के बाद बनेगी वह इस साल के अन्त तक २६ करोड़ के लगभग होगी। १ करोड़ ५५ लाख के टैक्स इस बजट में और रखे है। उस जोड़ दें तो ३०।। करोड़ रुपया और यदि कुछ ज्यादा मिल जावे तो जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का अन्दाज हैं ३१ और साढ़े इकत्तीस करोड़ से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं हो सकता।

राजस्थान की जनता ने जो सेक्रीफाइस किया है योजनाओं को पूरा करने में उस हिम्मत और हौसले से उसे पूरा करके फिर हम अगर भारत सरकार के पास जावेंगे चौथी योजना के प्रारूप को लेकर तो निश्चित तौर से हमारी बात वे सुनने वाले हैं, उसका असर होने वाला है और होने वाली चौथी योजना का प्रारूप जो रखा जा रहा है उस पर भी भारत सरकार को गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। चौथी योजना में भी जो हमारी क्षमता बनेगी तो उस पर भी अगली

Page No 53

(श्री रामनिवास मिर्धा)

पांचवीं योजना में हम मैग्ज़िमम कोशिश करेंगे वहां से लेने की। उसमें भी जो हम ४५० करोड़ का प्रावधान करना चाहते हैं उस बारे में मैं यह कह कर चलना चाहता हूं कि हमें उसके लिये भी उसी क्षमता का दिग्दर्शन करना पड़ेगा। हमारे मुख्य मंत्री जी ने पहले भी कहा है, और सदस्य भी जानते हैं कि भारत सरकार का जो रुख हमारे प्रति रहा तीसरी योजना में भी पर-कैपिटा राजस्थान की जनता के हिसाब से भी अन्दाज लगावें तो जो धनराशि भारत सरकार ने हमें दी है, १५६ करोड़ रुपया सहायता के रूप में दिया है, वह किसी भी स्टेट के मुकाबले में कम्पेयर करें, तो राजस्थान का आंकड़ा पहली एक-दो स्टेटों के मुकाबले में आवेगा।

इसलिये अगर राजस्थान, भारत सरकार से ज्यादा बड़ी योजना की मांग करता है और जनता की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाकर समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहता है तो उसे स्वयं को सेक्रीफाइस करना होगा और अपने निश्चित इरादे और दृढ़ शक्ति को लेकर जाना होगा, तभी भारत सरकार के सामने उसकी बात पार पड़ने वाली है। हम इस इरादे को लेकर नहीं चल सकते कि हम कुछ नहीं करना चाहते। भारत सरकार हमें तो सब पैसा दे। चाहे दूसरे देशों से उधार लाकर दे तो दे। फिर आप योजना बनावेंगे तो हम पूरी कर देंगे। तो यह रवैया और यह दलील लेकर हम भारत सरकार के पास नहीं जा सकते और न यह दलील चल ही सकती है।

इसलिये मैं कहता हूं कि चाहे हम यह कहें कि इस टैक्स को कम करें, उसको अच्छा न कहें, फलां को बुरा कहें, सदन के माननीय सदस्य अपने-अपने दृष्टिकोण से अपने अपने विचार रख सकते हैं। पर यह विचार भी सदस्यों को ही करना है कि हमें अपनी ही क्षमता पर चलना है, अपनी ही क्षमता का बल लेकर हम भारत सरकार से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, नहीं हो नहीं। हम यह बहुत आसानी से कह सकते हैं कि किसानों पर टैक्स का भार बढ़ गया, जनता पर टैक्सों का बोझा बहुत बढ़ रहा है सर-चार्ज का भार बढ़ गया है, ऑइल का भाव बढ़ गया है। यह कह कर भले ही हम लोगों को सन्तोष दिला सकते हो कि हमने आपकी विधान सभा में जाकर काफी पैरवी की। आपकी शक्ति नहीं है इतने टैक्सों का बोझ उठाने की और अगर है तो हमने तो यह कहा है। यह विरोधी पार्टियों का, राजनैतिक पार्टियों का दृष्टिकोण हो सकता है। यह कहने के लिये आसान भी लगता है, अच्छा भी लगता है। पर सही दृष्टिकोण यह नहीं कहा जा सकता, न हो सकता है।

आज अगर हम योजना का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो हमें इसका बोझ उठाकर चलना होगा। मैंने पहले भी कहा है और आज भी जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करके हमें अपनी प्रगति करनी है अपने को समृद्धि की तरफ ले जाना है तो हमें इसके लिये हर हालत में कुर्बानी करनी होगी, इस स्टेट के लोगों को ज्यादा शक्ति के साथ कमर बांधकर चलना पड़ेगा और हिम्मत और जोश के साथ इन योजनाओं को पूरा करना होगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप भी तो थोड़ी बहुत कुर्बानी करो, आप तो बहुत मोटे ताजे हो रहे हो। चारों तरफ से बटोर रहे हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब आप बिराज जाओ तो अच्छा है। आप जब बोल रहे थे तो मैंने शांति से आपको सुना था। आप भी शान्ति से सुनें। आपकी बात बड़े ठंडे दिमाग से सुनता हूं।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमें बहुत मजबूती के साथ, विश्वास के साथ और कुर्बानियां करके भी आने वाली पीढ़ी की सुख और समृद्धि के लिए हमारी योजनाओं को, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। अपने उत्पादन में वृद्धि करनी होगी और इसके लिये हमें कुछ कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा तो करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक ओर यह कहा जा रहा है कि इस योजना के आकार और प्रकार में कमी की जावे, जनता पर टैक्सों का बोझ कम किया जावे, यह बोझा उस जनता पर पड़ता है, किसान पर पड़ता है। उनकी क्षमता नहीं है। वे बहुत गरीब हो गये हैं। उनकी कमर झुक गयी है। टूटने को है। तो मैं एक बात मानकर चलता हूं और पहले भी वह बात कही थी, अब भी कह रहा हूँ कि और किसी की कमर टूटी हुई है, तो मैंने तो यह नहीं देखा। बल्कि मेरा तो दावा है, मैं कह सकता हूँ कि इस राजस्थान में इन पहली और दूसरी योजनाओं की समाप्ति और तीसरी योजना के प्रारम्भ के बाद राजस्थान में किसान मजदूर गरीब जिस किसी को भी लीजिये, उन सबके आर्थिक जीवन में एक कदम, दो कदम, तीन कदम और चार कदम का सुधार हुआ है। और इस दर्मियान न आज तक किसी की कमर टूटी है, न वह टूटने की स्टेज कभी आने वाली है, बल्कि ज्यों ज्यों हमारी योजनाओ के लक्ष्यों की तरफ हम दृढ़ता से आगे बढ़ते जावेंगे उनकी कमर सीधी और मजबूत होती जावेगी।

इतना कहने के बाद मैं कुछ खास मुद्दों की तरफ आना चाहता हूँ जो मेरे विभाग से सीधे सम्बन्धित हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): तो this is preamble only.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जोर से कहा जाता है कि महंगाई बढ़ रही है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। राज्य कर्मचारियों के लिए जो बजट में रिलीफ दिया गया है वह इतना थोड़ा है कि महंगाई पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उनका असन्तोष भी बराबर बढ़ता जा रहा है, यह भी कहा जा रहा है और उनका असन्तोष बढ़ाने के लिये भी बातें यहां कही जाती हैं। इस दृष्टिकोण से भी यहां कहा जाता है। राजनैतिक पार्टियों के होते हैं अपने-अपने दृष्टिकोण। वे कुछ न कुछ इरादे से ही अपनी बातें कहते हैं। पर हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हम इन इरादों से उस स्थिति में न पहुंच जावें जहां जाकर उसके परिणाम उनके ही लिये खतरनाक हो जाएं। आज कांग्रेस सरकार है, कल दूसरी कोई भी सरकार आ सकती है, तो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इस तरह से राज्य कर्मचारियों में असन्तोष का मानस बनाया गया तो वह किसी भी राजनैतिक पार्टी के हित में नहीं होगा। भारत के एक कौने में एक राज में आज वही स्थिति बनी है; जिसके अन्दर एक चुनाव हो चुका दो हो चुके आज कोई भी पार्टी स्टेबिलिटी में वहां नहीं है। एक इन-स्टेबिलिटी की हालत वहां पैदा हो गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कोई इन-स्टेबिलिटी नहीं है। नन्दाजी को कहिये कि लेफ्टिस्ट कम्यूनिस्टों को छोड़ कर देखें वे। सरकार बन सकती है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अपनी बात अपने समय पर कहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यहां भी आप हरिरामजी लाइये। अभी स्टेबिलिटी को इन-स्टेबिलिटी में परिवर्तित कर देते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : देश के एक कौने में जैसी हालत चल रही है अगर यही हालत हिन्दुस्तान के ज्यादा हिस्सों में पैदा कर देंगे, ऐसे राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन देकर या उकसा कर, तो यह हमारा कदम सही प्रकार का नहीं होगा। इससे इन-स्टेबिलिटी पैदा होगी और उसके जो परिणाम होंगे वे देश के लिए घातक होंगे और जिस प्रजातन्त्रीय प्रणाली के माध्यम से जिस मजबूती से हमारे देश, प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ना चाहता है उसमें रुकावट के सिवाय और कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं सदन के माननीय सदस्यों को कि उन्होंने महंगाई की बात कही। मैंने इस सदन के सदस्यों को जो कहा है कि दो, तीन, चार महीनों में इस महंगाई की परिस्थितियों में अन्तर आवेगा, गिरावट आवेगी तो आज जो स्थिति उनके सामने है वह मैं यहां रखना चाहता हूं। आज से करीब चार या तीन महीने पहले जन-जीवन की जरूरी आवश्यक वस्तुओं की हमारे राज्य के सभी लोगों को और देश के आम लोगों को जरूरत पड़ती थी, जो वे काम में लेते थे उनके भावों में कितना उतार-चढ़ाव आया है पहले से आज, उसका अन्दाज इस सदन के माननीय सदस्य लगा सकते हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज से दो, तीन, चार महीने पहले जो भावों की स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें कितना अन्तर है ? आज से दो-तीन महीने पहले बाजार के अन्दर जौ का भाव ६४-६५ रुपये क्विंटल था, वहां पर आज जौ का भाव ५०-५१ रुपया है। जहां आज से दो-तीन महीने पहले गेहूं का भाव जो हमने कन्ट्रोल कर रखा है और राजस्थान अपने प्रकार की एक ही स्टेट है कि जिसने मेग्जिमम भावों की गेहूँ के बारे में घोषणा की थी और उस घोषणा के बावजूद जो भाव पहले ५३ से ६४ रुपये क्विंटल तक रखे थे वे अभी भी इसी प्रकार से चल रहे हैं और गेहूं की अवेलिबिलिटी में भी पिछले आज से महीने २० रोज पहले कुछ इलाकों में, जिसको लोकल व्हीट कहते हैं उसकी काफी दिक्कत थी, अब काफी मण्डियों में, सिवाय एक दो

Page No 56

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जगह को छोड़कर, जहां व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया नहीं हैं...

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कोटा व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहां पर अवेलेबल नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सारे राजस्थान का गेहूं मंत्री महोदय के घर में है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप क्या मेरे साथ चलने का कष्ट करेंगे ? जयपुर के बाजार में कितना गेहूँ मिलता है; अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रैक्टीकल प्रपोजल रखता हूं। आप भाषण समाप्त करके यहां की धानमण्डी में चलें और मुझे एक मन गेहूं दिला दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं धानमण्डी में ही रहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका घर ही धानमण्डी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : चने का भाव जो दो–तीन महीने पहले ८८ और ६१ रुपए क्विंटल पर चल रहा था...

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर) : आप एक कृषि मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं या सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं ? अगर आप मंत्री की हैसियत से बोलते हैं तो जिम्मेदारी के साथ बोलें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सदस्य और मंत्री की जिम्मेदारी में कोई फर्क नहीं समझता।

श्री मुरलीधर व्यास : एक साधारण सदस्य की बात अलग है। यदि आप मंत्री की हैसियत से बोलते हैं तो उस तरह से कहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यदि सारी बातें कहने लगूंगा तो भाषण बहुत लम्बा होगा।

श्री अध्यक्ष : आप लम्बा नहीं कहे।

श्री मुरलीधर व्यास : यह गेहूं का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आप एक सेर तो दिला दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो मैं भाव बता रहा हूँ। सारी बातों पर मैं धीरे धीरे आ रहा हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : अध्यक्ष, महोदय, आपने एक सेर गेहूं दिलाने की बात कही है, मैं इनको पांच–सात दूकानें घूमाकर ५–७ सेर गेहूं दिला दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लन्च टाइम में गेहूँ की बात करते हैं, तो भूख तो लगेगी ही।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जो कहते है कि मंहगाई में अन्तर नहीं आया है उनकी जानकारी के लिए कह रहा हूं कि चने का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

भाव दो-तीन महीने पहले जहां ८८ और ९१ रुपये क्विंटल के बीच में चल रहा था वह आज पुराना चना ५५ और ६५ रुपये क्विंटल के बीच में चल रहा है और नया चना का भाव ६८ रुपये क्विंटल है। बाजरे का भाव दो तीन महीने पहले ६४ रुपये क्विंटल था वह अब ५०-५१ पर चल रहा है। ज्वार का भाव ६१ रुपये क्विंटल था वह आज ४३-४४ रुपये क्विंटल पर चल रहा है। जो मक्का आज से ३-४ महीने पहले ५२ रुपये क्विंटल था वह आज ४२ रुपये क्विंटल में चल रहा है। जो सरसों का भाव २०५ रुपये क्विंटल था वह आज १०५।१०० रुपये क्विंटल में विक रही है। जो तिल १९१ रुपये क्विंटल दो तीन महीने पहले थे वह आज १२५ रुपये क्विंटल बिक रही है। मूंगफली के तेल के पीपे के भाव जहां पहले ४३ रुपये थे वे आज ३४ रुपये रह गये हैं। जिस तिल्ली के पीपे का भाव ४५ रुपये था वह आज ३९ रुपये का पीपा रह गया है। इसके साथ ही जीरे और धनिये के भावों में भी काफी फर्क पड़ा है। जो चने का भाव......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुर्गीमुसल्लम का भाव और बता दो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अण्डे और मुर्गियों के भाव भी बता दो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य गंभीरता का वातावरण रखें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहूंगा कि चीनी और खांडसारी का भाव जहां पहले २४० और २७५ रुपये क्विंटल के थे उसके भाव आज १५० और १७५ रुपये के बीच में हैं। चीनी का ब्लैक मार्केट में जो भाव चलता था वह २५० रुपये का था वे आज बाजार के अन्दर १७५ रुपये क्विंटल के थे......

श्री मुरलीधर व्यास : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ब्लैक मार्केट चलता था क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जरा सुन तो लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसके असर में कोई कमी नहीं कर सकते। मुझे मेरी बात को कहने का हक है और मैं कहूंगा...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर......

श्री अध्यक्ष : कोई क्लेरफिकेशन की आवश्यकता नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे इन भावों से आप देखेंगे कि पिछले दो-तीन महीनों में भावों में कितना उतार आया है उसका अन्दाजा लगायें। माननीय सदस्य जो यह कहते हैं कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार हिन्दुस्तान के अन्दर बढ़ते हुए भावों को रोकने में नाकामयाब हुई है उसकी वजह

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से मैंने ये भाव सदन के माननीय सदस्यों के लिए रखे हैं। स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। जिन नीतियों को इस सदन में और हम लोगों के मानने के लिए स्वीकृति दी उन नीतियों के ऊपर चलकर जिन नीतियों के जरिये जो कुछ हमने आवागमनों के साधनों पर प्रतिबंध लगाकर जो जोन्स की व्यवस्था थी उसको देश में माना और स्वीकार किया जिसकी वजह से जो रबी की फसल आ रही है उनके आसार भी हमारे सामने हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दो तीन महीनों में अमेरिका में स्ट्राइक की वजह से जो इम्पोर्ट का माल आ रहा था उसमें कमी हुई। हालांकि भारत सरकार ने दूसरे राज्यों को तुरन्त कार्यवाही की जा कर गेहूं और चावल में राज्य की गुंजाइश थी उसको करने की कोशिश की और स्थिति इस प्रकार की नहीं बनी जिसके ऊपर हम काबू नहीं पा सके हों। फिर भी आने वाले २०-२५ रोज में अमेरिका से गेहूं के जहाज आ रहे हैं उनको ध्यान में रख और हिन्दुस्तान की रबी की फसल के आसार हिन्दुस्तान की राज्य सरकारों ने दिये हैं और जो स्थिति हमारे प्रान्त की भी है इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखें तो मैं कह सकता हूं कि पिछले दो तीन महीनों में गेहूं की अवेलेबिलिटी के प्रश्न पर चिन्ता बता रहे थे-हो सकता है बीकानेर में कुछ दिनों के लिए चिन्ता का विषय रहा हो और मुझे जानकारी भी है कि जिस समय इम्पोर्ट का कोटा भी कुछ कम हुआ हमने कुछ आटा देकर और कुछ इधर उधर से लाकर उस स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की और मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जिस खाद्यान्न की नीति के बारे आप काफी आलोचक रहे हैं और आपने यह भी कहा है कि इसमें जल्दी हेर फेर करने से भी राजस्थान में मंहगाई को हम नहीं रोक सके हैं और राजस्थान में खाद्यान्न की स्थिति को कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं मैं इतना ही अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान उन राज्यों में से है चाहे भावों के दृष्टिकोण से लीजिए, चाहे राजस्थान में चीजों की अवेलेबिलिटी के दृष्टिकोण से लें तो हिन्दुस्तान के और दूसरे इलकों की हालत है जहां आप भी कभी कभी जाते हैं और आपके पास भी कई प्रकार के समाचार मिलते रहते हैं उनका मिलान करें तो मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की स्थिति हिन्दुस्तान के अन्य राज्य के मुकाबिले में काफी अच्छी रही है। मैं उसके बारे में अकेला क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूं। पुलिस ने और खाद्यान्न विभाग के लोगों ने जिस कर्त्तव्यनिष्ठा से काम किया यह इन सारी बातों का परिणाम है कि राजस्थान के हालात दूसरे राज्यों के मुकाबिले में काफी अच्छे थे, आज भी ठीक है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार के ट्रेंड्स चल रहे हैं मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं और राजस्थान के लोगों के सामने यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में या एक दो महीने के बाद हमारी स्थिति में और भी सुधार होगा। हमारे भावों में और भी ज्यादा उतार होगा और जो हमने नीति बनाई है उसके अनुसार राजस्थान सरकार को ज्यादातर माल खरीदना पड़ेगा और किसानों की जिम्मेदारी हमने ली है कि उनके भाव बेसिक भावों से नीचे नहीं जाने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दिये जायेंगे और राजस्थान सरकार को ज्यादातर खाद्यान्न के रूप में खरीदना पड़ेगा। उसकी तैयारी है। राजस्थान सरकार चाहे उस केन्द्र की उस चीज के जरिये व्यवस्था करे या स्वयं व्यवस्था करे, लेकिन राजस्थान के उस माल को अपने पास खरीदेगी और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इम्पोर्ट्स के जरिये जो कुछ स्टाक है उनसे और और गोदामों को भरा जाकर आने वाले एक दो साल स्थिति और काबू से बाहर न हो इस प्रकार की व्यवस्था भारत सरकार भी रखने की कोशिश करेगी और राजस्थान सरकार भी इन बातों को रखने की कोशिश करेगी। इसलिए यह कहना कि महंगाई पर काबू नहीं पा सके, मैं नहीं कहता कि आप आज के वातावरण में कितनी चीज को महंगाई मानते हैं उसके बारे में कोई माननीय सदस्य खड़े होकर बोले तो सही कि इस चीज के ऊपर होगई तो महंगाई मानते हैं और इस चीज के नीचे हो गई तो सस्ती मानते हैं। इस तरह की कोई रचनात्मक बात तो रखें। जैसे कि 'मैंने निवेदन किया और इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने कई बार रखा है कि जो महंगाई की बात को लेकर चलते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि २-३ साल पहले जो भाव थे उन्हीं भावों पर सारी आर्थिक व्यवस्था टिक सकेगी जब कि हम लगातार मनी को पम्प आउट करते जा रहे हैं, एक इकोनोमी का ऐसा वातावरण करते जा रहे हैं अपने कामों के जरिये, अध्यक्ष महोदय, कि दो-तीन वर्ष पहले जो कुछ भाव थे उस पर स्टेबल रह सकें, बल्कि यह जरूरी मानकर चलता हूं कि बदलते हुए हालात में किस चीज से ज्यादा बढ़ी हुई चीज को महंगी मानते हैं, और जो कुछ भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिनिमम प्राइसेज़ की गारन्टी दी है, मेग्ज़िमम प्राइसेस मुकर्रर की हैं उसके बीच में ट्रेड के फ्लक्चुएशन को किसी प्रकार से ज्यादा महंगा नहीं मानेंगे, इस प्रश्न को अपने देश के लोगों को तय करना है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक बात आप और बता दें कि इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार और भारत सरकार की ऐसी नीति है प्राइसेज़ की स्टेबिलिटी को मेन्टेन नहीं किया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपसे कहा है कि प्राइसेज की स्टेबिलिटी मेन्टेन करने के लिए ही हम यह कर रहे हैं, प्राइस वगैरह की स्टेबिलिटी को मेन्टेन करने की दिशा में ही ये सारे कदम हैं। प्राइस की स्टेबिलिटी हो और ज्यादा एवेलिबिलिटी हो। यह चीज नहीं हो तो नीति के मायने कोई नहीं हैं, लेकिन स्टेबल प्राइसेज़ क्या हों, उसका विवरण मैंने पहले दिया। एक तरफ किसान की मिनिमम प्राइसेज़ हैं उसके बाद गेहूं की मेग्जीमम प्राईसेज़ फिक्स की हैं हमने राजस्थान में हालांकि दूसरे प्रान्तों ने मेग्जीमम प्राइसेज़ की व्यवस्था को अंगीकार नहीं किया है। भारत सरकार भी इस प्रकार विचार कर रही है उस पर विचार करने के लिए जो एग्रीकल्चरल प्राइसेज़ कमीशन बैठा है वह इस बात को सोच रहा है और विचार कर रहा है, और वे प्राइसेज़ मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जो आज से डेढ़-दो साल पहले थीं वे प्राइसेज़ ही

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वापिस आयें तब महंगीवाड़ा नहीं कहेंगे, इस बात को सदन लेकर नहीं चल सकता है और न आज के अर्थ के बढ़े हुये सारे व्यय को, खर्चे को देखते हुए यह सम्भव है और न इस बात को करना चाहते हैं और करी भी तो वह आर्टीफिशियल बात होगी और उससे किसी न किसी वर्ग को अननेसेसरी पिन्च करने की कोशिश करेंगे। आज जो इकोनोमिक फैक्टर्स हैं उसके दृष्टिकोण से सारी बातों का नाप तोल करते हैं तो निश्चित तौर से जो महंगाई तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही थी और उसको कन्ट्रोल करने की अवस्था में नहीं थे उसमें निश्चित सुधार हुआ है। उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जायेगा और मर्ज को रोकने में हम कामयाब हो चुके हैं और अब प्राइसेज में स्टेबिलिटी रहे ताकि चौथी पंचवर्षीय योजना का पहला साल जो कि अगले साल से शुरू होगा उसमें हम घुसें तो हम एक निश्चित व्यवस्था के जरिये हम उसमें प्रवेश करें और ठीक तौर से हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना को जमा कर चल सकें।

जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश में प्रकृति का बहुत बड़ा योग है और इन सारी चीजों के अन्दर जैसा कि खास तौर से डूंगरपुर से आने वाले महारावल साहब ने राजस्थान के प्राइस इन्डेक्स को लेकर कुछ बातें कहीं। ५६–६० से लेकर ६४ तक की प्राइसेज के अन्दर अन्दर बतलाया। खास तौर से जैसा कि मैंने कहा कि ६१–६२ का साल जो राजस्थान के लिए था वह खाद्यान्न के उत्पादन के दृष्टिकोण से राजस्थान के अन्दर जो सीजनल अवस्था रही उसके दृष्टिकोण से सबसे अच्छा उत्पादन का वर्ष रहा है जिसके अन्दर ५४ लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। पहले के दो–तीन वर्षों को पकड़ लिया और फिर उसके बाद के २–३ वर्षों को पकड़ लिया और कहने लगे कि पहले से उत्पादन घटा है और बाद में भी घटा है। यह ठीक बात है कि राजस्थान के अन्दर पैदावार के अन्दर पिछले २–३ वर्ष काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहे हैं, लेकिन राजस्थान के कृषि विभाग की निष्क्रियता या दूसरे फैक्टर्स की वजह से रहा हो, ऐसी बात नहीं है। वे कुदरतन फैक्टर्स थे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप ६०–६१ से लगाकर अन्त के चार वर्षों का प्रोडक्शन क्या रहा है, यह बता सकेंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं रोज ही बताता हूं। आप यहां नहीं होते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप दुबारा बता दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर भी बता दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रोज बदलते हुये आंकड़े दिया करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बदलते हुये आंकड़े नहीं देता हूं लेकिन आपका दिमाग बदलता रहता है।

श्री मुरलीधर व्यास : रोज बताते हैं तो आपको याद हो गये होंगे। वे क्या आंकड़ें हैं वे आपको अच्छी तरह से याद होंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले एक एक साल से बताना शुरू कर दूं। राजस्थान में पिछले वर्ष टोटल उत्पादन ३८.०७ लाख टन। राजस्थान में उससे पहले के वर्ष का उत्पादन ४३ लाख टन और उसके पहले वर्ष का उत्पादन ४७ लाख टन।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये तीनों ही आंकड़ गलत हैं। यह डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर...

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने हजारों के फीगर्स नहीं दिये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लाखों में भी गलत हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : बताइये, क्या गलती है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने 'रीसेन्ट डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान' एक आर्टीकल लिखा है उसके जो फीगर्स हैं उनको जरा सुनिये और नोट करिये और याद रखें। ६१-६२ में ५४.८० लाख टन है जो कि आपने अभी ४७ लाख बताया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ६१-६२ का मैं ५४ लाख टन पहले कह चुका हूं। अगर आपके पास है तो बैठ जाइये। अच्छा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने तो खड़े खड़े ही ७ लाख घटा दिये और ७लाख बढ़ा दिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : और भी बहुत बातें कहनी हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें उन्होंने कहा कि इन्डेक्स नम्बर में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आया है वह उतार-चढ़ाव राजस्थान में सीजन्स के वेरियेशन्स का परिणाम है। जिन वर्षों के अन्दर अच्छी बरसात है, अच्छा सीजन है, जहां कुओं में ज्यादा पानी है माइनर इर्रिगेशन के टैंक्स में ज्यादा पानी है, बड़ी नहरों में पानी आने की गुन्जाइश है, उस साल वातावरण प्रोडक्शन का अच्छा रहता है और ज्यादा उत्पादन होता है। इसी तरह से जिन वर्षों में बरसात की कमी हो, कुओं का पानी घट गया हो, इर्रिगेशन के टैंक्स नहीं भरते हैं तो उत्पादन घट जाता है। इसलिये इस बात को नहीं मानता हूं कि नीतियों के उतार-चढ़ाव के कारण से, राजस्थान सरकार की तरफ से जो इन पुट किया जाता है उनमें कमी होने की वजह से प्रोडक्शन में फर्क आता है। इर्रिगेशन के दृष्टिकोण से सुधरे हुये बीज की दृष्टिकोण से, राज्य में इन्सेक्टीसाइड्स की व्यवस्था हो रही है, उसका रकबा लगातार बढ़ रहा है, केमिकल फर्टीलाइजर्स की खपत को देखें तो पिछले साल नाइट्रोजन ४५ लाख और हाइ-ड्रोजन का १५ लाख टन के लगभग है। वह लगातार बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तो, माननीय अध्यक्ष, खाद्यान्न के दृष्टिकोण से उत्पादन के बारे में जो कुछ कहा गया कि उतार-चढ़ाव है तो वह उतार-चढ़ाव सीज़न के वेरियेशन्स के कारण से आया है। उसके बारे में चिन्ता व्यक्त की और शायद इस बात को मानकर चलें कि उत्पादन गिरता जा रहा है या प्रगति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं इस कन्क्लूज़न को ड्रॉ करना ठीक नहीं होगा।

इसके साथ साथ मैं खास तौर से···

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कीमतों के बारे में जो आपने फरमाया उसका मैं क्लेरिफिकेशन चाहता हूं जो कीमतें बढ़ीं वे सरकार की पोलिसी के कारण बढ़ी और आज जो कीमतें गिरी हैं जैसा आपने तेलों के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में बताया वे आपकी पालिसी के कारण गिरी हैं या जखीरेबाज आज उन चीजों को मार्केट में ला रहे हैं इसकी वजह से कीमतें गिरी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे माल भी आज बाजार में ला रहे हैं तो सरकार की नीतियों की वजह से ला रहे हैं। सरकार के एक्शन का परिणाम है कि जखीरेबाज ला रहे हैं। वे रोके बैठे थे क्यों बैठे थे इस सबको आप एनेलाइज कर लें लेकिन जो परिणाम राज्य की नीतियों की वजह से आ रहा है वह चाहे राज्य सरकार की नीति के कारण हो चाहे भारत सरकार की नीतियों के कारण हो लेकिन वह परिणाम आपके सामने आ रहा है। इसलिए खाद्यान्न के बारे में यह कहना कि ऐसे समय में जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, राज्य कर्मचारियों को हमने बहुत कम दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सीमित साधन हैं उनके अनुसार हमने दिया है। एक तरफ तो कोई साधन बढ़ता नहीं है, सीमित है फिर भी राज्य कर्मचारियों को देने की व्यवस्था की जाती है, उससे सदन के माननीय सदस्यों को सन्तोष नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि वित्त मंत्रीजी ने ये शब्द कह दिए इसलिए यह वातावरण हो जिससे वे कुछ कदम उठाने वाले हैं। मैं माननीय सदस्यों को आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों को पिछले दिनों में जो महंगाई के समय दिया, जो कुछ दिया ४०० से नीचे पाने वालों को उनके स्टेण्डर्ड का ख्याल रख कर दिया। ऐसा नहीं कह सकते कि २०० और ४०० के बीच पाने वालों को कुछ मदद करने की जरूरत न हो। हमारी जो व्यवस्था है उसमें यह कहकर नहीं चल सकते कि इतना ही पैसा दें तब उचित होगा, ऐसी व्यवस्था हमारी नहीं है। जो कुछ हमारे साधन थे उसके अनुसार हमने उनको देने की कोशिश की। मैं राज्य कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं कि वे प्रान्त के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं उनको सोचना चाहिए कि वे ज्यादा की आशा करते हैं तो हमारे पास इतने साधन कहां हैं। राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को संतुष्ट करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन राज्य सरकार का यह भी कर्त्तव्य है कि जिनकी उनसे ज्यादा कमजोर हालत है जो उनके मुकाबले में ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं

Page No 63

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उनका हालत में भी उतना ही सुधार हो जितना कि राज्य कर्मचारियों की हालत में। तो इन सारी बातों को लेकर उनके बेसिस पर सारे हालात पर सोचना पड़ेगा। वे जो कुछ कहें इस कारण नहीं कहें कि उससे उग्रता फैले। इस प्रकार का वातावरण उनमें बनता है तो उसके परिणाम आते हैं, काम ठीक तरह से नहीं होता है और असन्तोष की भावना बढ़ती है। हम भी चाहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे लेकिन सीमित साधनों को न देखकर वे इतना विपरीत रुख न ले लें, इस प्रकार का रास्ता न अपनालें कि जिसके जरिए जो कुछ होने जा रहा है उसमें कमी उठानी पड़े। मैं राज्य कर्मचारियों से आपकी मार्फत अपील करने के बाद निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो फैसला किया है वह उसके सामर्थ्य के कारण किया है। यदि लोगों के बहकावे में आकर या गलतफहमियों में आकर कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो राज्य सरकार को भी अपने दृष्टिकोण से कदम उठाना पड़ेगा।

महंगाई और इन बातों पर कहने के बाद मैं अब शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं।

इस सदन में चर्चायें हुई, इस बात पर जोर दिया गया कि राजस्थान में कई स्कूलें खोली जानी चाहिए, हाई स्कूलें और मिडिल स्कूलें खोली जानी चाहिए। सदन में ये भी चर्चायें चलती हैं कि हमारे यहां शिक्षण इन्सटीट्यूशन्स का विकास हुआ, लड़कों और लड़कियों का विकास हुआ है लेकिन स्टेण्डर्ड में कमी होती जा रही है, आप वही दृष्टिकोण रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बजट में जो कुछ व्यवस्था की है उसका अध्ययन किया हो तो एहसास मिला होगा कि वह बढ़ा दी है। जो लोग यह कहते हैं कि राजस्थान में शिक्षा के लिये कुछ नहीं किया उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस राजस्थान में सन् ५१-५२ में १ करोड़ ४८ लाख का खर्चा शिक्षा पर होता था उसी शिक्षा पर राजस्थान ने १५।। करोड़ रुपए का खर्चा पिछली साल में किया है। इस राजस्थान में जहां पहले ३५०० प्राइमरी स्कूलें थी वहां अब २३।। हजार प्राइमरी स्कूलें कुल मिलाकर हैं। जहां पहले ६०–७० मिडल स्कूलें थी वहां कुल मिलाकर १७०० मिडल स्कूलें हैं। जिस राजस्थान में आज से १०–१२ साल पहले गिनती की २५–३० हाई स्कूलें थी...

श्री भैरोंसिंह : मिडल स्कूलों और हाई स्कूलों की गिनती आपने कहां से बताई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो अन्दाज है...

श्री भैरोंसिंह : क्या आपका मतलब यह है कि राजस्थान बनने से पहले ५०–६० मिडल स्कूलें ही थीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, आप फिर गिनती कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मिडल स्कूलों की संख्या ६०० कही है, हाई स्कूलों की संख्या ५०-६० बताई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इस तरह कह दूं कि राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। लड़कों के नम्बर में, लड़कियों के नम्बर, में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

शिक्षण संस्थाओं के नम्बर में विस्तार हुआ है और खर्चे के लिहाज से भी काफी फैलाव और प्रगति हुई है । लेकिन जहां तक स्टेन्डर्ड का सवाल है, माननीय सदस्यों को चिन्ता रही है और चिन्ता होना स्वाभाविक है । मिडल स्कूलों और हाई स्कूलों का विस्तार करने की मंशा है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पास सीमित साधन हैं और उनके जरिये हम कुछ बातों को पूरा करना चाहते हैं तो प्रायोरिटीज को कायम करना पड़ेगा । मेरा एक मानस बना है और वह मानस यह है अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी स्कूलों के लिये जिन नये टीचर्स की व्यवस्था करने की आवश्यकता रहेगी वहां लड़कों के नंबर के दृष्टिकोण से उनकी व्यवस्था अक्षुण्ण रखी जाय । बाकी हाई स्कूल्स और मिडल स्कूल्स की नयी संस्थाएं खोलने के बजाय हमको यह निर्णय करना चाहिये, वह किया है, राजस्थान में जैसा पहले कहा है कुल ७२५ हाई स्कूलें हैं उनमें से ५५० हाई स्कूलें गांवों में हैं उनमें से जो विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं इस प्रकार निकलते हैं कि जिनके मानस का विकास जिस दृष्टिकोण से होना चाहिये, जिन लाइन्स का चुनाव होना चाहिये उनकी व्यवस्था गांवों में नहीं होने से उनका दृष्टिकोण नहीं बन सकता जो एक मैट्रिक पास विद्यार्थी का बनना चाहिये इसलिये मैं समझता हूं ऐसे गांवों के हाई स्कूलों के पास १०-२० माइल में, उन इलाकों को छोड़ दीजिये जो बैकवर्ड हैं जहां एक पंचायत समिति के पीछे एक भी हाई स्कूल नहीं है या डेजर्ट इलाका जहां ३०-४० मील में हाई स्कूल नहीं हैं, उनके लिये सोचा जाना चाहिये । इस साल नहीं तो आने वाली चौथी योजना में हमारे पास फंड हो तो उन गांवों के पास होस्टल्स की व्यवस्था करनी चाहिये (विराम) जहां आस पास के लड़के आकर रह सकें, रहने का वातावरण बने, कुछ नेशनेलिज्म और दूसरे मामलों पर सोचने का दायरा बने । जो आज संकुचित दायरे में रहते हैं आज उस दायरे से निकलने की व्यवस्था नहीं है, उन पर कंट्रोल नहीं है ऐसे लड़कों के लिये होस्टल्स की व्यवस्था होनी चाहिये जिनमें कम से कम १०० लड़के रह सकें । इन स्कूलों में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स का विस्तार किया जाय, एनीमल हसबेन्डरी की व्यवस्था की जाय, एग्रीकल्चर की ओर काम करने का उनका दिमाग बन सके । हाथ पांव से श्रम करने की ओर उनकी रुचि बढ़ सके ऐसे सब्जेक्ट्स जोड़े जाने चाहिये । इसके साथ ही साइन्स या विज्ञान की पढ़ाई जिनमें मैथेमेटिक्स और बायोलोजी जैसे सब्जेक्ट्स की सुविधा भी गांवों के लड़कों को मिल सके, विज्ञान की प्रगति करने में उनका सहयोग मिल सके, सही प्रकार के टीचर्स, लेबोरेटरीज, इन्स्टूमेन्ट्स की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि उनको इन सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने का मौका देकर आगे बढ़ावें, किन्तु जिन क्षेत्रों में कमी है, खास तौर से इलेक्ट्रिसिटी की प्रगति के लिये इलेक्ट्रिशियन्स की, मैकेनिक्स इन सबके लिए पाली टेक्निक में आगे पढ़ने की गुंजायश होनी चाहिए । इसके साथ ही राजस्थान के अन्दर सात सौ, आठ सौ डाक्टर्स की कमी है । गांव के लड़कों को इस तरह की शिक्षा मिलने की सुविधा मिल सके इसकी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

व्यवस्था होनी चाहिए। आज हो क्या रहा है, जो शहरों के लड़के पढ़ कर निकलते हैं वे आज गांवों की ओर जाना नहीं चाहते। इसलिए गांव के लड़कों को ऐसा बेस मिल सके जो आज नहीं मिलता है, इसकी व्य-वस्था करके जो आज इमबेलेन्स हैं शिक्षा के अन्दर और जो देश के अन्दर स्थिति चल रही है उसको करेक्ट करने की दृष्टि से शिक्षा की नीति के अन्दर एक नया मोड़ देने का मेरा मानस बन रहा है। अगर साथियों का इसमें सहयोग मिला और इस सदन के सदस्यों का सहयोग मिला तो अवश्य नया मोड़ दे सकेंगे। मैं सोचता हूं, इसे सदन के माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे। तो आज जो माननीय सदस्यों के ऊपर शिक्षा के फैलाव के दृष्टिकोण से प्रेशर आते हैं, जब वे कॉन्स्टीट्यूएन्सीज़ में जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर आते हैं कि गांव में मिडल स्कूल खुलवा दो, गांव के अन्दर हाई स्कूल खुलवा दो-और आप लोगों को जो उन प्रेशर्स को उठाना पड़ता है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आप सब माननीय सदस्यों को उस प्रेशर को मीट करना पड़ेगा और लोगों को यह बताना पड़ेगा कि शिक्षा के स्टेन्डर्ड को देखते हुए और जनशक्ति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे राज्य के अन्दर एक विशेष बेस बनाना चाहते हैं जिससे कि गांव के विद्या-र्थियों को मौका और सुविधा मिले और इस बात को पूरा करने के लिए हम खर्च होने वाली राशि को इन इन मदों में रखना चाहते हैं। इस प्रकार से जो पच्चीस-तीस लाख की मद है एक्सपेंशन के लिए, उसको मैं समझता हूँ कि बजट में इन प्रावधानों के लिए रखना होगा कि पचास होस्टल बने, साइंस क्लासेज़ की व्यवस्था हो और साइंस क्लासेज़ के लिए इक्विपमेंट और लेबोरेटरी की व्यवस्था हो और गांव के लड़कों को नये प्रकार का बेसमिल सके-इस प्रकार की व्यवस्था हो......

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): ओन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हायर सैकन्ड्री स्कूल और जूनियर हायर सैकन्डरी स्कूल सिस्टम की व्यवस्था कितने साल में कर देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा: जैसा कि मेरा सुझाव है, अगर स्कूल्स के फैलाव के बारे में ज्यादा जोर नहीं दें-वैसे मैंने कहा कि डिफिकल्ट एरिया के सवाल को आप छोड़ दें इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात की चिन्ता न करें, जिस एरिया में दूर दूर एरिया तक स्कूल नहीं हैं-वहां स्कूल की व्यवस्था की जायगी। अगर मेरी इस बात को मान लें तो आने वाले तीन साल के अन्दर राजस्थान में सब जगह गांवों में साइंस की हम व्यवस्था कर सकेंगे। अगर सदन के माननीय सदस्य मेरी इस बात को मानें......

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): बिल्कुल तैयार हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं सोचता हूँ कि यह काफी अच्छा प्रोग्राम है। जो हालत आज हो रही है और परेशानी हो रही है,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जो आज प्रेशर पड़ता है कि यहां हाई स्कूल खुलना चाहिए, यहां मिडिल स्कूल खुलना चाहिए, यहां स्कूल को रेज करें–ये बातें आती हैं और जो लड़के शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और इम्तिहान पास कर लेते हैं उनके मां बाप तंग करते हैं कि इसको नौकरी में लगायें और अगर क्लर्क की नौकरी में नहीं लगायें तो इसको चपरासी बनवा दें। इस कारण से घरों में भी संघर्ष होता है क्योंकि माता पिता लड़के की शिक्षा पर दस बारह साल में चार पांच हजार रुपया खर्च करते हैं और उससे कुछ आशायें करते हैं। जब वह पूरा नहीं हो पाता है तो लड़का भी निराश होता है और माता पिता भी निराश होते हैं। इसलिए इस बात को सोच कर कोई अच्छा रास्ता निकालना और भी जरूरी है–अपने देश की दृष्टि से, प्रान्त की दृष्टि से और घर की कलह को मिटाने की दृष्टि से और रास्ता निकाल कर प्रयत्न करना चाहिए कि राजस्थान का अच्छा भविष्य बन सके......

श्री भैरोंसिंह : आप इस बात की कल्पना करते हैं कि प्रेशर हम पर आने लग गया है, तो आप क्या अनुमान करते हैं कि इस साल कितने हाई स्कूल खुलेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक भी नहीं !

श्री भैरोंसिंह : उसके साथ ही प्रेशर खत्म हो जायगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक भी नहीं । इससे आपको भी आसानी हो जायगी और मुझे भी आसानी हो जायगी । रोज मेरे पास दस अर्जियां आती हैं। अब आप यह कह सकते हैं कि यह निर्णय ले लिया है...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): गये साल भी यह कहा था कि नहीं खोलेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, अब मैं खत्म करूं पांच–दस मिनट और ले लूं ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा !

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बड़ी बड़ी बातों का जवाब दे दिया है । एक–एक माननीय सदस्य की बात का जवाब मैं नहीं दे पाया हूं ।

श्री अध्यक्ष : अब छोटी छोटी बातों का जवाब दे दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको टाइम मिलना चाहिए । इतना सारगर्भित भाषण सुनने का कम मौका मिलता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य ने हायर सैकन्ड्री और.........

श्री अध्यक्ष : अब इस हायर सैकन्ड्री को छोड़िये और बातों में चलिये ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : हमको समझने दीजिये, साहब । हम नहीं समझते हैं तो हमको समझने दीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर खास तौर पर जो सिंचाई के बारे में प्रश्न उठाये, विशेष रूप से राजस्थान नहर के बारे में, इन दो पहलुओं पर माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला—एक तो इस बारे में चिन्ता व्यक्त की गई, राजस्थान नहर के बारे में, जो बड़ी योजनाएं, कोलोनाइजेशन का सिलसिला पूरा करने के लिए, रिहायेश का सिलसिला पूरा करने के लिए काफी बड़ी धनराशि की व्यवस्था हमको योजनाओं में करनी पड़ती है, इसलिए प्लान सीलिंग के अन्दर दूसरी योजनाओं पर असर पड़ता है, अब इसे भारत सरकार ले रही है, यह बहुत अच्छा काम वह कर रही है। इस बारे में सदन के सदस्यों ने भी खुशी जाहिर की है। लेकिन साथ ही साथ यह चिन्ता भी जाहिर की कि इस व्यवस्था में ऐसा न हो जाय कि जो जमीन राजस्थान के भूमिहीनों को मिल सकती थी, जो राजस्थान के लोगों को जमीन से लाभ हो सकता था—इस सबके बारे में जिस प्रकार की व्यवस्था होने जा रही है उसमें कमियां न रह जायं और कहीं राजस्थान के लोगों को नुकसान न उठाना पड़े। अध्यक्ष महोदय, इन बातों के सम्बन्ध में अभी चर्चायें पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन जिस लेवल पर बातचीत चल रही है, उससे मैं समझता हूँ कि सदन के सदस्यों को इस प्रकार की चिन्तायें अपने दिमाग में बनाने की और बना कर चलने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार की व्यवस्था के बारे में सोचा जा रहा है और जिस प्रकार व्यवस्था के बारे में बातें हुई हैं—कोलोनाइजेशन की पॉलिसी को और दूसरे बड़े बड़े सवालों को उसके सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले एग्रीमेंट में जो व्यवस्था है, हम इस मौके पर इस बात के लिए ज्यादा प्रिकांशन ले रहे हैं कि जिस ऑथोरिटी का जिस प्रकार गठन होने जा रहा है, उसके सामने राजस्थान की बात को ठीक ढंग से रखा जा सके, सुना जा सके और इसके सम्बन्ध में व्यवस्था रखी जा सके। और मुझे वह स्वरूप नजर आ रहा है लेकिन जब तक व्यवस्था पूरी न हो जाय उसके बारे में ज्यादा न कहना ही उचित होगा। लेकिन इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है और जो चिंता आपके दिमाग में है, मैं कहना चाहता हूं कि आप उसे निकाल दें। हम चाहते है कि उस रेगिस्तानी इलाके में, उस जमीन पर जल्दी से जल्दी कोलोनाइजेशन हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और उसका फायदा राजस्थान को और हिन्दुस्तान को मिले। इस व्यवस्था के बारे में काफी तेजी से काम किया जाय। बड़े बड़े फार्म उस एरिया में बनाने का भारत सरकार ऑथोरिटी विचार रखती है। उस लैण्ड पर इमीजियेटली, जल्दी से जल्दी मेकेनाइजेशन के जरिये, लेवल करके वहां उपलब्ध पानी का उपयोग करके प्रोडक्शन बढ़ाया जाय, इसके लिये बड़े बड़े फार्मों की व्यवस्था हो और उन फार्म्स में राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा लोग लगें और उस फार्म में ज्यादा प्रोडक्शन हो, उस प्रोडक्शन में हमारा भी हिस्सा हो और उससे होने वाली आमदनी में भी हिस्सा हो इस प्रकार की सोशियो इकोनोमिक कन्डीशन्स नये पैमाने पर, नये दृष्टि से उस कोलोनाइजेशन में करने की व्यवस्था और ज्यादा से ज्यादा कोलोनाइजेशन के जरिये कैनाल वाटर का उपयोग होकर प्रोडक्शन को बढ़ाने की व्यवस्था इसके

(श्री नाथूराम मिर्धा)

द्वारा रखी जा रही है और बड़े लेवल पर बातचीत की जा रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान कैनाल के सिलसिले में कई स्थगन–प्रस्ताव आये और ध्यान खींचने के प्रस्ताव आये, और दूसरे प्रस्ताव आये हड़ताल के सिलसिले में.........

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल के बारे में आपने जिस चिन्ता का संकेत किया और बताया कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार के बीच में निर्णय पर पहुंचने के लिए बातचीत चल रही है । मैं समझता हूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें राजस्थान की बहबूदी का सवाल है, और जिस पर खर्च भी काफी हुआ है—इसके सम्बन्ध में जो भी अन्तिम निर्णय हो उससे पहले क्या सरकार इस सदन के सदस्यों को अपने कॉन्फीडेंस में नहीं लेना चाहेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सोचता हूं कि वक्त होगा तो जरूर लेंगे सदन तब तक चल रहा होगा,तो जरूर कॉन्फीडेंस में लेंगे । सदन को कॉन्फीडेंस में नहीं लेंगे तो जायेंगे कहां ! इसमें सदन से कोई बात छिपा कर बाला-बाला किया जाय–यह कभी मन्शा नहीं है और उचित भी नहीं है । और करे भी तो सरकार कॉन्फीडेंस खो देती है इसलिए सदन को विश्वास में लेकर चलना पड़ेगा ।

तो, मैं आपके जरिये मजदूरों के प्रश्न पर कह रहा था । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है और खेद भी है कि राजस्थान के इतने बड़े प्रोजेक्ट पर, इतने बड़े बांध पर सारा काम-काज छोड़कर इतने बड़े पैमाने पर लोग काम-काज बन्द कर दें । इसके अलावा झगड़ा भी कोई बड़ा नहीं है । जो उनकी चौदह मांगें हैं उनको अलग अलग आपके सामने और सदन के सदस्यों के सामने मैंने विश्लेषण किया था । सिवाय एक बात को छोड़कर, जो ये स्केल्स के अन्दर कुछ लोगों का फिक्सेशन नहीं हो रहा है, उनके लिए कहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत काम पूरा कर लिया है और कुछ बाकी है । उसके बावजूद हम लोगों को बिना नोटिस दिये इतने बड़े पैमाने पर लोग काम-काज छोड़कर बैठे जायं जिससे राज्य सरकार को इस प्लान को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितने वर्किंग अवर्स कम हो जाते हैं उतना ही देश को और प्रांत को नुकसान हो रहा है । और यह सब एक छोटी सी बात को लेकर कि जो फिक्सेशन एक ऑर्डर के मुताबिक होना चाहिए वह नहीं किया गया और उसमें कुछ बदलाव हो गया । वह भी एक फोरमैन के सम्बन्ध में है । फौरमैन के पहले अलग अलग नाम थे और वेतन में अन्तर था । अब उसमें व्यवस्था की है, वह यह है कि एक बहुत बड़ी ग्रेस में रख दिया है । उसके लिए सबने कहा कि इसमें फिक्स किया जाना चाहिए । अब यदि सबका करते हैं तो कुछ को जो तनख्वाह अभी मिलती है उससे ड्योढ़ी और दुगनी मिल जाती है । अब जो गलती रह गई है उसको हम ठीक करना चाहते हैं और आपसी बात-चीत में ऐसी व्यवस्था करना

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चाहते हैं जो हम कर सकते हैं जिससे मजदूरों को नुकसान न हो और जो फायदा किसी को मिलता है वह मिले । इस प्रकार को मन्शा राज्य की, विभाग की और सरकार की है । फिर भी क्योंकि वे लोग हड़ताल पर चले गये और उन्होंने इसे प्रेस्टिज का प्रश्न बना रखा है, मैं सोचता हूं कि इस बारे में जो प्रयत्न श्रम विभाग और यूनियनों के प्रतिनिधियों के चल रहे हैं उनका ठीक परिणाम आना चाहिए और उनको काम पर लगाना चाहिए । हम किसी प्रकार मजदूरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते न नुकसान करने की नीयत न पहले राज्य सरकार की थी और न अब है । एक छोटे प्रश्न पर जिस तरह की मात हुई इसमें खेद है । मैं चाहता हूं कि वे वहां पर तुरंत जाकर अपना काम करें ।

(२.०० म. प.)

श्री मुरलीधर व्यास : अभी ये लोग जो राजस्थान कैनाल पर काम करने वाले हैं और जो हड़ताल पर हैं उसकी जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की है या राजस्थान सरकार पर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कोई जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर नहीं डालना चाहता । यह नीति के सम्बन्ध में है । मैं यह कहूंगा यह हमारी नीतियों की मिस अन्डरस्टेंडिंग है । यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े काम पर लोग हड़ताल पर चल रहे हैं और इससे हमको काफी नुकसान हुआ । मैं यह चाहता हूँ कि एक अच्छा वातावरण हमारे श्रम विभाग और हमारी ओर से बने और मामला निपटे । एक बहुत मामूली झगड़ा रह गया है । इसको आप सभी माननीय सदस्य जानते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आपने उनके प्रतिनिधियों को दुबारा खुला कर बात चीत करली है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई भी ऐसी बात नहीं है । जो हम कर सकते हैं करने को तैयार हैं ।

एक माननीय सदस्य : आपने उनसे बातचीत कर ली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने उनसे बातचीत कर ली है और मेरे घर के दरवाजे हर वक्त उनके लिए खुले हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : श्रम विभाग और आपके विभाग के बीच समझौता हुआ उसको लागू करने के लिए है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसी में तो गलत फहमी हो रही है । वे लोग कहते हैं कि पहले का हुक्म है उसके...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके डिपार्टमेंट से इश्यू किये हुए चार हुक्मों की नकलें तो मेरे पास मौजूद हैं । मैं उनको जब भाषण दूंगा जिक्र करूंगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जब

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अपना भाषण दें उस समय बता दीजिये। जहां तक दोनों के पास्ट आॅर्डर एक और दूसरे हुक्म एक ही हैं, सिवाय इसके कि हमने फोरमैनों की कैटेगरीज़ अलग अलग बनाई हैं। तीन-चार कैटेगरीज़ बनाई हैं। पहले अलग अलग स्टेटों में अलग अलग ग्रेड के फोरमैन छोटे बड़े फोरमैन पहले स्टेटों में थे जो डिप्लोमा होलडर नहीं होते हुए भी एक्सपीरियेन्स के आधार पर फोरमैन बना दिये जाते थे। उनको किसी को १००) और किसी को २००) वेतन मिला करता था। हसने फोरमैन की कैटेगरीज़ अलग अलग कर दी। सीनियर फौरमैन और असिस्टेन्ट फोरमैन। इसमें उन लोगों को किसी को २५ पर्सेन्ट और किसी को ३० पर्सेन्ट तरक्की मिल जाती है और किसी को ४० पर्सेन्ट तक तरक्की मिलती है। मगर जैसा वे कहते हैं रखने से लोगों को २०० पर्सेन्ट की तरक्की हो जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके और उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था।

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्रीमेंट हुआ है। उसको हम आज भी मानने को तैयार हैं। मैं यह कहता हूं कि उसमें एनोमोलीज़ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके लिये भी कोई रास्ता निकल जायेगा। अगर कोई हल नहीं निकलेगा और रास्ता नहीं निकलेगा तो हम किसी पंच को भी इस मामले में मुकर्रर कर लेंगे और कुछ न कुछ नतीजा निकालेंगे। हमारी नीति कतई यह नहीं है कि मजदूरों को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाए या उनको किसी प्रकार का नुकसान हो। लेकिन जो नीति अपनाई गई है उससे इतने बड़े काम पर जो मजदूरों को काम के घन्टों का नुकसान हुआ है। वह अवश्य नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि मैंने इस पर काफी प्रकाश डाला है। और भी कई मसले हैं जो बाकी रह जाते हैं और कई माननीय सदस्यों को अभी बोलना है। इसके अलावा आपकी अनुमति है कि जल्दी खतम करना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को भी मौका मिलेगा। डिमान्ड पर आपने तीन दिन का समय दिया है। उस समय मैं और निवेदन करूंगा और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सही मुद्दे उठावें जिससे हमको भी जवाब देने में खुशी रहे। आप अच्छे प्रस्ताव रखेंगे, जिससे और भी बातों को कहने की आवश्यकता होगी, कहूंगा। अंत में मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के लिये मेरी एक कल्पना है और एक चित्र मेरे सामने है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार राजस्थान बिखरा हुआ है और जैसा कि हम इसको बनाना चाहते हैं और मेरी कल्पना है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सही कल्पना है उसको अपना लें तो २० वर्षों के बाद राजस्थान का इलाका दुनिया का सबसे बढ़िया इलाकों का मुकाबला करेगा और केलीफोनिया का मुकाबला करेगा। मैंने केलीफोनिया को देखा है और आप में से भी कई माननीय सदस्यों ने देखा होगा, हम हमारे राजस्थान को केलीफोर्निया बना सकते हैं। जब नर्बदा का पानी जालोर और बाड़मेर की तरफ जाएगा, ट्यूब वेल्स आदि खुदेंगे तो एनिमल हस्बेन्ड्री के साथ साथ इन्डस्ट्री का भी विकास काफी पैमाने पर होगा जिसको हम करना चाहते हैं जो स्कीम

Page No 71

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हमारे राजस्थान की चल रही है जैसे अंगूरों की खेती यहां पर बहुत अच्छी हो सकती है मैं कहूंगा कि राजस्थान में अंगूरों के लिये पोटेन्शियलिटी बहुत अच्छी है। हिन्दुस्तान के और दुनिया के दूसरे इलाकों को देख कर मैं आया हूं। फ्रान्स में भी मैंने देखा है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, लोगों के मुंह में अंगूर का नाम लेने से पानी आने लग गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे यहां पर अंगूरों का गुच्छा तैयार होते ही आपको जरूर दूंगा। इस राजस्थान के भविष्य के लिये मेरे सामने एक तस्वीर है वह मैंने आपके सामने रखी है। यहां पर अंगूरों के लिये हिन्दुस्तान के दूसरे स्थानों से ज्यादा पोटेन्शियलिटी है। जिसको मैं समझता हूं कि यह सदन निर्माण कर सकता है।

इसके अलावा लगातार इस सदन के जो जीवन-काल से सदस्य रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वे जिस प्रकार से यहां कभी कभी कुछ बातें बोल जाते हैं उसके लिये सचमुच मुझे दुःख होता है। कुछ बातें वे कहें, वे लोगों को सुनने वालों को अच्छी लग सकती है, अखबारों में हेडिंग बन कर आ जाने में बहुत अच्छी होती है। आखिर हम किसी खास पर्सोनेलिटी का दिग्दर्शन करना चाहते हैं, जिससे लोगों की निगाहों में वे नीचे गिर जावें या अपनी कुर्सियों से नीचे आ जावें तो इससे समस्या का सही हल नहीं हो सकता। प्रजातान्त्रिक तरीकों से छोटे बड़े लोग आते जाते रहते हैं और आते जाते रहेंगे। मगर ऐसे बुजर्गों को जो लगातार जीवन—काल से यहां पर बैठते हैं, ऐसी बातें कहते हैं, दूसरे तो यह समझें कि फिर आकर कर लेंगे। मगर जो जन्म-काल से बैठते हैं अगर ऐसी बातें करते हैं कि तवायफें तक ले जावें...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा छोटे मोटे सदस्य। हमें छोटे बनाते हैं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार की बातें न कहें, यह मेरी आपसे अपील है। आप मानें तो आपकी मर्जी है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी अपील को मैं मानने को तैयार हूं। आप भी मंत्रि-मंडल में अपने मंत्री मंडल के लोगों का आचरण सुधारने की चेष्टा करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह कहूंगा कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब दृष्टिकोण से पूर्ण हों। खामियें सभी में रहती हैं जो इन्सान होते हैं। मेरे में भी हैं, आप में भी हैं। परफेक्ट तो केवल ईश्वर है। इसलिये जितनी कमजोरियां इन्सान में होनी चाहिये होती हैं उसके

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लिये भी कहने का सुन्दर तरीका है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री मानसिंह महार : मैं तो महसूस करता हूं कि अब तो कौल साहब को अफीमचियों से टैक्स वसूल नहीं करना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अफीमचियों की बातें करने लग गये। यदि हम सब इसके लिये प्रयत्न करें तो राजस्थान को सुन्दर क्षेत्र बना सकते हैं। मैं अकेला दावा नहीं कर सकता। काने को काना कहें और अन्धे को अन्धा कहें तो ठीक है...

श्री भैरोंसिंह : कानों को काना ही कहा है। अन्धे को अन्धा ही कहा है।

श्री अध्यक्ष : काणे को काणा न कहें, अन्धे को काणा कहें।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं कह रहा था कि हम इस प्रान्त को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 'मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री विठ्ठलभाई !

श्री विठ्ठलभाई (बांसवाड़ा सु०) : अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण को पढ़ा, देखने से मालूम हुआ कि कुछ तो ऐसा दिखावटी फायदा व नुकसान उधर छोटे नौकरों के लिये जो आपने भाषण में बताया कि ५ रुपया वृद्धि की जाय। ५ रुपया पिछले साल का था, ५ रुपया इस साल का। अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक नहीं है, ५ रुपया वृद्धि करने में कोई खास बात नहीं है, लेकिन आज के युग में इस राजस्थान में छोटे नौकरों के लिये छोटी तनख्वाह वालों के लिये आज की इस मंहगाई को देखते हुए, इनके लिये ५ रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं कहूंगा अगर वित्त मंत्री महोदय चपरासी की जगह होते और इतनी छोटी सी तनख्वाह इनको मिलती और अपनी गृहस्थी की आवश्यकताओं को पूरा करते तो उन्हें मालूम होता कि किस तरह पूरा किया जाता है। इस मंहगाई में ५०-६० रुपया छोटे चपरासी को मिलता है, कॉन्स्टेबल को ६०-७० रुपया मिलता है, इन छोटी तनख्वाह पाने वालों के लिये अगर उनके घर में १० बाल बच्चे भी हो तो कपड़ों का भी पूरा नहीं हो सकता तनख्वाह के पीछे। हमें देखना होगा कि छोटे नौकरों के लिये पांच रुपयों की वृद्धि करना और लोगों को यह बताना कि हमने बहुत बड़ी उदारता छोटे नौकरों के लिये कर दी है, तनख्वाह बढ़ा दी है और उनका बहुत भला होने वाला है। अगर आप इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते तो इस को भी कम कर सकते हो। आप छोटे नौकरों की तनख्वाह नहीं बढ़ा सके, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ा सके और कहा कि जो मरते हैं मरते रहें, जो खाते हैं खाते रहें, सुनने वाला कोई नहीं शायद भगवान् भी नहीं है। खाद्य मंत्री जी ने कहा कि गलती करने वाले

(श्री विट्ठलभाई)

गलती करते हैं, भूखों मरने वाले मरते ही हैं, पर आपको सोचना पड़ेगा कि कब तक मरते रहेंगे। आज १८ साल हो गये कांग्रेस के राज को पिछड़ते हुए ही चले जा रहे हैं इन्सान, गांवों में जाकर देखें कि क्या हालत है वहां गरीबों की, आज भी गरीबों की झोंपड़ी थी जैसी की जैसी है और अमीरों के घर और अधिक लखपति बने हैं। जो लोग लखपति थे उनको आपने ठेके दिये, मोटरों की लाइनें दीं, बड़े बड़े ठेके उन लोगों को देकर आपने उन्हें लखपति बनाया और छोटे लोगों के लिये सहकारी समितियों का कानून बनाया कि पी.-डब्लू. डी. के ठेके सहकारी समितियों को देंगे, जंगलों के ठेके और दूसरे ठेके सहकारी समितियों को दिये जायं, पर सहकारी समिति के नाते किसी एक को भी ठेका नहीं दिया जा रहा है, न सहकारी समिति के नाते मोटर लाइन दी जा रही है, न ठेके दिये जा रहे हैं और न किसी को पनपाया जा रहा है। खाली कानून बना रखा है, दुनियां को बताने के लिये रख रखा है कि छोटे लोगों को आगे लाने के लिये कानून बना कर आगे ला रहे हैं, पर यह बिल्कुल गलत है। मैं नहीं मानता कि आगे ला रहे हैं, आज गरीबों को आगे बढ़ाने के लिये आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम समाजवाद ला रहे हैं पर मैं बताऊंगा कि हमारे बांसवाड़ा जिले में जिस समय पंचायतों के चुनाव हुए, उस समाजवाद की किस तरह की नीति आप सामने लाये हैं। सदन के सामने यह सब बताने का आज मुझे मौका मिला है, पहले समय नहीं मिला, आज मैं वे सब बातें रखूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): ट्रेज़री बैंचेज खाली पड़ी हैं, गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेन्ट कर रहा है?

श्री दिनेशराय डांगी (उप–मंत्री सिंचाई): मैं हूं।

श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा): हां, आप पक्के मिनिस्टर हो।

श्री विट्ठल: छोटे–मोटे सदस्य बोलते हैं तो उनकी नहीं सुनते, बड़ों की सुनते हैं।

सरकार कह रही है कि वह गरीबों को आगे ला रही है। मैं बताऊं किस तरह गरीबों को आगे ला रहे हैं। अभी पंचायतों के चुनाव हुए हमारे बांसवाड़ा जिले में जहां आदिवासी इलाका है, वहां पंचायतों के चुनावों में कम से कम कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी के २० पंच ज्यादा थे। पंचायत समितियों के चुनाव हुए तो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री हरिदेव जोशी वहां पड़े रहे, उन्होंने ऐसा खोटा रास्ता अपनाया कि पंचायत समिति के क्षेत्र में कैम्प बनाये, कैम्पों में कम से कम ५०० आदमियों के खाने–पीने की व्यवस्था की और ऊंची से ऊंची शराब जगमोहन, केसर कस्तूरी, गुलाब की बोतलों का इन्तजाम किया। इनसे नीचे वाली शराब को तो किसी ने पिया ही नहीं। जो शराब पीने वाले थे उनके लिये बोतलें छोड़ दीं और उनको कह दिया कि खूब शराब पीओ

(श्री विट्ठलभाई)

और खाओ-पिओ और मौज करो, वोट देना हो तो हमको दे देना, हमको वोट नहीं देना है तो यहीं बैठे रहो, पांच-पचास रुपये हम और दे देंगे, पर सोश्यलिस्ट पार्टी के सदस्य को वोट देने मत जाना।

जिला परिषद का चुनाव होता है, २४० वहां के वोटर हैं उनमें से १२१ वोट हमारे थे और ११६ कांग्रेस के थे......

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): यह कैसे मालूम हुआ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): जिसने जिसको ज्यादा पिलाया।

श्री विट्ठल भाई: एक वोट हमारा ज्यादा था लेकिन क्या होता है कि कांग्रेस की तरफ से यह किया गया कि कैसे इन वोटरों को चुराया जाय। ऐसा किया कि प्रतापपुर गढ़ी तहसील के ६ सरपंचों को बुलाया कि सहकारी समिति का रुपया बांट रहे हैं, इन्स्पेक्टर को भेजा, मैनेजर को भेजा और कहा कि बैंक से सहकारी समिति का रुपया दिला रहे हैं, सरपंच भी और सभापति भी आ जाओ। वहां के इलाके के लोग सीधे हैं, उन्होंने सोचा कि ठीक है, हमको सहकारी समिति का रुपया मिल रहा है तो चल कर ले आयें। इन्सपेक्टर ने उनको अपने घर रखा और कांग्रेस केन्डीडेट से मिला, उन्होंने कहा कि रुपया तो हम आपको दिला देते हैं पर वोट हमको दे दो। उन्होंने कहा कि वोट तो हम आपको नहीं देंगे। उन्होंने कहा कल रुपया दिला देंगे, हमारे यहां ठहर जाओ, इन्सपेक्टर ने उनको अपने घर पर रखा और फिर क्या होता है कि कांग्रेस की गाड़ियां आती हैं, उनमें उन लोगों को बैठा कर प्रतापपुर गांधी आश्रम में उन ६ आदमियों को बन्द किया। जिस रोज़ चुनाव थे उससे पहले रात को प्रतापपुर से फौन आया कि आपके ६ आदमी गांधी आश्रम में बन्द हैं, चाहो तो पकड़ सकते हो। हमने कलेक्टर बांसवाड़ा को रिपोर्ट दी कि हमारे पांच-छः आदमी प्रतापपुर में गायब हैं, कलेक्टर ने एस. पी. को रिपोर्ट दी, एस. पी. ने फोन किया, पुलिस थाने पर फोन गया। उधर थाने पर कांग्रेस के सी. आई. डी. लगे थे......

(२.१६ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उन्होंने कांग्रेस वालों को इतला दे दी कि आ रहे हैं इनको लेने। हमारी गाड़ी वहां पहुंचती है तो उनमें से एक आदमी तो जो नले पर टट्टी गया था वह मिल गया, ५ आदमियों को बन्द कर रखा था। एस. पी. ने फोन किया तो कांग्रेस वालों ने उन पांच आदमियों को गाड़ी में बैठाकर, डूंगरपुर, आसपुर को जो रास्ता जाता है वहां ले गये, हमारी गाड़ी पीछे गई और उनको पकड़ा। इधर वोट पड़ रहे हैं, उधर हमारे पंचों और सरपंचों को उड़ा कर डूंगरपुर ले गये। जो इन्होंने गद्दारी की हमारी पार्टी के साथ और लोगों के साथ और वह भी करने वाले हरिदेव जोशी, खोटा रास्ता जो अपनाने वाले हैं, उन्होंने

(श्री विट्ठल भाई)

हमारे साथ इस तरह का बुरा व्यवहार किया है। बांसवाड़ा जिले में समाजवादी लोगों के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। कांग्रेस आज तक बांसवाड़ा क्षेत्र से नहीं जीत सकी, वहां के लोगों को आज तक नहीं जीत सकी, ऐसे नहीं जीत सकी तो उसने इस प्रकार के खोटे धंधे अपना कर पैसों की मदद से, लोगों को उड़ा कर जीतने की कोशिश की; वोट वहां दोगे तो चलो बांसवाड़ा छोड़ देता हूँ। इस प्रकार झूठा समझा कर उनको बांसवाड़ा नहीं ले जाकर डूंगरपुर ले गये। रास्ते में हमारी पार्टी की गाड़ी गई थी और हम वापिस बिठा कर ला रहे थे तो तीन बजे का समय था वह टल गया और वे लोग वोट नहीं दे सके। पन्द्रह आदमियों का तो पता ही नहीं कि कहां छिपा दिया। इस प्रकार २० आदमी कांग्रेस पार्टी ने तोड़ लिये। यह तुम्हारा खोटा धन्धा है। इस तरह समाजवाद आप आज नहीं ला सकते, कल भी नहीं ला सकते। मैं यह साफ कह देता हूं। हम लोगों ने बांसवाड़ा एस. पी. को रिपोर्ट दी है। बांसवाड़ा एस. पी. भी कांग्रेस पार्टी भी देखती थी।

श्री बालकृष्ण कौल : क्या ये सब नाबालिग थे ?

श्री विट्ठल भाई : सहकारी समिति से कर्जा देने के लिए आपके इन्सपेक्टर ने बुलवाया था और फिर अपने घर पर ले गये और फिर कांग्रेस पार्टी में ले गये यह कह कर कि तुमको कर्जा दिलाते हैं बैंक से ऐसा कह कर गाड़ी में बिठा कर ग्रू ले गये। आपको भी यदि इस प्रकार कह कर गाड़ी में बिठा कर ले जायें तो क्या करेंगे ?

श्री मुरलीधर व्यास : बयान दिया है, जांच होनी चाहिये। कांग्रेस के अध्यक्ष इस प्रकार का काम करें, धोखा लेकर ले जायें और बन्द कर दें, इसकी जांच होनी चाहिये और आपकी मार्फत मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री और गृह मंत्री इसकी जांच करायें। वित्त मंत्री जी ही हैं यहां।

श्री बालकृष्ण कौल : इससे बजट का ताल्लुक नहीं है। कोई विशेष बात लानी है तो स्थगन-प्रस्ताव लाइये और कहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : डेमोक्रेसी में थोड़ा विश्वास करते हैं तो जांच करके जवाब देना चाहिये।

श्री विट्ठल भाई : एफिडेविट भी हो गये हैं। हलफिया बयान भी हो गये हैं। सरकार पूरी जांच करे तो कार्यवाही हो सकती है और भगाने वालों को पकड़ सकती है। नहीं करनी है तो अच्छी बात है...

श्री बालकृष्ण कौल : अरे भाई हर तरह भगाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आपके अंकित दस मिनट समाप्त हो चुके हैं इसलिए आप अपना सीमित भाषण ही रखें। पांच मिनिट और ले लीजिये।

श्री विट्ठलभाई: वित्त मंत्री ने अपने बजट में बताया है कि इस घाटे को पूरा करने के लिए भूमि जो काश्त के लिए है वह लोगों को दी जाय। मैं भी इसके लिए राय दूंगा। कि जितने हमारे जिले हैं राजस्थान में उन सब ही जिलों में बंजर भूमि पड़ी हुई है बहुत सी और उस भूमि को जो भूमि-हीन काश्तकार है उनको दे दें तो उससे दो फायदे हो सकते हैं। एक तो काश्तकार को भूमि मिल जायगी, जो भूमिहीन है और दूसरा उससे जो अनाज की पैदावार होगी और बढ़ोतरी होगी इससे अन्न संकट भी नहीं रहेगा। इसके साथ साथ सरकार को भी राजस्व का फायदा होगा लगान अधिक आयगा। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापपुर उन हिस्सों में जंगल बहुत हैं। रेवेन्यू की जमीन से जंगलात की ज्यादा है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि जहां जंगलात की जमीन है, जो काबिल काश्त है, उस जमीन को निकाल कर रेवेन्यू में डाल कर वहां के जो आदिवासी भूमिहीन किसान हैं उनको दी जाय। अगर हमारे पास पड़त भूमि पड़ी रहेगी और सरकार इनको देगी नहीं तो क्या होगा भूखमरी फैलेगी और क्या होगा ? अगर जमीन देंगे तो भूखमरी मिटेगी और सरकार को भी उससे राजस्व का फायदा हो सकता है मैं गारन्टी के साथ कहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि जो जमीन काबिल काश्त नहीं है वह दी जाय। वह बात अलग है। हम वृक्ष भी रखना चाहते हैं और पहाड़ भी उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। काबिल काश्त जमीन पड़ी हुई हैं। २० वर्ष पौधे के लिए जंगल रखते हैं, जितना बीस वर्ष में जंगल में पौधा बन कर फायदा पहुंचायेंगे उतना यदि बीस वर्ष तक किसान उस जमीन को काश्त करेगा तो उन पौधों की आमदनी से कहीं अधिक आपको राजस्व की आमदनी होगी और अधिक अन्न उपजेगा काश्तकार को भी जमीन मिलेगी। और सरकार को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट और साहब।

हमारे बांसवाड़ा जिले में माही बांध की पांच साल से योजना चल रही है लेकिन अभी वहां कोई काम नहीं चल रहा है। जमीन बहुत ज्यादा है, लेकिन न तो वह किसानों को मिल रही है और न ही कुछ हो रहा है। न तो किसानों को कोई राहत मिल रही हैं और नहीं पंचायत समिति से राहत मिल रही है न मदद मिल रही है और न ही जमीन मिल रही है। या तो सरकार उसको बंधाने की कोशिश करे, नहीं तो जमीन किसानों को दे दे।

श्री बालकृष्ण कौल : माही का बांध बनेगा। टोकन ग्रान्ट है।

श्री विट्ठल भाई : कब बनेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब के बतायेंगे।

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : श्री घारू।

श्री हरिराम धारु (सिवाना-मु.) : उपाध्यक्षजी, तीन दिन से यहाँ पर राजस्थान के इस वर्ष के बजट पर विरोधी दलों के सज्जनों ने अपनी बुद्धि अनुकूल तरंगे निकाली हैं और आलोचना की है । परन्तु उपाध्यक्ष जी, मैं आप से निवेदन करूं कि हम राजस्थान के अन्दर पाकिस्तान हिन्दुस्तान सरहद के पास बसते हैं तो हमारा बजट और टैक्स अच्छे हों जिससे हमारे यहां हर काम में उन्नति हो और मैं यह भी निवेदन करूं आपके द्वारा कि टैक्स लगाने में जो थोड़ी बहुत कमी है और ज्यादा लगाने चाहिये । जनता खुद टैक्स देने को राजी है, क्योंकि जनता खुद मांग करती है कि हमारे यहाँ स्कूल हों, हमारे यहां कॉलेज हों । जनता चाहती है कि सरकार खेती बाड़ी के लिए और कोऑपरेटिव में पैसा दे । सरकार के बजट में पैसा हो तब ही तो मिलता है । बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाहें बड़ी हैं, बजट में पैसा होगा और टैक्स लगेंगे तो छोटे लोगों को भी तनख्वाह खूब मिलेगी । फोर्थ क्लास के हैं, उनको कम से कम सौ रुपया तनख्वाह होगी तब ही जाकर वे अपने बाल-बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध कर सकते हैं; नहीं तो ६०), ७०) में तो उनका पूरा होना मुश्किल है । उनकी शिक्षा तो दूर रही, उनका खाना और कपड़ा भी पूरा नहीं होता । सबसे गंदा काम हमारे मेहतर समाज का है । उनकी तनख्वाह १२५) रुपयों से तो कम नहीं होनी चाहिए ।

(विपक्ष द्वारा हियर-हियर)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : चार दिन में एक ही बात काम की सुनने को मिली ।

श्री हरिराम धारू : यह आपके दिल की बात है ।

उपाध्यक्षजी, यह जो धान की तकलीफ आ रही है, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि धान की कमी के अन्दर जनसंघ के नेताओं की शरारत है । ये रात में उथल पुथल करते ही रहते हैं । दिन को तो नहीं करते, मैंने रात में सी. आई. डी. के तौर पर देखा है कि रात को ये उथल पुथल करते रहते हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): आपका मतलब, तस्कर व्यापार करते हैं ?

श्री हरिराम धारू : धान को इधर उधर करना । इधर चीन की लड़ाई में धान की कमी हुई, काश्मीर में धान का प्रबन्ध करना पड़ता है । उन पर चौकीदारी रखनी पड़ती है । बहती गंगा में जनसंघ भी हाथ धोना चाहता है और चाहता है कि सरकार इस प्रकार कमजोर हो जाय । तो सरकार कमजोर होने वाली नहीं,सरकार बड़ी जागरूक है, हमारे कृषि मंत्री जी, मुख्य मंत्रीजी, सब समझते हैं । नाथूराम जी बहुत होशियार हैं उनका पूरा ध्यान रखते हैं......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डांगी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री हरिराम धारू : टैक्स आप लगा रहे हैं । राजा-महाराजाओं को जेब खर्च के लिए लाखों रुपया आप देते हैं । इसके बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया कि यह बहुत बड़ी रकम है, इसलिए भारत सरकार से अपील की जाय इस जेब खर्च को या तो खत्म कर दे, नहीं तो आधी रकम कर दी जाय । क्योंकि हमें चारों तरफ लड़ने की तैयारी रखनी पड़ती है ।

(श्री हरिराम घारू) .

इसके अलावा हमारे टाप लीडर नेता नाथूराम जी साहब बिराजे हैं उनसे अर्ज करूंगा कि उन्होंने इस बार पंचायतों के चुनावों में विरोधियों को बहुत कमजोर कर दिया है; उनको इतना कमजोर नहीं करना चाहिये। कुछ न कुछ विरोधी पार्टी रहनी ही चाहिये। आपने तो १०० सरपंचों में मुश्किल से तीन-चार को ही आने दिया है। ऐसा कर देंगे तो इनका दिल बैठ जायगा। यह ठीक नहीं हुआ है।

मैं मेरे क्षेत्र के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक मन्डी है वहां आने के लिये बीच में नदी पड़ती है। समदड़ी में आप बरसात में नदी पर पुसिया बन्धा दे तो वहां की जनता को बहुत फायदा होगा। सिवाना में बिजली घर लगाया है, उसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं, ४५० किलोवाट का बिजली घर लगाया है। सिवाना में बिजली गई है ३ मील मोकलसर माहिलियावास गई है, इसके लिए बिजली मंत्री और सरकार को धन्यवाद देता हूं।इससे तीन सौ किसानों को बिजली मिली। उससे वहां धान भी बहुत पैदा होगा।

इसके अलावा कृषि मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि सिवाना में पैकेज प्रोग्राम बनायें, जिस प्रकार पाली में बनाया है। वहां पर भी काफी धान उपजता है बेरों से। कुओं से सिंचाई होती है। अगर वहां पर जिस प्रकार पाली में पैकेज प्रोग्राम है उसी प्रकार कर दिया जाय तो आगे चल कर बहुत अच्छी बात होगी।

बालोतरा, सिवाना, मोकलसर सड़क है उस रोड पर काफी बसें चलती हैं, वहां पर डामर रोड बनाना अच्छा रहेगा। मैंने चुनाव के समय दोहा भी कहा था कि "डामर रोड माथे मोटर चालसी रे बिन घड़के री"।

सरकार टैक्स लगावे तो वह भी ठीक ढंग से लगावे। मेहतरों की तनख्वाह १२५ रुपये से कम नहीं होनी चाहिये। बोर्डर पर अच्छी सड़कें हों। हमारे बोर्डर की हिफाजत का प्रबन्ध हमारी सरकार का है। इसलिये ज्यादा टैक्स लगाकर भी बोर्डर का क्षेत्र है उस पर जागरूक रह कर पाकिस्तान की चौकीदारी रखनी चाहिये।

श्री केसरीसिंह (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की खुशहाली को लक्ष्य में रखकर कांग्रेस ने जो नीतियां अपनायी हैं उनके आधार पर सेन्टर में और प्रान्तों में वित्त मन्त्री महोदय अपना अपना बजट बनाया करते हैं। उन नीतियों पर चलने से देश में क्या और कैसी खुशहाली आयी है वह हमारे सामने है। मैं यह नहीं कहता कि कोई विकास नहीं हुआ, काफी विकास हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके का विकास हो सकता था, साथ ही सस्ता विकास हो सकता था। यह विकास हमें महंगा पड़ा है, इस विकास के साथ कई तरह की कठिनाइयां हमारे सामने मौजूद हैं। टैक्सेज का बहुत भार है जो सीमा से बाहर जा चुका है। मंहगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर बात में रोजमर्रा के कामों में गवर्नमेंट का दखल दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। अन्न की समस्या आपके सामने है, ये सारी कठिनाइयां है। यह उन नीतियो का परिणाम है जो कांग्रेस ने अपनायी हैं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

अब इन परिस्थितियों में जिस चीज को

(श्री केसरीसिंह)

जरूरत है वह जैसा कि मेरे कई मित्रों ने बताया ग्राम आदमी को राहत मिले। साथ ही यह भी जरूरी है कि उत्पादन—सभी तरह का उत्पादन-औद्योगिक, कृषि आदि तेजी से बढ़े, इसकी जरूरत है।

अब राहत देने के नाम पर जो महंगाई भत्ते में आपने तरक्कियां की हैं उनके बारे में हमारे मित्रों ने जो कुछ कहा वह आपने सुना ही है। वास्तव में वह न तो पर्याप्त है और न उचित। जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह इस बढ़ती हुई मंहगाई की समस्या का हल नहीं है। यह तो एक विषाक्त सर्कल है जिसके अनुसार कीमतें बढ़ गईं और आपने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया; इसी तरह से ज्यों ज्यों मंहगाई बढ़ती जायगी, आप भत्ते में बढ़ोत्तरी करते रहेंगे, लेकिन यह उसका निदान नहीं है।

नये कर जो आपने लगाये हैं उनके बारे में भी आपने हमारे मित्रों की टीका टिप्पणी सुनी। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। हां, एक बात जरूर कहूंगा। दवाओं पर आपने जो टैक्स लगाया है उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि दवाओं पर टैक्स लगाने की भावना है वह बड़ी डिस्गरिटिंग है। जैसा कि आपने रिक्शा चालकों के बारे में अपनी राय बताते हुए कहा था कि एक आदमी को दूसरा आदमी खींचे, यह इन-ह्यूमेन है। इसी तरह से आप अगर सोचें तो एक वेलफेअर स्टेट में एक बीमार को अपनी दवाई पर टैक्स देना पड़े, तो मेरे ख्याल से यह बहुत ही ज्यादा निकृष्ट भावना है, हर तरह से त्याज्य है।

दूसरे, टैक्सेज के बारे में विशेष मैं कुछ नहीं कहूंगा, राहत के नाम पर जो डिसएबल्ड पर्सन्स को सहायता का प्रावधान किया गया है वह ठीक है। लेकिन इससे आम आदमी को राहत मिल जायगी, ऐसी उम्मीद रखना वृथा बात होगी।

जैसा एक माननीय सदस्य ने बताया, आम आदमी को कोई महसूस होने वाली राहत मिल सकेगी, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में, जैसा आपने बताया, यह बजट जो बनता है उसमें केवल वित्त मंत्री ही नहीं होते हैं उनके साथ और बहुत से फैक्टर्स रेस्पोंसिबल होते हैं। उन सब परिस्थितियों से आप बंधे हुए होते हैं और बहुत हद तक यह बजट आपके बेबसी का परिचय है। जो कुछ भी आपने किया है आपने एक संतुलित बजट पेश किया है। अब प्रश्न यह रहता है कि ऐसी परिस्थितियों में कुछ राहत आम आदमी को मिल सकती है या नहीं?

हम विरोधी पक्ष वाले आपका केवल क्रिटिसिज़्म ही करते हैं या कोई पोज़िटिव आॅल्टर्नेटिव भी पेश कर सकते हैं। हमारा मत है कि पोज़िटिव आॅल्टर्नेटिव है और वह हम पेश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि राजस्थान और सेंटर तथा दूसरी स्टेट्स में जो नीतियां कांग्रेस ने अपना रखी हैं उनमें कुछ बुनियादी परिवर्तन आवश्यक है। वे बुनियादी परिवर्तन क्या हैं? पहला तो प्लानिंग के मेथड से छुट्टी मनाइये। We must have a holiday from this sort of planning.

तीसरी योजना के जो टार्गेट्स हैं सारे ही देश के, वे पूरे नहीं हो सकते। तो, मैं यह कहूंगा कि इस पंचवर्षीय योजना को सप्त-वर्षीय योजना बना दिया जाय ताकि आपके

(श्री केसरसिंह)

टार्गेट्स पूरे हो सकें । ऐसी परिस्थिति स्टालिन के मरने पर ख्रुश्चेव के सामने आई थी और उन्होंने साहस किया कि हमारी प्लान इनकम्प्लीट है पहले उसको समाप्त कर दें । कोई दूसरी बनाने के पहले let us finish this first. तो इस तृतीय पंचवर्षीय योजना को दो साल और बढ़ाना चाहिये और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को स्थगित रखना चाहिये ।

दूसरी बात, आपको ये सारे कंट्रोल्स आदि खत्म करने पड़ेंगे । इस परिमिट, लाइसेंस और कोटा राज को समाप्त करना अत्यन्त आवश्यक है । दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रिटेन में कन्जर्वेटिव पार्टी ने ऐसा ही किया था और थोड़े ही समय में उस देश में काया पलट हो गई और मिनिस्टर बटलर कह सके कि.........

एक माननीय सदस्य : कोरम तो पूरा नहीं है ।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : कोरम तो पूरा है ।

श्री केसरीसिंह : तीसरी बात जो हमको करनी होगी यह फॉरेन पालिसी में बुनियादी तब्दील स्वीकार करनी है । आपकी जो तथाकथित तटस्थता की नीति है वह छोड़नी पड़ेगी और आपको इन्टरडिपेंडेंस स्वीकार करना पड़ेगा । आपको मानना होगा कि दुनिया एक है और मित्रों और पड़ोसी देशों से आइसोलेशन में रहना सम्भव नहीं है । इसका मतलब यह होगा कि अमेरिका, ब्रिटेन आदि मित्र देशों से हमको संधि करनी पड़ेगी और उनसे प्राप्त हो सकने वाला मिलिटरी एसिस्टेन्स, न्युक्लियर वेपन्स सहित स्वीकार करना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप जिस विषय पर कह रहे हैं वह केन्द्रीय सरकार के स्कोप में है ।

श्री केसरीसिंह : कुछ नहीं हुकुम ।

हमारा दल नॉन अलॉइनमेंट के विरुद्ध नहीं है । यह हो सकता है कि आपका जो नॉन अलाइनमेंट का नोशन है उस नोशन से हमारा नोशन मेल न खाये । तो नीतियों में यदि बुनियादी परिवर्तन कुबूल किये जायं तो सेंटर और स्टेट्स में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि आम आदमी को राहत मिले ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : कैसे ?

श्री केसरीसिंह : आपके जितने भी टैक्सेज हैं वे ४० या ५० प्रतिशत तक आप टाल सकते हैं । जितने भी आपके डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्सेज हैं वे कम कर दें । आपके डिफेंस का खर्च आपके टैक्स-पेयर पर नहीं पड़ेगा और भी कई देश हैं जिनको अमेरिका ने मिलिटरी ऐसिस्टेंस दी; जैसे वेस्ट जर्मनी, जापान, इटली, फिलीपाइन्स, टर्की, ईरान और डिफेंस एक्सपेंडीचर का बर्डन उनकी एकोनामी पर नहीं पड़ेगा ।

दूसरी बात जो मैंने अर्ज की कि चौथी योजना को स्थगित कर दें । तीसरी योजना को दो साल और बढ़ा दें । ऐसा करने से नये वेस्टफुल प्रोजेक्ट्स पर जो खर्च होता है वह नहीं होगा । आप नये वेस्टफुल प्रोजेक्ट्स तब तक नहीं लें जब तक कि, पहले के प्रोजेक्ट्स से लाभ मिलना चालू नहीं हो जाय । तो नई प्लान का खर्च भी बच जायेगा और आप डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टैक्सेज कम कर सकेंगे । इसका आपकी इकोनोमी पर

(श्री केसरीसिंह)

यह असर पड़ेगा कि उत्पादन आगे बढ़ेगा। उत्पादकों पर से जब आपका यह दम घोटने वाला शिकंजा हट जायगा तब वे एंटरप्राइजिंग लोग बहुत कुछ कर सकेंगे । एरहार्ड ने कहा. "You leave the man and money loose and they will make the country strong." उन्होंने ऐसा ही कदम जर्मनी में उठाया था और उसका वैसा ही परिणाम जर्मनी में हुआ ।

रोजगार बढ़ेगा, वाणिज्य व्यवसाय बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा धन उपलब्ध होगा और ऐसा वातावरण बनेगा कि जिसमें फॉरिन करेन्सी भी बड़ी तादाद में एकत्रित करने लगेंगे जिसकी आज बड़ी जरूरत देश को है।

इस प्रकार प्रोडक्शन के द्रुत गति से बढ़ने का परिणाम क्या होगा ? कुल मिलाकर यह होगा कि we shall have more goods and services with the same amount in circulation.

इसका असर यह होगा कि कीमतें बढ़ती हुई रुक जावेंगी । प्राइसेज में स्टेबिलिटी आवेगी और मैं तो यहां तक कहूंगा कि since 1940, for the first time you will have stable prices and honest money (Rupee).

ये बड़े बड़े टैक्स जब आप बन्द कर देंगे, तथा कन्ट्रोल और परमिट की प्रथाएं समाप्त कर देंगे तो मैं कहूंगा कि करप्शन भी बहुत हद तक रूट आउट हो सकेगा । टैक्स इवेजन और ब्लैक मनी रुक कर मनी केश के रूप में फर्दर इन्वेस्टमेन्ट के रूप में उपलब्ध होगा जिसकी कि आज नितान्त जरूरत है देश के इन्डस्ट्रियलाइजेशन के लिए।

इसी प्रकार डी-कन्ट्रोल होने से जिस अन्न का अभाव चारों ओर आज दिखाई दे रहा है और महसूस होता है कि वह सारा अन्डर ग्राउन्ड चला गया, बाजार में दिखाई नहीं देता, वह बाजारों में आने लगेगा और अन्नाभाव की समस्या सही माने में और मुकम्मिल तौर पर अपने आप हल हो सकेगी ।

इसी प्रकार प्रोडक्शन की स्पिरिट से जो उत्पादन द्रुत गति से बढ़ेगा उससे हमारी अर्थ व्यवस्था में रेट ऑफ ग्रोथ एक्सीलरेट होगी । आज हमारी इकॉनामी की रेट ऑफ ग्रोथ आठ वर्षों से स्टेग्नेन्ट है । रेट ऑफ ग्रोथ वह आज करीबन दो पर्सेन्ट है और उधर हमारी जन्म संख्या की औसत भी २.२ या २.४ पर्सेन्ट है । अर्ज करने का मतलब यह है कि रेट ऑफ ग्रोथ आज बहुत ही नाकाफी है ।

ऐसी नीतियां आज जिन देशों में अमल में आती हैं, जैसा मैंने अर्ज किया, वहां रेट ऑफ ग्रोथ आठ पर्सेन्ट से दस पर्सेन्ट और कहीं कहीं जापान सरीखे देश में २० पर्सेन्ट तक है । इस प्रकार जब रेट ऑफ ग्रोथ हमारी बढ़ेगी तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि वी विल हैव ए लार्जर केक कि जिसमें से हरेक के लिए हरेक के हिस्से में एक बिगर स्लाइस आना शुरू होगा । सब मिलाकर स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा हर तरह की क्लास ऑफ पीपल का । We will have to provide for every class of people a richer life.

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह सब हो सकता है जब हम अपनी इन वर्तमान नीतियों में बेसिक परिवर्तन करें । मैं कहता हूं कि हमने जो यह अल्टरनेटिव आपको बताया इसके मुताबिक

(श्री केसरीसिंह)

यदि मन्त्रिमण्डल ने बुनियादी परिवर्तन स्वीकार कर लिया तो कोई दस-पन्द्रह साल की बात नहीं है, बल्कि मैं निवेदन करूंगा कि दस-पन्द्रह महीनों में ही वातावरण बदलता हुआ हम देख सकते हैं। आप निश्चित रूप से यह देख सकते हैं कि हमारा उत्पादन किस तेजी से बढ़ता है, और रेट ऑफ ग्रोथ हमारी किस द्रुत गति से चलती है। इसमें मुझे तो लेशमात्र भी सन्देह नहीं है। देशवासी आज की इस घुटन के वातावरण से तत्काल चैन की सांस ले सकते हैं। इसमें भी लेशमात्र शंका मुझे नहीं है। टैक्स कम होंगे, इनकी आवश्यकता भी उतनी नहीं रह जावेगी, तो टैक्स कम होंगे तो महंगाई कम होगी। हर बात में रोजमर्रा की हर चीज में जो आज सरकार का दखल हो रहा है, एक निगेटिव दृष्टिकोण से देश में जो घुटन का और रुकावट का वातावरण निर्मित हो गया है वह दखल कम होगा और घुटन का वातावरण निर्मल वातावरण में बदल जावेगा। करप्शन कम होगा और प्रोडक्शन तब ऐसी तेजी से बढ़ेगा कि जैसा यहां आज तक देखने को नहीं मिला है। लोगों को इन्सेन्टिव मिलेगा। दूसरे देशों की तरह लोग यहां के उत्पादन बढ़ाने में भी प्राणपण से जुट जावेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में समाप्त करता हूं। जर्मनी में इन्हीं नीतियों को काम में और अमल में लाकर एरहार्ड ने जो आर्थिक परिवर्तन देश में तीव्र गति से किया है उसे इकॉनोमिकल मिरेकल कहा जाता है। तो उन्हीं नीतियों पर चल कर अपने देश में भी वह इकोनोमिकल मिरेकल जरूर हो सकता है।

तो अब प्रश्न यह रहता है कि जब यह सब हो सकता है तो किया क्यों नहीं जाता! ऐसा तो है नहीं कि इन बातों को आप समझते ही न हों। आप भी बुद्धिमान हैं और निश्चय ही इन सारी बातों को आप समझ सकते हैं। तो फिर क्या कारण है कि जिससे आप ये सब कदम उठाने को इन नीतियों को अपनाने को तैयार ही नहीं है। इस विषय में मैं अर्ज करूंगा कि मेरे ख्याल से इसका एक ही कारण है कि आप पर भूतकाल सवार है। भूतकाल की बातों को आप आज वर्तमान में भी पकड़े रहना चाहते हैं। You have gone into a rut and you don't have the courage to get up. विगत पन्द्रह सालों से जो मार्ग, सही या गलत, श्रद्धेय जवाहरलालजी नेहरू ने इनको पकड़ा दिया, वह आपसे छोड़ा ही नहीं जाता। पकड़े ही चले जा रहे हैं। मैं मानता हूँ यह बड़ी मुश्किल चीज है कि जिस रास्ते पर आप ऐलान करके चलें, पर उसमें गलती अगर मालूम हो तो उसे मन्जूर करके अपने स्टेप्स राइट डाइरेक्शन में बदल दें, यह साहसी व्यक्ति के ही बूते की बात है, इसमें बहुत बड़े साहस की जरूरत है। मैं मानता हूं यह साहस अब आप में रह नहीं गया। आपके लिए यह कठिन चीज है। हालांकि देश के हित में यह अति आवश्यक है कि आगे बढ़ने के लिए खुले दिमाग से काम लिया जाय। आज तो आप आराम तलब हो गये हैं, आप में गलतियों को सुधारने का साहस नहीं रह गया है। चेन्ज के लिए आपके दिलों में इस प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिये। चेन्ज से चमकना नहीं चाहिए। You should be able to think and act boldly.

Page No 83

(श्री केसरीसिंह)

परन्तु आज इस देश में; आज की आपकी इस स्थिति में जिस स्थिति में आप पड़ गये हो, आपसे उम्मीद करना मृग मरीचिका है। देखिए वित मन्त्रीजी आपने जरा सा ही कहा था अपनी बजट स्पीच में कहा था अपनी बजट स्पीच में कि नेहरूजी, का देहावसान एक ऐतिहासिक घटना है और उसके साथ ही एक युग समाप्त हो जाता है और नये युग का सूत्रपात होता है। जिस भावना से आपने ये शब्द कहे मैं तो उनका आदर करता हूं। परन्तु आप देखें कि आपके ही मित्र आपके ही पीछे पड़ गये इन शब्दों को लेकर कि आप तो नेहरू युग को समाप्त करने की बात कहते हैं और कौन युग चलाना चाहते हैं आदि आदि। और न जाने क्या क्या बातें कहीं? तो यह उनका नेरो माइन्डेडनेस है। उनकी तंगदिली का परिचायक है और ऐसे मित्रों से घिरे हुए आपसे हम कोई उम्मीद कर यह बेकार है। आप ड्रास्टिक चेन्ज नहीं ला सकते जिसकी नितान्त आवश्यकता है आज देश को आज की इन परिस्थितियों में। पर फिर भी मैं कह सकता हूँ...

श्री बालकृष्ण कौल (वित मन्त्री) : Are these compliments ?

श्री केसरीसिंह : As you like.

तथापि मैं यह कहूंगा कि हमारे देश में आज की परिस्थितियों में जो सरकारी नीतियां हैं उनमें बुनियादी परिवर्तन की देश–हित में सख्त जरूरत है। आज की यह सरकार विगत १५ वर्षों से जो नीतियां अमल में लाती रही है उनके परिणामस्वरूप जनता में व्यापक असन्तोष फैला हुआ है तो समय रहते अगर आपने हवा का रुख नहीं पहचाना और अपनी नीतियों को सही रास्त पर नहीं लाये तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यह व्यापक असन्तोष ३ रोज में आपको बदल सकता है। यह बदलना इनएवीटेबल है। जब जनता में फैला हुआ व्यापक असन्तोष तीव्र रोष का रूप धारण करता है तो बड़ी बड़ी ताकतें धूल में मिल जाती हैं। बातें अच्छी नहीं होतीं तब। उपाध्यक्ष महोदय, विप्लव का जन्मदाता ही यह बदलना होता है।

मैं कहता हूं अभी समय है। समय रहते आप बदलिये। जनता के इस असन्तोष को समझिये। वर्ना देश बरबादी की तरफ जा रहा है, और जावेगा। यह चेतावनी देते हुए तथा परिवर्तन के लिये एक पोज़ीटिव ऑल्टर्नेटिव आपके समक्ष उपस्थित करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जब अपना भाषण दे रहे थे तो उनकी बातों को सुनकर मैं सोच रहा था कि हमारा यह बजट समाजवाद की तरफ बढ़ाने जा रहा है। हमें ऐसा आभास हुआ कि वित्त मन्त्री महोदय जिनकी सरकार का कार्यकाल दो वर्ष और रह गया है और उसके बाद जनता के सामने जाकर जवाबदेही देनी होगी उनको कि इन पांच वर्षों के अपने कार्यकाल में अपनी घोषित नीति समाजवाद की ओर कितना वे आगे बढ़े हैं, तो वे निश्चित ही अपने बजट भाषण में ऐसा कुछ कहेंगे कि जिससे यह प्रतीत हो कि उनकी सरकार समाजवाद लाने को कटिबद्ध है और जब उन्होंने अपने

(श्री नाथीसिंह)

भाषण में उस जमीन का जिक्र किया जिसके ऊपर लोगों की तकदीर बनने वाली है वह तस्वीर बनने वाली है, रंग उसमें भरे जाने हैं; पर भाषण सुनकर निराशा ही हाथ लगी।

(३. म. प.)

तो वह जमीन मैं सोच रहा था उस जमीन की ओर उनका ध्यान है। जिस जमीन में इस राजस्थान में आज अधनंगे भूखे इन्सान रहते हैं। एक ओर उस जमीन पर आज भी यह हालत है कि लोगों को दो जून खाने को मयस्सर नहीं होता, तीन आने रोज की आमदनी वाले बहु-संख्यक लोग इस प्रदेश में बसते हैं और दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति भी इस प्रदेश में ज्यादा हैं जिनकी हमारे राज्य की बनिस्बत आमदनी की सीमा कहीं अधिक है। ३ लाख ४ लाख महीना पाने वाले भी इस प्रदेश में अधिक हैं। यह आमदनी में जो विराट अन्तर है उसको पाटने के लिए कोई क्रांतिकारी कदम अपने बजट में वित्त मंत्रीजी रखेंगे, मैं इस प्रकार की कल्पना कर रहा था लेकिन वह मेरी कल्पना ही साबित हुई। वे इस भूमि पर नहीं उतरे, उनको नजर जमीन पर गई ही नहीं कि आज भी जो हमारी सम्पत्ति है उसका संचय शहरों में हो रहा है। इस संचय पर हम किस प्रकार से सीलिंग लगायें इस पर आपने नजर नहीं डाली इस प्रदेश में इस प्रकार के लोग भी हैं कि जो जनता के मार पर आज भी बिना कमाये ऐशो आराम की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। आज मैं प्रिवी पर्स वाली बात नहीं कहता। इस ओर उनकी नजर नहीं गई। इसलिए मैं कहता हूं, जब सही दिशा में उनकी नजर नहीं जाती है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम एक ही होना चाहिए था कि उनकी नजर गलत जगह पर जायेगी, गलत जमीन पर जायेगी और उसका नतीजा समाजवाद की ओर कदम बढ़ाना नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि उनकी नजर किसी जमीन पर नहीं गई हो, लेकिन वह जमीन तलाश करते करते वह उन खातेदारों की जमीन पर जा पहुंची जहां गरीब किसान का कुआ है और उन्होंने ढूंढकर उस जमीन को देख डाला और कहा कि इससे हम ३० लाख की आमदनी कर लेंगे। उन कुओं पर आपने टैक्स लगा दिया। आप उसके लिए सनद देंगे और उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर किसान को और ज्यादा हकूक जो आज के कानून में हैं उनसे ज्यादा क्या करने जा जा रहे हैं? मुझे खुशी होती यदि आपकी नजर पड़ती उस जमीन पर जिस जमीन पर आज किसान पैदा करता है और किसान पैदा करने के बाद में भी उस जमीन से कोई मुनाफा नहीं कमाता। आपकी नजर उस जमीन पर जाती जिससे लोग मुनाफा कमाते हैं और आप घोषणा करते कि आज हमारी सरकार यह क्रांतिकारी कदम लेना चाहती है। जिस किसान से हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे प्रदेश में अनाज का उत्पादन बढ़े, मंहगाई घटे, लोगों को अनाज मुहैया हो और जी तोड़कर जो किसान धरती की छाती को चीर कर मेहनत करता है वह किसान उस जमीन पर से, जिससे उसको मुनाफा नहीं होता और

(श्री नत्थीसिंह)

एक तरह से केवल वह अपना पेट पालने के लिए या देश--सेवा की भावना से अनाज पैदा करता है । उस जमीन पर, बिना मुनाफे की जमीन पर जिसकी प्लानिंग ने ६ एकड़ की सीमा निर्धारित की है उसके ऊपर लगान की माफी दें। इसके अलावा हम उधर देखते हैं कि शहरों में जहां आदमी बढ़ती जा रही है और सम्पत्ति बढ़ती जा रही है उनके ऊपर सीलिंग की ओर आप इशारा करते, लेकिन आप ऐसा नहीं करते क्यों कि मैं आगे जाकर इसका जिक्र करूंगा कि कैसे आपने नेहरू युग को खत्म होने की बात कही है वह आपने बिलकुल सही कहा है। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि हम समाजवादी समाज की रचना के लिए जो सही कदम उठाया जाना चाहिए उस ओर आप हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं कदम उठाने की ।

आज हम शाइलॉक हो रहे हैं और पौण्ड ऑफ फ्लैश चाहते हैं । एक तरफ आप बिना मुनाफे की जमीन पर लगान नहीं छोडना चाहते हैं और कुओं पर आपकी नजर पड़ गई। किसानों को आज कुओं के ऊपर से पानी लेने का हक है उसको आप नहीं हटा सकते । लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो यह कह रहा हूँ यह सदन में कुछ पहले भी विवाद था कि जब खातेदारी हकूक मिले और उनके इन्तकाल दर्ज किये' गये उसकी फीस ली गई और वह एक किस्म का टैक्स था जो नहीं लिया जाना चाहिए था। कई बार सदन में यह दोहराया गया लेकिन उसको वापिस देने की कोई बात नहीं है। हमारे भरतपुर जिले में खातेदार काश्तकारों पर जब जमीदारी थी तो उस समय दुगुना लगान लिया जाता जाता था। एक लगान राज्य में जमा करने के लिए और दूसरा मुनाफे के तौर पर। यह जमीदारी एबोलीशन के साथ साथ में कानून की स्थिति बदल गई और उसके बाद यह प्रावधान है कि जब किसानों से वही लगान लिया जायेगा जो कि राज्य लगान होगा लेकिन हमारी मुनाफाखोर सरकार आज भी भरतपुर जिले में दुगुना लगान वसूल करती है। यहां विधान सभा में सवालों के जरिये से और दूसरे जरिये से राज्य सरकार के सामने यह प्रश्न लाया गया लेकिन इनकी नीति इन्साफ करने की ओर कतई नहीं जा सकी । इनकी दृष्टि वहां जाती है कि यहां से किस तरह से कुरेदकर, इन्सान को और दबाकर हम अपने खजानें को किस तरह से भर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी यह दृष्टि समाजवादी दृष्टिकोण की दृष्टि नहीं कही जा सकती ।

दूसरी बात जो आप बड़े जोर से कहते उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां यह कहा गया है कि अब की बार वर्षा का अभाव रहा, अकाल पड़ गया, महंगाई हुई और अनाज बाजार में नहीं आया और इसलिए हमारे राज्य पर भारी बोझा पड़ा है। हम इसको देखते हैं ठीक है कि राजस्थान में अकाल आता है। हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि इसकी साइकिल बनी हुई है और कुछ सालों के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है लेकिन उसका दृढ़ता के साथ मुकाबिला करने के लिए क्या कदम हमने उठाये हैं। हमारे सिंचाई मंत्री जी कह रहे थे कि हमने

(श्री नत्थीसिंह)

बड़ी बड़ी योजनायें और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चालू किये हैं। सही है, यह भी अपने माने में एक कदम है लेकिन जिस प्रदेश में अकाल का यह हाल है वहां जब तक आप असरदार रूप से माइनर ईरिगेशन को नहीं बढ़ावा देते तब तक आप किसी भी हालत में कहने के लायक नहीं हैं कि हम अकाल का मुकाबिला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वह यह है कि मैंने अब की बार आपके बजट को देखा, पिछली बार मैंने ध्यान आकर्षित किया था कि हमारे यहां गुड़गांव केनाल की बात आई थी। इन पंचायतों के चुनावों में सौभाग्य से कहें या कैसे भी कहें, हमारे यहां के एक केन्द्र में मंत्री हैं। उन्होंने गांव गांव में जाकर लोगों को कहा कि कांग्रेस को वोट दोगे तो गुड़गांव की नहर तुम्हारे यहां आ जायेगी। लोगों ने उनकी बातों में आकर सोचा कि चलो अब की बार यह भी करके देखो। लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और उसको जिताया। मैंने बजट देखा कि पिछली बार जो प्रावधान रखा गया उसके लिए उससे भी बहुत कम अब की बार रखा गया है। मतलब यह है कि केन्द्र की सरकार के साथ, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हमारी सरकार मात खा गई। वह गुड़गांव नहर को हमारे प्रान्त में लाने में असफल रहे हैं। चलो, वह तो इस बात का बहाना ले सकते हैं कि प्रधान तो हमारे जीत गये लेकिन प्रमुख हरा दिया, इसलिए नहीं लायेंगे लेकिन हमारे यहां राजस्थान की सरकार इसके लिए क्या बहाना लेगी। उसके साथ ही साथ जो छोटी सिंचाई के मामले हैं उनमें क्रांतिकारी कदम यह लाना चाहिए था कि जो आपके वर्तमान साधन हैं उनमें सुधार करके कई सुझाव देते हैं जिनके जरिये आप एग्ज़िस्टिंग मीन्स में ही सुधार कर सकते है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। भरतपुर फीडर को बढ़ाने के लिए एप्रोच किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। जब इस प्रकार की बातें हैं तो हम कैसे मान लें कि आपकी नीयत साफ है ?

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि क्या आप इस बात पर कटिबद्ध हैं कि चाहे अकाल आये या कैसी भी स्थिति हो किसान को आप सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। आपको खेती को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए अगर उसमें प्रगति में नुकसान होता तो उसकी जिम्मेदारी बचाने के लिए राज्य सरकार को लेनी चाहिए।

मैं कहता हूं कि आज तक आपने कोई कदम नहीं बढ़ाया है और अगर आपकी हिम्मत है तो और चीजों के लिए नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम सीरियल्स, नाज के लिए तो बीमा योजना चालू करें जिससे किसानो के दिल में यह बात पैदा हो कि सरकार कम से कम इस बात के लिए तैयार है और हमको मशक्कत करना चाहिए और उत्पादन बढ़ाना चाहिए और यदि प्रकृति का प्रकोप होगा तो सरकार उसके लिए भागीदार होगी। उसकी तरफ नजर नहीं जाती है और आप कहते हैं कि प्रकृति के प्रकोप के कारण नाज की तकलीफ हो गई। हमारे

(श्री नत्थीसिंह)

खाद्य मंत्रीजी कह रहे थे कि हमने ऐसे कदमों को बढ़ाया है जिन कदमों के बढ़ाने से आपको भावों में राहत मिली है। यह तो मार्केट में रबी की फसल आ रही है और जिनके पास स्टाक था वह भी जानता है कि इस में घाटा हो सकता है तो वह कुछ माल बाहर लाया। इसलिए यह स्थिति कुछ सुधरी हुई दिखाई देती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसमें आपका योगदान क्या है ? आप मिनिमम प्राइसेज और मेग्जीमम प्राइस की बात कहते हैं लेकिन अभी भरतपुर जिले की फूड एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बतलाया गया कि १० लाख रुपये इस बात के लिए दिये गये हैं कि १२ रुपये मन पर चना और चने की दाल खरीदना चाहते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि इस सरकार का दिमाग स्पष्ट है और जानबूझ कर भ्रम फैलाती है। १२) रुपये मन के भावों से आप किसानों से खरीदना चाहते हैं और जबकि बीज की बात आती है तो किसानों को बीज २८) रुपये मन के भाव से दिया गया, तो वहां पर एक छटांक चने की दाल भी नहीं खरीदी जा सकती है जब तक कि आप इस बात की तैयारी न कर लें कि हमारे भावों की जो नीति होगी उसमें कम से कम फेर-बदल होगा। मेरी पार्टी कहती है कि ढाई रुपये मन से ज्यादा अदला बदली भावों में मत आने दो अगर आप यह करने को तैयार नहीं है तो नीति तो बदलती है।

आप कानूनों की बात कहते हैं कि हमने कानून बनाया तो जिन कानूनों का गर्व आप करते हैं उन कानूनों का हवाला मैं देना चाहता हूं। आपने ग्रेन मूवमेंट के सिलसिले में जो कानून बनाया और जिसमें जल्दी जल्दी प्रावधान किये गये हैं तो एक पिछला संशोधन किया था कुछ दिन पहले तो उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने इस प्रकार का संशोधन किया कि १० मील के अन्दर २ किसी प्रकार के नाज का ट्रान्सपोर्टेशन कोई नहीं कर सकता। हमारे जिले में उससे यह हाल हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, जो आदमी अपने घर से चक्की पर पिसाने ले गया वह गिरफ्तार हो गया। अगर ५ सेर की पोटली सिर पर रख कर ले जाये तो उनसे पुलिस वाले पैसा लेकर जाने देते हैं। एक किसान ३६ किलो नाज भरतपुर ला रहा था पिसाने के लिए तो उसका पकड़ लिया गया और उसको हवालात की हवा खानी पड़ी और उसके बाद उसको छोड़ा गया और मैजिस्ट्रेट ने कहा कि टेक्निकल ऑफेन्स तो बन गया, क्योंकि ट्रान्सपोर्टेशन पर पाबन्दी लगी हुई है। तो भरतपुर से कुम्हेर १० मील के अन्दर, डीग १० मील के अन्दर, कामा १० मील के अन्दर है। हरेक १० मील के अन्दर है। उस दस मील के अन्दर कोई भी ले जाये तो पाबन्दी लगा दी है और इस पाबन्दी से आपके कानून का पालन हो, उससे आप चाहते हैं किसी तरह की रुकावट आजाये ग्रेन के मूवमेंट में तो यह बात गलत है। इससे आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं इसके सिवाय और कोई बात नहीं करते हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने

(श्री नत्थीसिंह)

१ करोड़ का इजाफा बताया है पुलिस पर और अभी खाद्य मंत्रीजी कह रहे थे कि उससे करप्शन को रोकने में बड़ा योग मिला है । अभी हमारे जिले में एक कमिश्नर महोदय आये थे खुराना साहब, इस बात की जांच करने के लिए कि यह बोर्डर का इलाका है और यहां से नाज बाहर गया है । तो इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का क्या हाथ है ? कौन सा ऑफिसर रिश्वत लेता हैं ? मैंने कहा कि आप यह सवाल क्यों करते हैं ? आप सवाल यह करें कि कौन इसमें शामिल नहीं है ? तो शायद आपको जवाब देने में आसानी हो । और इसका एक कारण है और कारण यह है कि सरकार जिस कदम को उठाती है उस कदम में सरकार की निष्ठा नहीं है । बोर्डर का जो इलाका है उस इलाके में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनका धन्धा यह है । स्मग्लिग का वे धन्धा करते हैं । उनके बारे में आपका एटीट्यूड क्या है ? कड़ाई का रुख आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते है ? मगर आप कड़ाई का रुख नहीं लेते हैं । आपका रुख तो यह दिखता है कि आप उनकी सुरक्षा करते हैं तो निश्चित रूप से चाहे वह पुलिस का कर्मचारी हो उसकी हिम्मत नहीं है कि वे उसको रोक सकें ।

मैं उदाहरण देता हूं अपने जिले का आपकी पुलिस एक्शन ले, आप यह चाहते हैं और यहां की राज्य सरकार क्या करती है ? पंचायतों के चुनावों के समय यह देखने में आया है । एक कानून बना हुआ है कि जो नैतिक अपराधी है तो कोई भी नैतिक अपराधी ६ वर्ष तक खड़ा होने का अधिकारी नहीं है । आज राज्य सरकार को यह दिये गये अधिकार को वह वेव कर सकती है । अब आपकी निष्ठा की बात कहता हूं । आप बहुत कहते हैं । वित्त मंत्रीजी ! आप इस राज्य का इन्तजाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सरकार की किसी बात में निष्ठा है ही नहीं । एक स्मग्लिग करने वालों का नेता है ग्रेन्स का, वह बहुत मुश्किल से पकड़ा गया । आप कहें कि नहीं पकड़ा गया क्योंकि आपके साथ मिलता रहता है यू.पी. की पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको ६ महीने की सजा हो गई और हाई कोर्ट तक सजा बहाल रही और चुनाव का मौका आया और वह जेल से छूट कर आया तो कांग्रेस ने देखा कि कोई चारा नहीं रहता जब तक कि उसको खड़ा नहीं करते हैं तो वे हमारी राज्य सरकार के पास आये और उनसे निवेदन किया कि नैतिक अपराधी को ६ वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जाय; उस बात को किसी तरह से हटा दें तो यह सरपंच बन जायेगा और उसके बाद प्रधान बन जायेगा तब हमारा वहां पर राज्य चलेगा । अगर आप निष्ठावान थे और आप चाहते थे कि चोरों को प्रोत्साहन न मिले तो आपका काम था कि उसको फटकार देते, लेकिन आपके राज्य सरकार के मंत्रि-मंडल ने उसको वेव किया ।

(व्यवधान)

उसके बाद वह सरपंच बना और आज पचायत समिति का प्रधान है, लेकिन केन्द्र

Page No 89

(श्री नत्थीसिंह)

व राज्य के मंत्री के साथ वे बैठते हैं, जिस आदमी को किसी राजनैतिक दल का संरक्षण प्राप्त है। वह डोरीलाल सरपंच है। उसको मुख्य मंत्री जी के यहां से इजाजत मिली है और उस इजाजत के बाद आप चाहते हैं कि वहां के कर्मचारी किसी भी तरह से उस आदमी पर कन्ट्रोल करें यह मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में आपने क्या किया है? इसी प्रकार दूसरे बोर्डर पे......

श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०) : वह सरपंच वाकई इस तरह का था। वह अब सरपंच चुना गया और अब प्रधान भी चुन लिया गया है। वह वाकई इस तरह का है।

श्री उमरावसिंह ढावरिया (बनेड़ा) : आप इस तरफ आ जाइये।

श्री नत्थीसिंह : इसको रोकने के लिए जो दूसरी बात की है वह मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि खानपुर, का सरपंच था वह व्यक्ति इस बार नहीं चुना गया पहले था, वह गोविन्दनारायण था। राजस्थान की पुलिस उसको नहीं रोक पाई स्मग्लिंग करने से। यू. पी. की पुलिस ने उसका मुकाबला किया, और लाठियां चलीं। वह पुलिस के आदमियों को घायल करके भाग आया और वहां से वारन्ट दिया यहां की पुलिस को। दुर्भाग्य की बात है कि वह थाने में गया सिफारिश करने के लिए कि फलां आदमी का कुछ नहीं करना। थानेदार ने उसको दिखा दिया कि तुम्हारे नाम यहां वारन्ट आया हुआ है और तुमको गिरफ्तार करते हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि थानेदार को हटाया गया, उसके घर में चोरी कराई गई और वह थानेदार पड़ा हुआ है लाइन्स में। आप लोगों का इन्तजाम करना चाहते हैं तो कैसे इन्तजाम होगा? उनके मोरल को आप डाउन करते हैं, स्वयं राजस्थान सरकार इस प्रकार से करती है। ऐसी हालत में आप चाहते हैं कि वे लोग इन्तजाम कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, उप-गृह मंत्री जी को बुला दीजिये। यह बहुत ही सीरियस मसला है। इस मसले का जवाब मिलना चाहिए। गृह मंत्री नहीं तो कम से कम उपगृह मंत्री को उपस्थित रहना चाहिए। वित्त मंत्री जी उसका क्या जवाब देंगे?

श्री नत्थीसिंह : अब मैं सरकार की निष्ठा के मामले की दूसरी बात कहना चाहता हूं। एक तरफ तो यह बात कही और दूसरी तरफ मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने जब कन्ट्रोल का जमाना आया और इस कन्ट्रोल के मामले में आपकी यह प्रणाली रही......

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण को सीमित करें।

श्री नत्थीसिंह : मैंने बहुत कम टाइम लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : २० मिनिट हो चुके हैं और मुझे बहुत सों को मौका देना है ।

श्री नत्थीसिंह : तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट एन्टरप्राइज़ वाले लोगों को सहायता नहीं देते हैं, इसलिये कोऑपरेटिव्ज़ के जरिये वितरण कराया जाय । कन्ज़्यूमर्स को ग्रॉपरेटिव सोसाइटीज़ और दूसरी मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनाई जायं, उनको हम काम देंगे और उनके जरिये कंट्रोल्ड कोमोडिटीज़ का वितरण होना चाहिये । कन्ज़्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गईं लेकिन आपके अधिकारियों ने इस व्यवस्था को नाकामयाब करने का प्रयत्न किया । नतीजा यह हुआ कि किसी के जरिये चीनी वितरण का काम कराया गया तो किसी को गेहूं वितरण का काम मिला, लेकिन इसमें भी यह किया कि किसी को समय पर चीज नहीं दी और किसी को चीज दी तो इतना ज्यादा परमिट दे दिया कि उनकी सारी मनी का ब्लॉक कर दिया और जिन प्राइवेट लोगों ने सिन्डीकेट बनाया था उनको समय पर परमिट मिलते गये और उनका माल पहले निकलवाया गया और सबके ऊपर उन लोगों को प्राथमिकता दी गई और कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज़ का ऐसा नक्शा पेश किया कि मानो ये काम नहीं कर सकतीं । यदि आप चाहें तो मैं प्रमाण पेश कर सकता हूं, लेकिन अभी उसके लिये समय नहीं है लेकिन सहकारिता की डिमान्ड आयेगी तब मैं बताऊंगा कि कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज़ के माल को डेढ़-डेढ़ महीने तक रुकवा दिया गया इसलिये कि वे फंड्स का इन्तजाम नहीं कर सकें और प्राइवेट सिन्डीकेट वाले अपना माल निकाल दें ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : यह किसने किया ?

श्री नत्थीसिंह : आपके विभाग ने ।

श्री मथुरादास माथुर : सहकारिता विभाग ने ।

श्री नत्थीसिंह : सहकारिता विभाग तो इसके लिये लड़ रहा है । इसमें तो मैं और आप एक हैं । लेकिन मेम्बर्स के सिलसिले में, मेम्बर्स के लिये कोऑपरेटिव्ज़ चलेंगी, ये सोसाइटीज़ तभी चल सकती हैं जब उनके लिये पूरे साधन हों । आप भी इफेक्टिव मिनिस्टर नहीं हैं । कोऑपरेटिव्ज़ के माध्यम से चलाना चाहते थे, उसमें भी आप फेल हुए ।

मैं अब एक दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, वह संक्षेप में कहूंगा । आपने व्यवस्था की बात कही । बोर्डर पर पुलिस की संख्या बढ़ाई है । पुराने गृह मंत्रीजी भी अब सदन में आ गये हैं, उनको मालूम है । सन् ६२ में आप सदन में पहले बैठे थे उस वक्त भरतपुर जिले के अधिकांश सदस्यों ने शिकायत की थी कि वहां का एक थानेदार है जो बड़ा बदनाम है उसका नाम कैलाश प्रसाद है । वह बदनाम खाली इसलिये ही नहीं है कि स्मगिलग कराता है बल्कि वह आदमियों को मरवा देता है, थेफ्ट करा देता है और मामला चलने पर गवाहों को भी खत्म करा देता है । वह जहां भी जाता है वहां मकान बनाता है । उसके खिलाफ

(श्री नत्थीसिंह)

कई चार्जेज लगाये गये थे । उसको आप भी सस्पेन्ड करना चाहते थे लेकिन इतना दबाव पड़ा कि आप उसको सस्पेन्ड नहीं कर सके और ज़िले से बाहर भेज दिया ।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे तो याद नहीं है। मैं तो एक थानेदार को जानता हूं जिसका नाम है नत्थीसिंह ।

श्री नत्थीसिंह : उसको तो आप थानेदार नहीं बना पाये । अब की बार रूपवास के जो प्रधानजी हैं उन्होंने कहा मेरी जमानत न जब्त हो जाय इसलिए उसको वापिस लाया जाय । उनको आप सब जानते हैं। उसको वापिस लाया गया और भरतपुर में उसके जरिए मतदाताओं को धमकाया गया, ११-१२ वोट बढ़ भी गए लेकिन अब उसकी तैयारी स्मग्लिंग की है । उसने दूसरी कोठी रूपवास में तैयार भी कर ली । जो लोग बदमाम हैं उनको आप शह देते हैं यह तो वही हुआ जैसी कहावत है जलेबी की रखवाली कुतिया को दे दी; तो ऐसे कैसे काम होगा······

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने घंटी दे दी तो मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा । इस सरकार की नीयत समाजवाद लाने की कत्तई नहीं है । आपने राज्य कर्मचारियों को देने के विषय में बात की है लेकिन मैं कहता हूं कर्मचारियों को आपने दिया कुछ नहीं है । लेकिन आपने कहा कि वे क्लर्क बनना ही सीखे हैं । लेकिन मैं पूछता हूं कि आपने कौन सी उनको टैक्निकल एजुकेशन देने की फेसिलिटी दे रही है ? दूसरे लोगों में चर्चा है कि यह सरकार एल० डी० सीज़ के भरोसे पर ही चलती है, एल० डी० सी० सरकार इसका नाम है। वित्त मंत्री जी के बजट में भी एल० डी० सीज़ के सिवाय कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने उनको संरक्षण नहीं दिया केवल ५) रुपये बढ़ा दिये । जिस आधार पर आप काम करना चाहते हैं, सारे भाषण में यदि आपने सही बात कही है तो यही एक बात कही है । वित्त मंत्री जी के भाषण में उनके सिर्फ उर्दू के शब्द ही हैं, बाकी सब एल० डी० सीज़ का लिखा हुआ ही भाषण है जिनको आप कोसते हैं उन्होंने कहा कि नेहरू जी के जाने के साथ ही नेहरूजी का युग चला गया। उन्होंने यह बात हिम्मत के साथ कह दी है। नेहरूजी के जमाने का आप इनका दूसरा भाषण पढ़ लें, उस समय इनको मजबूर होकर समाजवाद की बात कहनी पड़ती थी लेकिन नेहरूजी के जाने के बाद इनको हिम्मत हो गई यह कहने की कि नेहरू युग चला गया······

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्षजी, बजट भाषण पर सामान्य वाद-विवाद का यह चौथा दिन है···

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.): मेरा नंबर नहीं आएगा क्या ? हम

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

आदिवासियों के साथ यहां भी पक्षपात होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं और मैं भी कुछ विचार आपके जरिये सदन में प्रस्तुत करूंगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस साल का, ६५-६६ का बजट प्रस्तुत किया है और उसमें १ करोड़ ५५ लाख के अतिरिक्त कर लगाने का भी प्रस्ताव किया है। उसके साथ ही पिछले साल में राजस्थान में क्या कार्य हुआ और आगे के साल में क्या योजनाएं, किस रूप में कौन कौन से कार्य किए जायेंगे उनके एस्टीमेट्स किताबों के जरिए हमारे सामने प्रस्तुत किए और इस रूप में माननीय सदस्यों ने जो बोलने में भी भाग लिया, अपने विचार प्रस्तुत किए।

माननीय उपाध्यक्षजी, आपकी मार्फत इस सदन के सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह प्रजातन्त्र का युग है और उसमें जनता का मत लेकर हम अपने विचार सदन में प्रस्तुत करते हैं और लोगों की जो भावना है उसके अनुसार सदन में विचार प्रस्तुत करें और राज्य सरकार को यदि ठोस और सक्रिय सुझाव दियें जायं, विरोधी पक्ष की तरफ से और इस पक्ष की तरफ से और जो गलती हो उसको संतुलित ढंग से रखें और इस बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना सदस्यों का फर्ज है और राज्य सरकार का भी फर्ज होता है कि आलोचना जो सक्रिय रूप से की जाय उसमें तथ्य हों तो सहृदयता से कदम उठाना चाहिए और राज्य सरकार की त्रुटि हो तो खास करके साधारण जनता के अभियोग पेश होते हैं उनके निवारण के लिए सरकार को तत्पर होना चाहिए। इसके साथ ही माननीय सदस्यों से आपके जरिए ये भी शब्द अर्ज करूंगा कि सब पार्टीज़ का यह भी फर्ज हो जाता है कि जो बातें कहते हैं मामूली मसलों को बड़ा रूप देकर समाधान नहीं किया जा सकता। उसके समाधान के लिए राज्य सरकार की ओर से अलग अलग साधन उपलब्ध हैं, कोर्ट का मसला हो तो कोर्ट में तय हो सकता है। सरकारी अधिकारियों से तय होने का हो तो उस तरह से समाधान किया जा सकता है। यदि समाधान न किया जाय और पब्लिक इन्ट्रेस्ट की बात हो तो सदन में उसका जिक्र किया जा सकता है ताकि राज्य सरकार उस पर कदम उठावे। लेकिन जनरेलाइजेशन और इधर उधर की बातें करते हैं, सारा शासन भ्रष्ट है, भ्रष्ट अधिनायकवाद है या क्या क्या पर्यायवाची शब्द कहते हैं उनमें प्रजातन्त्र की भावना नहीं होती।

कई माननीय विरोधी सदस्यों ने अपनी बातें कहीं वे वास्तव में अगर समस्याओं के निवारण के लिए कही गई हैं तो निवारण करना सरकार का कर्त्तव्य है। लेकिन वेग एलिगेशन्स, पासिंग रिमार्क्स प्रस्तुत करके बाद में स्पष्टीकरण पूछा जाता है और जब उनसे कहते हैं कि फैक्ट्स रखिए तो फैक्ट्स आते नहीं हैं; तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारा मोरल स्टेन्डर्ड माननीय सदस्यों का ऐसा होना चाहिए कि बात ऐसी कही जाय जिस-

Page No 93

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

में यदि सरकारी अधिकारियों का दोष है तो उनको राज्य सरकार पर्याप्त रूप में दण्ड दे सके ।

अगर कोई दंड भी नहीं दिया जाय और किसी तरह जो सरकारी ऑफिसर भ्रष्ट है उसको सरकार ठीक करना चाहती है तो उसके लिए सिफारिश पहुंच जाती है और इस प्रकार जो राज्य सरकार करना चाहती है उसको करने में रोड़े अटकाने का प्रयत्न किया जाता है और क्योंकि यह जनता का राज्य है इसलिए जनता की विश को पूरा किया जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जब तक यह मोरल स्टेन्डर्ड नहीं बढ़ेगा और समाज है, उसमें से भ्रष्टाचार को क्लीन करने की कोशिश नहीं की जायगी और सरकार के साथ में जब तक दोनों पक्ष के मेलजोल के साथ शासन-तंत्र को सुधारने की कोशिश नहीं की जायगी तब तक यह कभी सम्भव नहीं है । किसी तरह से चाहे कितनी ही भ्रष्टाचार निर्मूल की दुहाई इधर और उधर के माननीय सदस्य दें । इसका हल कभी होने वाला नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार है वह एक के लिए भ्रष्टाचार है तो दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है । जब तक यह चलता रहेगा तब तक जनता की आस्था सरकार में दिनों दिन कम होती जायगी । यह इसलिए हमारे दोनों पक्षों का, इधर के माननीय सदस्य और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य हो जाता है कि जनता के मानस को क्लीन करना पड़ेगा । साथ ही साथ सरकार का भी यह फर्ज है कि वह एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल ठीक ढंग से सुधारे और शासनतंत्र का सुधार करे । बड़े ऑफीसरों का जहां तक सम्बन्ध है, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को कहने में मुझे हिचकिचाहट नहीं है, यह बात तो है कि बड़े अधिकारियों के नीचे जो कर्मचारी कार्य करते हैं और उनके द्वारा नोटिंग की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार जो कोई भी कार्य या कागज प्रस्तुत होता है वह चाहे कितना ही इम्पोर्टेन्ट क्यों हो वह पहले दफ्तर में चला जाता है । दफ्तर में कोई बहुत ही होशियार क्लर्क हो तो वह उस पर नोटिंग करके काम को करवा देता है । नहीं तो बहुत दिनों तक तो कागज गायब हो जाता है और वह इम्पोर्टेन्स की बात एक तरह से भुला दी जाती है । इसी-लिए जल्दी ही किसी कागज पर आर्डर करने के लिए यह जरूरी है कि जो नोटिंग की व्यवस्था है इसको इमीजियेटली दूर करना चाहिए और जो बड़े अधिकारी हैं, जो दो तीन हजार रुपये तनख्वाह के पाते हैं उनको यह सोचना चाहिए कि यह उनकी जिम्मेदारी है, जो कम्प्लेन्ट उनके सामने रखी जाती है उस पर इमीजियेटली गौर करके उस पर आवश्यक हुक्म जारी कर देना चाहिए । अगर ऐसा नहीं होता है और बीच में दफ्तर में चला जाता है तो उसमें हुक्म होने में बहुत दिन लगते है और इस प्रकार डिले हो जाती है । और आप सब जानते हैं कि "Delay defeats justice."

मैं समझता हूं कि सरकार को अपने शासन-तंत्र को कसना पड़ेगा । जब हम किसी कागज के लिए नीचे पूछते हैं, किसी क्लर्क से जाकर पूछते हैं तो वे कहते हैं कि साहब के पास नोटिंग करके भेजा है ।

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

साहब से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि नोटिंग होकर नहीं आया है । यह परिपाटी आपको बन्द करनी पड़ेगी। ज्यादातर नीचे जो काम करने वाले हैं जिनकी तनख्वाह कम है उनमें से कुछ इनएफीशियेन्ट होते हैं इसलिए वे बहुत से कागजों को गायब कर सकते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार क्यों नहीं इस दिशा में सोचती कि कितनी कम्प्लेन्ट्स होती हैं और किस आदमी के पास उसमें कार्यवाही करने में कितनी देर लगनी चाहिए। इसके लिए ऑफिसर्स को बहुत कसना चाहिए ताकि कागज वहां रुकें नहीं और ऑफिसर्स का यह फर्ज हो कि जल्दी से वह केसेज का डिस्पोजल करे। यह तभी हो सकता है जब नोटिंग की प्रथा कम हो और जो ऑफिसर्स हैं वे खुद नोटिंग करके जल्दी उस पर ऑर्डर पास करे । इसके साथ ही मैं निवेदन कहना चाहता हूं कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अच्छे होते हैं उनका जनता में भी मान होता है। मैं समझता हूं कि सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि जो ईमानदार ऑफिसर हैं उसके लिए सरकार को इनाम घोषित करना चाहिए। हमारा भी यह फर्ज है कि जो ईमानदार ऑफिसर हैं उनको हम जनता की नजर में अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। यह नहीं होना चाहिए कि जो जनता के नेता हैं वे इन लोगों को भ्रष्ट करके जनता के अन्दर बदनाम करें । मैं समझता हूं, यह नीति हमको छोड़नी पड़ेगी। हम उनको गुमराह भी कर सकते हैं और सही रास्ते पर भी ले जा सकते है । इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमारा फर्ज हो जाता है कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो जनता के मानस को भी सुधारना पड़ेगा। साथ ही सरकार का भी यह फर्ज है कि वह अपने शासन-तन्त्र को ठीक करके इसमें सुधार करे। इस तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैंने बात कही...

श्री केसरीसिंह (पाली) : यह तो उपदेश हो गया ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मिनट और लूंगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता के अन्दर जब तक प्योरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में विश्वास क्रियेट नहीं किया जायगा तब तक प्रजातंत्र की नींव मजबूत नहीं हो सकती है यह हमको मान कर चलना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार का फर्ज है कि इनएफीशियेसी के बारे में और करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में शिकायतें आती हैं तो उन शिकायतों का निवारण करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जनता इनएफीशियेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तो बर्दाश्त कर सकती है परन्तु करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बर्दाश्त कतई नहीं करती है क्योंकि इससे प्रजातंत्र की नींव कमजोर होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र के बारे में सोचना पड़ेगा। इल्लिट्रेसी को दूर करने के लिए जो जन–सहयोग की मात्रा रखी है

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

इसको कम करके सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा करके इस इल्लिट्रेसी को दूर नहीं किया जायगा तब तक इल्लिट्रेट जो किसान है वह खेती की उन्नति करने के लिए खेती के नये तरीकों को उपयोग में नहीं लायेगा। इसके साथ ही उसके अन्दर जो कन्ज़र्वेटिव भावना है उसको दूर नहीं किया जायगा, तब तक कृषि के क्षेत्र में सफलता नहीं हो सकती है। शिक्षा के लिए गांवों के लड़कों के लिए मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सैकन्डरी स्कूल की व्यवस्था होना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के लिए भी शिक्षा के पर्याप्त साधन होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सरकार से सिफारिश करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ७५ प्रतिशत लोग रहते हैं उनकी हालत को जब तक सुधारने की व्यवस्था नहीं होगी, उनकी माली हालत को जब तक नहीं सुधारा जायगा, उनके लिए मेडीकल व्यवस्था नहीं की जायगी और मेड़िकल फैसीलिटीज नहीं बढ़ाई जायगी तब तक इल्लिट्रेसी को दूर नहीं किया जायगा और दूसरी चीजें दूर नहीं की जायंगी तब तक प्रजातंत्र की भावना मजबूती से आगे नहीं बढ़ पायेगी।

इसके साथ ही जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है इसको भी दुबारा एग्ज़ामिन करना पड़ेगा...

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है। कोरम के अभाव में भाषण हो रहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो गरीबों के पास से टैक्स आता है और जो अमीरों के पास से टैक्स आता है इस टैक्सेशन के स्ट्रक्चर की पूरी तरह से सर्वे करके जो इसका इम्पेक्ट जनता पर पड़ता है उसको देखना पड़ेगा। और जहां पर पहले से ही टैक्स ज्यादा है उसको वहां कम किया जाय और जहां पहले से टैक्स कम हैं वहां उसको ज्यादा किया जाय। इस तरह टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से एग्ज़ामिन करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार को टैक्स लगाने पड़ते हैं वह क्योंकि सरकार का फर्ज है जनता की सुविधा की व्यवस्था करना, उसके लिए लगाने पड़ते हैं। लेकिन जनता की कैपेसिटी के अनुसार टैक्स लगाने चाहिए।

श्री मानधाता सिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट सरकार ने सदन में पेश किया है वह इस मकसद से पेश किया है कि सदन गवर्नमेंट के लिए ये फंड्स पास कर दे ताकि वह अपने शासन को चला सके। लेकिन जो गवर्नमेंट अपने शासन को अपक्षपातपूर्ण और नियमित ढंग से नहीं चला सकती वह फंड्स को पाने की अधिकारी नहीं हैं। इस सदन के सामने कई उदाहरण माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं जिनमें बताया है कि किस तरीके से पंचायत चुनावों में पक्षपात बरता गया है। मैं उदाहरणों को दोहराऊंगा नहीं। केवल उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस ओर

Page No 96

(श्री मानधातासिंह)

आकर्षित करूंगा कि चुनाव खत्म होने के बाद भी सरकार द्वारा पक्षपात बरता जाता है। पक्षपात करने की भावना होती है चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव के बाद भी इस पक्षपात का अन्त नहीं होता। चुनाव खत्म होने के बाद जो प्रधान विरोधी दल के बनते हैं या प्रमुख बनते हैं उनको सहूलियतें नहीं दी जाती हैं, बल्कि उनके मार्ग के रोड़े अटकाये जाते हैं...

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अभी पचास रुपये बढ़ाये हैं।

श्री मानधातासिंह : उनको काम नहीं करने दिया जाता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण बामनवास, सवाई माधोपुर जिले का रखना चाहता हूं। सवाई माधोपुर बामनवास नादोती के पहले प्रधान थे वे कांग्रेस की डी. सी. सी. के प्रेसिडेंट थे। उस डी. सी. सी. के अध्यक्ष को विरोधी दल, स्वतंत्र पार्टी के नुमायन्दे ने ७९ वोटों से पराजित किया। यह मामूली जीत नहीं है स्वतंत्र पार्टी की, लेकिन ७९ वोटों से पराजित करने के बाद भी उस प्रधान को काम नहीं करने दिया जा रहा है...

श्री मानसिंह महार (आमेर) : शेम ! शेम !

श्री रघुनाथ विश्नोई : आते ही शुरू कर दिया।

श्री मानधातासिंह : जिस रोज उसका इलेक्शन डिक्लेअर हुआ उसके बाद उसने शपथ ले ली। उस दिन से उस प्रधान को अपने पद पर कार्य करने का अधिकार हो गया, परन्तु जब वह ऑफिस पहुंचता है उस रोज वहां विकास अधिकारी नदारद मिलता है। वह विकास अधिकारी को बुलाता है तो वहां से जवाब आता है कि आप मेरे घर पर तशरीफ लायें। वह बेचारा प्रधान उसके घर पर जाता है। इसमें देखना यह है कि अगर कोई प्रधान कांग्रेस का है तो क्या किसी विकास अधिकारी की हिम्मत हो सकती है कि वह ऑफिस में नहीं आये ? लेकिन वह कहता है कि प्रधान जी, आप मेरे घर पर आइये। इस तरह का बर्ताव विरोधी दल के प्रधानों के साथ किया जाता है। यही नहीं, कुछ समय पहले विकास अधिकारी को जनता ने एक सरकारी जीप में दो लड़कियों के साथ पकड़ा था। खुद विकास अधिकारी उस जीप को चला रहे थे जबकि सरकार के इस सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं। सरकारी नियमों के अनुसार कोई भी अधिकारी जीप नहीं चला सकता। उसका ड्राइवर ही उस जीप का जिम्मेदार है और वही उसको चला सकता है। इसके अलावा यह भी समझ में नहीं आता कि दो लड़कियां उस जीप में थीं किस मतलब से जा रही थीं। उसको पकड़ने के बाद उसकी रिपोर्ट सरकार को दी गई। मगर कोई सुनवाई नहीं हुई।...

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सदन में एक भी मंत्री नहीं रहे और हम लोग बोलते रहें उसको कौन सुनेगा ? ऐसे

(श्री मानसिंह महार)

मौके पर कम से कम एक मंत्री को तो सदन में उपस्थित रहना चाहिये । मैं यह कहूंगा कि यह बहुत गलत परम्परा है । यह बहुत अनुचित परम्परा है । मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन को आध घण्टे के लिये एडजोन कर दिया जावे । फिर हम बोल लेंगे जब मंत्री आवेंगे ।

एक माननीय सदस्य : इनमें से किसी को टेम्पोरेरी मिनिस्टर......

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : (अकलेरा—सु.) : हमारे यहां पर सदियों से कुर्सियों की पूजा भी होती आई है इसलिये आप कुर्सियों को ही बोल दीजिये ।

श्री मानसिंह महार : हम इतने मूर्ख नहीं हैं ।

श्री मानधातासिंह : मैं यह कहना चाहता था...

(श्री बालकृष्ण कौल का सदन में पदार्पण)

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूं कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकारी बेंचेज पर कोई भी एक मंत्री अवश्य हो ।

श्री मानधातासिंह : ऊपर के अफसरों तक शिकायत पहुंचाई गई, मगर कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया । मैं यह समझता हूं कि एक विकास अधिकारी का इस तरह से प्रधान का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता जब तक कि उसके पीछे सरकार का भी बहुत मुमकिन हो हाथ नहीं हो क्योंकि बगैर सरकार के ऊपरी हाथ के नीचे के अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह ऊपर के अधिकारी का इस प्रकार मुकाबला कर सके ।

इसके बाद एक दफा जब वह प्रधान दफ्तर गया तो दफ्तर बन्द मिला । उसने चपरासी को दफ्तर खोलने के लिये कहा तो उसने कहा कि आप दफ्तर में नही बैठ सकते । ये सब बातें मैंने माननीय मंत्री, जो इस विभाग के हैं उनके सामने रखीं मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसके अलावा और भी कई समितियों के चुनाव हो रहे हैं उनके अन्दर चुनाव अधिकारी विकास अधिकारी हैं । उसको बदलने के लिये शिकायतें की गईं । उसका तबादला हो गया । मगर चूंकि वह कांग्रेस का सपोर्टर है चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाया, उसका तबादला कैंसल कर दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और उदाहरण में सवाई माधोपुर में करौली में प्रधान का चुनाव हुआ उसका बताना चाहता हूं...

एक माननीय सदस्य : जैसा अभी माननीय सदस्य ने फरमाया कि वह कांग्रेस सपोर्टर है, चुनावों में उसने कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाया और इसलिये उसका ट्रान्सफर कैंसल कर दिया गया, यह मेरी कोन्स्टीटुएन्सी का मामला

(एक माननीय सदस्य)

है उनको क्या मालूम है। वे तो वहां के हैं नहीं। कांग्रेस जीतती तो बात होती वहां पर विरोधी दल का प्रधान आया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मानधातासिंह : मुझे सब मालूम है। मैं करोली के बारे में अर्ज कर रहा हूं। वहां प्रधान पद के लिये दो तीन आदमी खड़े हुए कांग्रेस के विरोध में स्वतन्त्र पार्टी का एक सदस्य खड़ा हुआ। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि उसके नोमिनेशन को खारिज कर दिया गया और वह इसलिये कि जिस समय स्क्रूटनी हो रही थी उस समय उसका समर्थक उपस्थित नहीं था। मैं कहूंगा कि आज तक कहीं पर भी इस बिना पर कि समर्थक उपस्थित नहीं हो और वह खुद उपस्थित हो तो उसके नोमीनेशन को खारिज कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में मेरी रिटर्निंग ऑफिसर से बात चीत हुई। उसने यह जाहिर किया कि उसने यह सब ऊपर के इशारे से किया है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य फरमा रहे हैं यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री मानसिंह महार : आपको क्यों दुख हो रहा है? हम क्यों न कहें? कहेंगे। आपका करोली से क्या सम्बन्ध है। अफसरों से आप बेईमानी कराते हैं जब कहते हैं तो आप कहते हैं कि झूठ कहते हैं। आप कहते हैं तो हम सुनते हैं, हम कहते हैं तो आप भी सुनिये।

एक माननीय सदस्य : वे साले की मदद कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको बोलने दें।

श्री मानधाता सिंह : सवाई माधोपुर जिले के अन्दर एक सीमेन्ट फैक्टरी जयपुर उद्योग के नाम से मशहूर है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने जो भी बताया है कि वहां पर क्या हुआ सब गलत है...

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको बोलने दें। आपकी बारी आवे तब आप भी जो कहना चाहें कह दें।

श्री मानधातासिंह : उनकी जीपें पंचायत चुनावों में काम कर रही थीं। इस सीमेन्ट फेक्टरी की जीपें पंचायत चुनावों में ही क्या हनुमानगढ़ तक गईं। वे भीलवाड़ा भी गईं। कोई भी व्यापारी हो, जब तक कोई फायदा नहीं उठाते इमदाद नहीं करते हैं। उन्होंने सरकार से बहुत फायता उठाया है। इसलिये मजबूरन कांग्रेस की मदद करनी पड़ती है। जैसे फैक्ट्री ने सरकार से लोन लिया उसकी वाजिब किश्त अदा करनी थी वह उन्होंने अदा नहीं की। वाजिब अदा नहीं होने पर भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती उनके खिलाफ...

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आ गई कि जिस किश्त की शायद ये बात कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं कि वक्त पर नहीं की गई, मैं यह कहूँगा कि किश्त भी ली गई और उस पर सूद भी लिया गया। यह वही किश्त की बात हो तो मैं कहूंगा और अगर कोई दूसरी किश्त की बात हो तो वे बता दें। लास्ट ईयर की बात है। इसमें कुछ डिले हो गई तो किश्त भी ली गई और ब्याज भी लिया गया।

श्री मानधातासिंह : मैं यह कह रहा था कि समय पर किश्त अदा नहीं की गई। आप कहते हैं कि सूद भी लिया गया और उनसे वसूल किया गया, मैं यह कह रहा हूं कि समय पर किश्त वसूल नहीं की गई।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं समझता हूँ कि जब हमने किश्त भी वसूल की और उस पर सूद भी लिया गया तो फिर उनके साथ क्या रियायत की गई ? जिस आदमी ने अपना रुपया चैक से भेजा और वह चैक २५ दिन तक क्रेडिट नहीं हो सकता, उसका भी हमने २५ दिन का ब्याज लिया है।

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेडा) : आपने उनसे इन्ट्रेस्ट क्या लगाया ? यह तो आप बता दें ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इतना निवेदन करूंगा कि २५ दिन चैक केश नहीं हुआ उसका भी इन्ट्रेस्ट हमने उनसे वसूल किया है। इसलिए यह कहना है कि हमने उनके साथ कोई रियायत की, यह गलत है।

श्री अब्दुलजब्बार खां : उन्होंने कम इन्ट्रेस्ट दिया और ज्यादा इन्ट्रेस्ट वसूल किया।

श्री मानधातासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह वही है जिसके लिए माननीय मन्त्री बता रहे हैं। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि किश्त समय पर अदा नहीं होती है। इसके अलावा जो फैक्ट्री के नीचे जमीन है वह सिवाय चक की जमीन है। सन् ६१-६२ में इस फैक्ट्री ने २ लाख ८८ हजार रुपया चुनावोंके खर्चके लिए चुनाव फण्ड में दिये। और इस मामले को स्वर्गीय जयनारायणजी ने उठाया क्योंकि उसमें से केवल १ लाख २० हजार रुपया ही जिलों में पहुंचे और बाकी नहीं पहुंचे। कहा जाता है कि वह रकम सुखाड़ियाजी को दी गई और वह रकम थी उसका अकाउण्ट नहीं। उसमें से ६५ हजार रुपये उदयपुर में गये और ५८ हजार रुपये बाकी जिले के लिए। इस प्रकार बाकी जिलोंके साथ सौतेला बर्ताव किया है। बाकी जो १ लाख ६० हजार रुपयों की रकम बची उसका क्या हुआ ? उसके बारे में स्वर्गीय श्री जयनारायण व्यास ने काफी आवाज उठाई थी।

यह रियायत जो इस फैक्टरी के साथ की है……

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : यह रकम राज्य सरकार को दे दी थी क्या ?

श्री जयनारायण सावोदिया (निवाई) : कांग्रेस को दी थी।

श्री फूलचन्द जैन : कांग्रेस को दी थी तो आपको यह कहने का क्या अधिकार है कि पता नहीं है, आपको कैसे पता कि उस रकम का पता नहीं है; अगर पता है तो आइए, बताइए ।

श्री जयनारायण साजोदिया : 'आइए' का सवाल नहीं, थे ।

श्री मानधातासिंह : स्व० जयनारायणजी व्यास का पत्र निकलता था उसमें यह दिया हुआ है ।

इसके अतिरिक्त मैं एक उदाहरण और रखता हूं । पंचायतों के चुनावों के दौरान में मैंने सवाई माधोपुर जिले में काफी दौरे किये । एक दफा कुम्भारामजी सवाई माधोपुर के इलाके में आए और मलारणा चौर में मीटिंग रखी । गवर्नमेंट का यह सर्कूलर है कि कोई भी मिनिस्टर कहीं जिले में पार्टी के काम से, मीटिंग में आते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि कलेक्टर या अन्य सरकारी अधिकारी उनकी हाजरी भरे और उसके पीछे पीछे फिरें । पर कलेक्टर और एस० पी० वहां पहुंचे, पूरे पुलिस फोर्स के साथ वहां गए । रात को ११-१२ बजे मैं वापस आ रहा था, उसी रोड पर तीन माइल पर एक गांव के पास मैं खड़ा था, मेरी गाड़ी खराब थी । एस. पी. कलेक्टर की तीन गाड़ियां आ रही थी, मैंने उनको रुकने का इशारा किया, पर कोई भी गाड़ी नहीं रुकी, हालांकि कलेक्टर मेरे कालिग रह चुके हैं और एस. पी. मुझे अच्छी तरह जानते हैं, पर उन्होंने एक एम. एल. ए. के लिए यह कर्टसी भी नहीं बताई, हालांकि गवर्नमेंट का सर्कूलर इस प्रकार का है कि एम. एल. ए. के लिए पूरी कर्टसी बताई जाय । मेरी जगह यदि कोई कांग्रेसी होता, एम. एल. ए. नहीं कोई साधारण खद्दरपोश होता तो कलेक्टर, एस. पी. रुककर साथ लेते । यही तरीका विरोधी एम. एल. ए. के लिए अपनाया जाता है, यह सरकार के लिए शर्मनाक है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अर्ज करता हूं कि इस प्रकार अन्याय करने वाली सरकार ने जो बजट पेश किया है, वह स्वीकार नहीं किया जाय ।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम !

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो वित्त मंत्री महोदय ने ६५-६६ का बजट पेश किया है और अपनी बजट स्पीच में आपने कहा है कि गरीबों को राहत पहुंचाई है और महंगाई भत्ते का हमने गरीब कर्मचारी लोगों के लिए प्रबन्ध किया है । मैं निवेदन करूंगा कि आपने गरीबों को वह राहत नहीं पहुंचाई है जो कि वास्तव में गरीबों को राहत मिलनी चाहिए । उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करूंगा कि यह जो ऊंच-नीच का भेदभाव है, उसके बारे में मैं कहूंगा कि जो गरीब लोग हैं उनको कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है क्योंकि इस महंगाई का ज्यादा असर गरीबों पर पड़ा है जिन लोगों को टाइम पर कोई चीज उपलब्ध नहीं हो सकी और मजदूरी के साधन भी उपलब्ध नहीं हो सके जिनसे कि महंगाई

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

का मुकाबला कर सकें । इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दे और गरीब तबके के लोगों को राहत पहुंचाये, तभी समाजवादी समाज लाने की जो बात सरकार करती है वह पूरी हो सकती है ।

दूसरी बात हिन्दी के लिए कही । सरकार तो बहुत दिनों से हिन्दी अपना चुकी है, पर हिन्दी का पूरा उपयोग अब भी नहीं करती है । यह भी सरकार की अच्छी नीति नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बाहर ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं जहां हिन्दी का उपयोग होना चाहिए किंतु वहां इंगलिश में राजपत्र और दूसरे पत्र जाते हैं, अगर हिन्दी भाषी राज्य इस प्रकार का तरीका अपनाये तो अशोभनीय है ।

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ५ रुपया दो दफा करके बढ़ाया, यह भी ऊंच नीच की दृष्टि से बढ़ाया ठीक तरह नहीं बढ़ाया । महंगाई भत्ता बढ़ाया इसमें छोटे कर्मचारियों और बड़े कर्मचारियों में भेद रखा गया है । छोटे कर्मचारियों को जिस कदर महंगी चीज मिलती है उसी तरह से बड़े कर्मचारियों को भी महंगी मिलती है, दोनों को बराबर रूप से महंगी चीजें मिलती हैं, किन्तु छोटे कर्मचारियों का भत्ता बड़ों के मुकाबले कम है । ऐसी हालत में यह पक्षपात का और भेद का रवैया अपनाया गया है यह सरकार की विपरीत नीति है प्रजातन्त्र को सही तरीके से पनपाने में यह नीति, यह जो ढंग अपनाये हैं, उनसे सफलता नहीं मिल सकती । सरकार झूठ-मूठ का प्रोपेगेण्डा करती है कि हम समाजवाद लायेंगे, उससे गरीबों को राहत मिलेगी, ये सारी बातें गलत हैं ।

इसके अलावा दवाओं पर जो टैक्स लगाया गया है यह टैक्स बिल्कुल गलत है । हॉस्पिटलों में दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां डाक्टर बाजार से दवा लाने को लिख देते हैं और गरीबों को बाजार से दवाएं लानी पड़ती हैं, तो जो टैक्स दवाओं पर लगाया गया है इससे गरीबों पर असर पड़ता है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह टैक्स हटा दिया जाय और सरकारी दफ्तरों व विभागों में जो ज्यादा खर्चा लगाया है उसको कम करके टैक्सों में कमी की जाय तो इस बजट की भी पूर्ति हो सकती है और टैक्स में भी कमी हो सकती है तथा गरीब जनता को सस्ती दवाइयां मिल सकती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा मेरा कहना यह है कि वित्त मंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय ने अपनी स्पीच में जो सबसे आवश्यक बड़ी चीज है उसके लिए कुछ नहीं कहा, जिस पिछड़े हुए वर्ग को सहायता देने के लिए, उसे ऊंचा उठाने के लिए यहां लोकतन्त्री सरकार बनाने का विचार था उस वर्ग को सहायता देने की, उसे ऊंचा उठाने की कोई बात स्पीच में नहीं कही है कि समाजवादी समाज आए और उस गरीब तबके को राहत मिले । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे संविधान में सुविधाएं इन लोगों को दी थीं वे इन्हें मिलनी चाहिए, ये सुविधाएं इनका अधिकार है । जैसे जमीन के लिए, जमीन इनको दी जानी चाहिए थी, शिड्यूल्ड कास्ट का, शिड्यूल्ड

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

इट्राब्स के लिए सरकारी नौकरियों में १२'। पर्सेन्ट स्थान मिलने चाहिए थे, शहरों में प्लाट दिए जाने चाहिए थे, पर यह सब कुछ नहीं दिया गया। शहरों में प्लाट दिए जाते हैं, बस्तियां बसाई जाती हैं उसमें भी सरकार का पक्षपात का, भेदभाव का रवैया रहता है, प्लाट शक्तिशाली लोगों को दिए जाते हैं जो पहले से ही शक्तिशाली हैं। अगर इन नई आवाद होने वाली बस्तियों में इन लोगों को, पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को भी मिले जुले रूप से नहीं बसाया जा सकेगा तो इनके संस्कार भी ठीक नहीं हो सकेंगे। सभ्यता के पास जाकर फटकेंगे तक नहीं तो सभ्यता कहां से इन लोगों में आ सकेगी।

वर्तमान सरकार की नीति ऐसी रही है कि अलग वस्ती बसाकर इन पिछड़े वर्ग के लोगों को अलग बसाती है, यह गलत नीति है, यह तो वही पुराना रवैया है कि फलां कौम का, यह नीची कौम की बस्ती, यह ऊंची कौम की बस्ती, इस प्रकार की भेदभाव की नीति से बस्तियां बसाती है, यह गलत तरीका है।

अनुदानों की मांगोंपर मन्त्री महोदय ने कहा है कि इतनी जमीनें खेतिहर को दी है भूमिहीनों को दी है। मैं निवेदन करूंगा कि जितनी भूमि अलॉट की है, वह शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को अलॉट नहीं हो सकी है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सिवाय चक जमीनें और नहरों की भूमि इन पिछड़े लोगों को दी जाय ताकि इन लोगों की गरीबी का इलाज हो सके।

एक तरफ तो सरकार कहती है कि छुआछूत को कम करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ सरकार का ऐसा रवैया है कि गांवों में जो कुएं सरकार बनाती है वहां कुए सब कौमों के लिए अलग २ कुएं बनाए जाते हैं इससे छुआछूत बढ़ती है इसमें सरकार दोषी है, छुआछूत को कम नहीं करते हुए छुआछूत को बढ़ाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि कुए अलग अलग नहीं बना कर सरकार छूआछूत को कम करने की कोशिश करे। आगे उपाध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि जो सरकारी हॉस्पिटल अलग अलग खोले जाते है उसमें भी सरकार की गलत नीति है, बच्चों को जाति के अनुसार अलग रखा जाता है और इससे सरकार जाति प्रथा को बढ़ावा देती है।

(४.०० म० प०)

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : छुतछात कैसे बढ़ रही है ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : मेरा मतलब है, छात्रावासों में सब जातियों के बच्चों को एक ही जगह रखा जाय, इससे छुआछूत कम हो सकती है, इससे देश की काफी उन्नति हो सकती है। जो छात्रवृत्ति सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अनिवार्य रूप से कर रखी है उसमें भी जहां तक मैंने देखा है, पांच दस स्कूलों में मैंने जाकर देखा है, जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं, उनमें छात्रवृत्ति बिल्कुल नहीं मिलती है। थोड़ी बहुत छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग के भू जाती है उसमें एक-आध बच्चे को छात्रवृत्ति मिलती है वर्ना जो अनिवार्य रूप से रखी है और वह

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

न मिले, तो यह सरकार की गलत नीति है। इसलिए जिन सुविधाओं का संविधान में प्रावधान है, वह पूरे रूप से दी जाय। यदि सरकार की नीति है कि पिछड़ा वर्ग ऊंचा आए तो जब तक फैसिलिटी नहीं मिलेगी तब तक वे ऊंचे नहीं आएंगे। इस महंगाई से पिछड़े गरीब लोग इतने परेशान हैं कि बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अगर सरकार थोड़ी सहायता दे तो अच्छी उन्नति होगी।

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

सरकार ने उद्योग भी उन्हीं लोगों के पनपाये हैं जो बड़े लोग हैं, जो पहले से ही शक्तिशाली हैं। उद्योगों के लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछड़े वर्ग को उद्योगों को स्थापित करने में सरकार सहायता करे। जब तक सरकार उनको साधन उपलब्ध नहीं करेगी तब तक ये गरीब लोग उद्योगों को स्थापित नहीं कर पाएंगे। उनको सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलना ही चाहिये। एक चमड़ा उद्योग था जिसको कोई भी करने को तैयार नहीं है लेकिन पिछड़ी जातियों के लोग करते हैं, हमारी सरकार की ऐसी गलत नीति है जो सरकार ने इस पर तीन जगह सैल्स टैक्स लगाया, कच्चे पर दोपरसेंट, पक्के पर दो परसेंट और फिर खरीद २परसेंट, तो यह जोतीन जगह पर टैक्स लगता है उसको खत्म किया जाय। चमड़े का थोड़ा बहुत उद्योग था वह खराब हो गया है।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

जहां तक शिक्षा का संबंध है, वह राजस्थान में दूसरे राज्यों के मुकाबले में नीचे है, इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और गांवों में एग्रीकल्चर तथा साइन्स के विषय जरूर पढ़ाये जाने चाहिए जिससे किसानों के बच्चे तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके जब बाहर निकलें तो रोजगार में लग जायं और आधुनिक ढंग से खेती करें ताकि अन्न का उत्पादन बढ़े और इससे सरकार की मन्शा भी पूरी हो सकती है।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत १९६५–६६ का आय-व्ययक का जो ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत हुआ उसको लेकर सदन के माननीय सदस्यों ने चार दिन से बराबर अपने विचार रखे हैं। इस मोके पर माननीय सदस्यों से आशा की जाती है कि वे जो गत वर्ष गुजरा है उसमें जो आय-व्यय हुआ, उसमें जो कमियां रहीं, उसमें जो वृद्धियां रहीं उस बारे में विचार रखें और आने वाले आय-व्यय का ब्यौरे पर अपने विचार रखकर और जो कुछ भी आगे आने वाली सरकार की तरफ से मुख्य डिमांड होगी, उस बारे में अपने विचार रखें। मुझे इस बात का दुःख है कि इस बहस के अन्दर कुछ माननीय सदस्यों ने भाषणों के अलावा हमें कोई ऐसा आशाप्रद रास्ता नहीं बताया जिसकी वजह से वित मंत्री ने जो १,५५,००,०००) के कर लगाए थे और जो इस प्रकार ये जिसका कॉमन मैन पर डाइरेक्टली असर नहीं पड़ता है, उसको न लगाकर कोई दूसरा रास्ता या सुझाव हमको नहीं मिला।

माननीय सदस्यों ने और खास तौर से विरोधी दल के नेता ने अपने भाषण की

(श्री मथुरादास माथुर)

शुरूआत की और उसके बाद में दूसरे माननीय सदस्यों ने कुछ खास मुद्दे रखे । मैं पहले उन मुद्दों का उत्तर देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं । विरोधी दल के नेता ने भी और जयपुर से आने वाले जनसंघ के माननीय नेता ने यह बात कही कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना जब २३६ करोड़ की बनो थी और जिसमें राजस्थान सरकार की तरफ से ८० करोड़ रुपये इकट्ठा करना था वह हमारा हिस्सा था और १५६ करोड़ भारत सरकार से मिलने वाले थे । हमने जब अपनी तीसरी योजना का सीलिंग २३६ करोड़ से घटाकर कम कर दिया तो उस वक्त हमारा जो ८० करोड़ का हिस्सा था वह भी कम कर देना चाहिये था । इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस ८० करोड़ के अन्दर जो ३२ करोड़ रुपये जो कर से वसूल किए पंचवर्षीय योजना में, उसमें उन्होंने दिलचस्पी दिखाई और वह रुपए वसूल कर दिए और बाकी मुद्दों के अन्दर कमजोरियां बताईं । इसलिए जनता ने कुर्बानियां करके टैक्स दिए और उसके बाद में भी २३६ करोड़ रुपए, जो हमारी योजना थी वह पूरी नहीं कर सके और उसको वजह से जो हमारे फिज़ीकल टार्गेट्स थे वे पूरे नहीं हुए ।

उपाध्यक्षजी, जो ८० करोड़ पंचवर्षीय योजना के अन्दर राजस्थान की जनता, चाहे वह कर के रूप में दे, चाहे वह कर्जे के रूप में दे, चाहे स्माल सेविंग्ज़ के रूप में दे, रुपया सब जनता से आता है । कर एक तरीका होता है । हमारी कभी यह मन्शा नहीं थी कि जो प्लान सीलिंग २३६ करोड़ रुपए की थी उसको कम किया जाय । मगर कुछ हालात ऐसे बने जिनकी वजह से ८० करोड़ रुपये जो हम २३६ करोड़ रुपए की योजना में डालना चाहते थे नहीं डाल सके । उसके कुछ कारण थे । सबसे बड़ा कारण एमर्जेन्सी का था । इधर कुछ रिसोर्सेज स्कैर्यसिटी कन्डीशन्स में डाइवर्ट करने पड़े और उसके साथ साथ माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो दस करोड़ रुपया अल्प बचत योजना से आंका था वहां पांच करोड़ रुपया ही वसूल हुआ और पांच करोड़ रुपया वसूल नहीं हो पाया । मैं आगे जाकर बताऊंगा । आप से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो पांच करोड़ रुपया वसूल हुआ, बाकी का वसूल नहीं हुआ सो यहां घाटा रहा पांच करोड़ का । उसके अलावा जमीन बेच कर रुपया वसूल करना चाहते थे, बेटरमेंट लेवी से वसूल करना चाहते थे, १४.६७ करोड़ रुपया नहीं कर सके, इसमें इसलिए घाटा रहा ।

इसके साथ साथ राज्य सरकार ने जो कर्जा लिया उसकी अदायगी हमें करनी पड़ी । २३.६ करोड़ जो कर्ज लिया उसकी खंदियां भी हमें देनी पड़ी । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार ने कोई कसर रखी हो । योजना के अलावा २३ करोड़ रुपया हमको चुकाना पड़ा तो वह रिसोर्सेज में से ही तो चुकाया गया । कुल मिलाकर असर यह हुआ कि २३६ करोड़ की योजना को कम करना पड़ा । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बेटरमेंट लेवी के सवाल में विरोधी दलमें बैठने वाले माननीय सदस्यों ने विचार रखे, चर्चा हुई थी । राज्य सरकार की यह नीति रही है कि जहां उन

(श्री मथुरादास माथुर)

इलाकों में पहले पानी डाला जाता है कुछ अर्से तक बेटरमेंट लेवी नहीं ली जाती है; जब तक मेच्योरिटी नहीं आ जाती है तब तक बैटरमेन्ट लेवी नहीं ली जाती है। लोगों को एन्करेज करने के लिए जो ईरिगेशन पोटेन्शियल पैदा कर दिये हैं उनका इस्तेमाल करें तो ही बेटरमेन्ट लेवी वहां ली जाती है। गंगानगर इलाके में बेटरसेन्ट लेवी है वह माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है।

जहां तक जमीन बेचने का सवाल है वह तो जब चाहें तब बेच सकते हैं। वह तो राजस्थान की पूंजी है। वह कहां जाती है? यदि उस जमीन का पहले विकास किया जाय और विकास से पूर्व यदि उस जमीन को बेचा जाय तो उसकी कीमत कम मिलेगी और बाद में बेची जायगी तो अधिक मिलेगी। कम कीमत में उसको बेचना मुनासिब नहीं समझा गया। इसलिए इस कारण से ये सब बातें हुई हैं। माननीय सदस्यों के दिमाग में कोई भ्रम हो कि राज्य सरकार द्वारा टैक्स लगाने के अन्दर टैक्स लगाने की मशीनरी ने ही काम किया हो और बाकी जगह कोई काम न किया हो और बाकी जगह रुपयों की वसूली रही हो तो यह भ्रम उनको निकाल देना चाहिये। विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने कहा कि टैक्स तो पूरे वसूल कर लिए लेकिन योजना पूरी नहीं की, यह भी भ्रम उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिये। जहां फिजिकल टार्गेट्स से रुपया कम करना पड़ा वहां फिर भी इतनी कटौती नहीं की और उनको पूरा करने की कोशिश की। उनका ब्यौरा आगे चल कर मैं आपके सामने रखूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, कृपया यह बतायें कि २३ करोड़ रुपये जो आपने भारत सरकार को चुकाये, जो आपने कभी उधार लिया था, वह किन शर्तों पर उधार लिया था? इसे प्लान बनाते समय पूरा ही क्यों नहीं किया गया जिससे यह इन्स्टालमेंट देनी पड़ी?

श्री मथुरादास माथुर : यह दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में लेना पड़ा। उसकी सदन में चर्चा हो चुकी है। सदन के सामने इसलिए मैं नहीं लाया। वह रुपया लेना पड़ा है। उसी रिसर्सेज से तो ये निकाले हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसका मतलब यह है कि सैकन्ड फाइव ईयर प्लान का थर्ड फाइव ईयर प्लान में असर इतना पड़ा कि उसमें कटौती हो गई और सैकन्ड फाइव ईयर प्लान के लिए रुपया लिया, थर्ड फाइव ईयर प्लान की शुरूआत में रुपया लिया इसके कारण थर्ड फाइव ईयर प्लान में कटौती करनी पड़ी, इसका कन्क्लूजन किस पर है?

श्री मथुरादास माथुर : एक बात पर हुआ है कि सैकन्ड फाइव ईयर प्लान में टार्गेट्स को फुलफिल करने के लिए अधिक लेना पड़ा, आवश्यकता पड़ी, इसलिए तीसरी योजना में उसको चुकाना पड़ा। टार्गेट्स यहां पूरे हुए। स्कूल यहां खुले, अस्पताल यहां खुले। वहां तो एक इमेजरी लाइन है, पोलिटिकल लाइन समझिये। दूसरे देशों ने, रूस वालों ने भी सात सात साला योजना

(श्री मथुरादास माथुर)

बनायी है, सात साला योजना बनाते हैं। आखिर रुपया लगा और यह क्लीयर है कि फिजिकल टॉर्गेट्स पूरे किये, इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी में खर्च किये गये। उसकी अदायगी की गई, इस कारण सीलिंग में यहां कमी हुई।

मेरा ख्याल है, मेरे इस एक्सप्लेनेशन से माननीय सदस्यों को संतोष हुआ होगा, खास तौर से उन लोगों को जिनका यह इम्प्रेशन है कि हमारा दूसरा कोई काम नहीं है और हम टैक्स लगाने तक ही महदूद हैं, और बाकी काम नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है। सब जगह कोशिश की गई है। जो यह दलील दी है कि जमीन पड़ी है, बेटरमेन्ट लेवी जमीन से आमदनी होती वह उससे वसूल करते...

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी सरकार के रहने के बाद तो और ज्यादा थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : (कृषि मन्त्री) हमारी नहीं रहेगी और आपकी आयगी तो क्या ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : बीस साल में भी नहीं बेचें तो आपको क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : आप अन्त में प्रश्न पूछ लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने तीसरी पंच साला योजना में जो रिवाइज्ड आंकड़े हैं, जितनी धन-राशि ज्यादा से ज्यादा हमारे इकोनोमिक डेवलपमेन्ट के लिए, सोशियल कन्डीशन्स को ठीक करने के लिए और इमर्जेन्सी को देखते हुए जो रिवाइज्ड टार्गेट्स से सदन को अवगत कराया था उनको पूरा करने की कोशीश की और कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, एक बात जो जनसंघ के नेता ने यहां रखी थी, मेरा ख्याल है कि उन्होंने यह कहा था, कि शायद मैं उनको गलत समझा होऊं, चौथी पंच साला योजना के बारे में यह कहा था, पहली दूसरी तीसरी पंच साला योजना का आउट ले टोटल से करीब ४०५.७७ करोड़ होती है वह उतनी होनी चाहिए थी। मगर उन्होंने, शायद मेरा ख्याल है कि उनकी अरिथमैटिक कमजोर मालूम पड़ती है, इसलिए ४०५.७७ टोटल होता है; हमारी चौथी पंचशाला योजना ज्यादा बननी चाहिए, ४३८ करोड़ की, अगर उनकी बात माने तो ज्यादा बननी चाहिए थी। सदन कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहेगा कि योजना अधिक न बने, लेकिन रिसोर्सेज जो हम मोबिलाइज कर सकते हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। भारत सरकार के शेयर के बारे में यह कहा था था कि ६० पर्सेन्ट लेना चाहिए। चौथी पंच साला योजना के विषय में जो हमने आपको एक डाक्यूमेन्ट दिया था उसको आपने पढ़ा होगा, हम तो यह चाहते हैं कि ६५ प्रतिशत योजना को पूरा करने का भारत सरकार से हमको हिस्सा मिलना चाहिए।

किसी योजना को बड़ा बना देने से इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी, इकोनोमिक ग्रोथ

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं होती। योजना चाहे कितनी ही बड़ी बना दें, योजना के अन्दर जब तक पर्सेन्टेज एन्ड पोटेन्शियलीटीज ऑफ इन्वेस्टमेन्ट और नेशनल इनकम ये दोनों आप मोबिलाइज़ नहीं कर लेंगे और दोनों मोबिलाइज होकर आपकी सेविंग्ज़ की केपेसिटी नहीं बढ़ जावेगी और सेविंग्ज़ की केपेसिटी जब बढ़ेगी तब एक्स्पेन्डीचर रिड्यूस करेंगे और एक्स्पेन्डीचर रिड्यूस करेंगे जब प्रोस्टिरिटी आवेगी। किसी योजना-बद्ध विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इस इन्टेरिम पीरियड में इसका मुकाबला करना पड़ता है। एक नया जमाना पैदा हो रहा है। एक बर्थ पेंग और एक डेथ पेंग है। पुराना भारत मर रहा है और आधुनिक भारत निकल रहा है। योजना बनाना हो तो इन्वेस्टमेन्ट, सेविंग्ज़ की केपेसिटी बढ़नी चाहिए तब जाकर इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी आयगी। आउटलेट बड़ा कर देने से इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी आगे नहीं बढ़ती। वह तो एक तरफ से समाज कल्याण का काम होता है। इकोनोमिक डेवलपमेन्ट के लिए ज्यादा काम होना चाहिते। राजस्थान में कई हालात में से गुजरे हैं। दस करोड़ रुपया जहां अल्प बचत योजना से प्राप्त करना चाहते थे वहां पांच करोड़ ही कर सके।

दस करोड़ का इनवेस्टमेन्ट नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन मैन का कोन्ट्रीब्यूशन गिर गया। आज लोगों की हेबिट्स में बहुत तब्दीली आने की जरूरत है। आज लोग मौसर के अन्दर खर्च कर देते हैं, शराब खोरी के अन्दर खर्च कर देते हैं, इस प्रकार से जो नॉन प्रोडक्टिविटी के आइटम्स हैं इन पर खर्चा कर देते हैं, इस कारण विकास के काम में यह पैसा नहीं आ सकता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : शराबखोरी को बन्द कर दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : बहुत टैक्स लगा दिये हैं; इससे कम हो रही है।

[illegible] जब तक हमारे लोगों में बचत की आदत नहीं होगी और वह पैसा विकास के लिये वे नहीं लगायेंगे हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। इसलिए केवल बड़ी योजना रख देने से काम नहीं चलने वाला है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है, उन्हें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए और जैसा कि वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में सदस्यों से अपील की, लोगों को स्माल सेविंग्ज़ में अपना पैसा लगाने के के लिए प्रेरित करें इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देश की सम्पति बढ़ेगी और उसके साथ साथ पर-केपिटा इनकम में वृद्धि होगी। उपाध्यक्ष महोदय पर केपिटा इनकम के बारे में मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार प्रगट करते हुए ब्योरेवार उनको समझाने की कोशिश की थी, इसलिए अब उसमें ज्यादा समय लेना नहीं चाहता लेकिन पर केपिटा इनकम के बारे में एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं। यह सही है कि किसी भी देश की या प्रान्त की प्रोस्पेरिटी का इन्डीकेटर वहां पर केपीटा इनकम ही है। इसका मुकाबला करते वक्त अपने यहां के हालात को सामने रखना होगा, पर केपीटा इनकम हमारे यहां दो पोइन्ट या तीन पोइन्ट कम

(श्री मथुरादास माथुर)

हो गई, यह प्रशासन की खराबी है, इनकम गिर रही है; एक दम प्रशासन पर इसके लिए पहुंच जाना सरासर गलती है ।

उपाध्यक्षजी, राजस्थान के अन्दर ऑल इन्डिया एवरेज के मुकाबले जो आबादी के आंकड़े हैं वे दूसरे प्रान्तों से ज्यादा हैं । हमारे यहां आबादी ऑल इन्डिया एवरेज से ज्यादा बढ़ती है, पर ईयर ग्रोथ हमारे यहां का अन्य प्रांतों से बहुत अधिक है ।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान ने तरक्की ही इसी पोइन्ट पर की है ।

श्री मथुरादास माथुर : आप लोगों की मेहरबानी से है । ऑल इन्डिया पर ईयर ग्रोथ २. ५ परसेन्ट है और राजस्थान में २.६ परसेन्ट है । आप लोगों की इत्तिला के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि पर ह्यूमन एक उम्र के अन्दर हमारी राजस्थानी महिला ६ बच्चों को पैदा करती है, पंजाब इसमें हमारे से कुछ आगे है वह ६.७ और हम ६.५ हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपको कम्पेरिजन ही करना है तो बंगाल से करिये ना ।

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्दर फर्टीलिटी का सम्बन्ध है, इस मामले में हिन्दुस्तान में दूसरा नम्बर आता है । पोपुलेशन का ट्रेन्ड राजस्थान में २.६ है जबकि एवरेज नेशनल पापुलेशन का २.५ है । यदि हम तरह से स्टेट इनकम को इसमें डिवाइड करते हैं तो हम नीचे जाते जायेंगे । जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि यह आंकड़ों की जुगलरी है । मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, केलकुलेशन की जो मेथोडोलीजी है उसमें भिन्नता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह जस्टिफिकेशन है कि पर केपिटा इनकम नहीं बढ़े ।

श्री मथुरादास माथुर : मजबूरी है । जब आप यहां की आमदनी को इस प्रकार से घटाते हैं तो वह आयगी । आप दिल्ली से कम्पेयर कर लें । दिल्ली में पर-केपीटा इनकम ऑल इन्डिया एवरेज से टोप हैवी है । इसकी वजह है; वे कोई मानसून पर डिपेन्ड नहीं करते, वहां पर खेतीबाड़ी से आमदनी का सवाल नहीं, वहां पर इण्डस्ट्रीज हैं जो स्टेबल रहती हैं, इसलिए वहां पर-केपिटा इनकम ऊपर बढ़ जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : हम और स्टेट्स के मुकाबले कहां ठहरते हैं, यह बतलाइए ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर चुका हूं २७६ पर-केपिटा इनकम के फीगर्स दिए थे । लोकनाथन की रिपोर्ट को मैंने पढ़कर सुनाया था । आप कहते हैं २६७ है । उसके अन्दर मैथोडोलोजी मे डिफरेन्ट है, तरीका डिफरेन्ट है केलकुलेशन का ।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि बाकी स्टेट्स के मुकाबले हमारा कौनसा नम्बर है ?

श्री मथुरादास माथुर : बाकी की स्टेट्स के मुकाबले हमारा छठा नम्बर आता है ।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्रीजी के हाथ में जो कॉपी है उसमें से बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : वही किताब है जिसका मैंने जिक्र किया था। वह ५७-५८ की प्राइस की बेस पर था और यह ६०-६१ की प्राइसेज पर है। बड़ी मुश्किल होती है "नीम हकीम खतरे जान" है, फीगर्स में कम्पेरिजन का काम इसी प्रकार का होता है। आप ५७-५८ पर कम्पेयर करते हैं और कहते हैं कि हमारी पर-केपिटा इनकम गिर गई, हम बरबाद हो गए। यह बात नहीं है। राजस्थान बहुत तरक्की कर रहा है। हमें इतना जरूर देखना है कि विकास का जो क्रम है उसमें डिफरेन्स ऑफ ओपिनियन हो सकती है। हमने जो मेथोडोलीजी एडॉप्ट की है, हमने कोमन मेथोडोलोजी को एडॉप्ट किया है। बहुत से फर्म प्राइम पर केल्कुलेट करते हैं, कुछ ग्रोस प्राइस पर केल्कुलेट करते हैं, इससे कुछ डिफरेन्स आ सकता है। ३५५ रुपया थर्ड प्लान के अन्त तक हो जायगा। आपने कहा था, वादा किया था लेकिन आपके कहने के अनुसार ३१५ भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हम तो यह मान कर चलते हैं कि इण्डिया के लेवल पर तो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि हमारे दो-तीन साल ऐसे गुजर गए जिन सालों में स्केर्यासिटी काफी रही है, फिर भी हम आशा करते हैं कि ऑल इण्डिया लेवल से १०-१२ पोइन्ट्स का डिफरेन्स रखा जायगा।

श्री भैरोंसिंह : करेन्ट प्राइस बेसिस पर नहीं हो सकता।

श्री मथुरादास माथुर : आपने जो बताया है वह ४८-४९ प्राइस लेवल का बेसिस लिया है जबकि मैं ५४-५५ के प्राइस लेबल के आधार पर कह रहा हूं।

इसके अलावा आपने सेन्ट्रल असिस्टेन्स की जो बात कही थी उसके बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। हम बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से हमें अधिक से अधिक रुपया मिले।

एक बात और कही गई। वह यह कि राजस्थान के अन्दर जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा लेन्ड रेवेन्यू है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूं कि वे मुकाबला कर लें, जो उनके पास किताबें हैं वे ले आयें; राजस्थान का ओन एन एवरेज एक एकड़ पर ८४ पैसा हमारे यहां लेण्ड रेवेन्यू है जो हिन्दुस्तान के सब प्रान्तों से कम है।

तो ये फिगर्स हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ये कैसे केल्कुलेट किये ?

श्री मथुरादास माथुर : बुक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, कागज हैं उन पर से।

श्री भैरोंसिंह : लैंड रेवेन्यू को पर कैपिटा पर डिस्ट्रिब्यूट किया जावे तो वह तो उससे भी कम आवेगा।

श्री मथुरादास माथुर : आपने भूल भुलैया में डाला। पर कैपिटा के आधार पर, आबादी के आधार पर निकाल कर बता दिया। राजस्थान की आबादी अधिक है,

(श्री मथुरादास माथुर)

आप तो खेतों पर निकालते इसका कैल्कुलेशन। आबादी के आधार पर निकाल कर बता दिया तो मुखियाजी, आपकी अटकलबाजी को हम भी समझते हैं। इसलिए राजस्थान के अन्दर लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं तो जमीन की बात करिए। पर कैपिटा एक एकड़ पर लेंड रेवेन्यू हिन्दुस्तान के सभी सूबों से यहां कम है और वह ८४ नए पैसे है। अब तो पैसे हैं ८४। इसलिए राजस्थान पर वित्त मन्त्री जी ने करों का कोई भारी बोझा डाला हो, ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बेकार जमीन कितनी पड़ी है, बेकार जमीन पर भी आपने मल्टीप्लाई कर लिया है।

श्री मथुरादास माथुर : जो कल्चरेबल लैंड है उस पर ही कैल्कुलेशन होता है, पहाड़ों पर नहीं होता है। अगर पहाड़ों पर भी, जहां खेती होती है, तो उसको भी कैल्कुलेट किया जाता है। कोरे पहाड़ों को नहीं।

फिर वह मैं अपने घर के फिगर्स नहीं दे रहा हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : बसेड़ी तहसील में ४५) एकड़ तक का लैंड रेवेन्यू है बसेड़ी और बाड़ी तहसीलों में।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो एवरेज की बात कहता हूं। आपकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में लगान ज्यादा है तो फसल भी तीन-तीन आप ही लेते हैं। जमीन भी बढ़िया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जमीन बढ़िया नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने एवरेज कहा है। हो सकता है कहीं कम हो, कहीं ज्यादा हो, कहीं चार आने, दो आने, दो पैसे भी हों। पर एवरेज एक एकड़ पर ८४ पैसे हैं। यह टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी से क्वोट कर रहा हूं। इसलिए राजस्थान में लैंड रेवेन्यू सबसे कम है। इसलिए यह जो फिज़ा बनाई गई है कि किसान के गले पर कोई बहुत बड़ा डूंगर और पत्थर या रोड़ा रख दिया गया हो, यह गलत बात है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन सर,......

श्री मथुरादास माथुर : आप क्लैरिफिकेशन बाद में कर लेना। वर्ना मैं भूल जाऊंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक स्थान पर ४५) रुपये का लैंड रेवेन्यू और राजस्थान में दूसरी तरफ कुछ आने और कुछ पैसे के हिसाब से प्रति एकड़ पर मालगुजारी है। ऐसी सूरत में क्या राजस्थान सरकार की यह नीति होगी कि वह सब जगह पर एक सी रेट कायम करे। भरतपुर की ही दूसरी तहसीलों में जहां आठ आना बीघा का लगान है उसी किस्म की जमीन का हमारे यहां २०) रुपया है।

श्री मथुरादास माथुर : आपके दर्द को अच्छी तरह समझते हैं हम। आप सैटलमेन्ट से ठीक करा लेना। आर्बिट्रेरिली मुझे इसमें कुछ करने का अधिकार भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप एक बात तो स्वीकार करते हैं कि प्रति व्यक्ति एक आध स्टेट को छोड़ कर हमारे यहां सबसे ज्यादा है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह कतई स्वीकार नहीं करता हूं। मैं जो बात कह रहा हूं वह यह कह रहा हूं कि लैण्ड के मामले में एकड़ को देखा जावेगा। आदमी को नहीं देखा जावेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ये आंकड़े किस साल के हैं ? दस साल पहले जो कमेटी बैठी थी उसके हैं या अभी कमेटी बैठी उसके ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो आप उस टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए। जमीन को मुरब्बों में आंका जाता है, मिनखों में नहीं आंका जाता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने पूछा कि किस कमेटी की है ?

श्री मथुरादास माथुर : बाद में भी हुई है कमेटी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह तो दस साल पहले की है।

श्री मथुरादास माथुर : दस साल पहले तो आप बच्चे थे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप भी ऐसे ही थे।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो आपसे बड़ा हूं।

अब दूसरा सवाल उठाया गया है वह यह था कि हमारे यहां पर पर-कैपिटा टैक्स रेवेन्यू है वह बहुत भारी है, लोग दब गए हैं, ये सब बातें हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पर कैपिटा टैक्स रेवेन्यू पर भी गौर करें तो राजस्थान का नम्बर आठवां आता है। सात ही स्टेटें राजस्थान से ज्यादा हैं। अगर राजस्थान का आंकड़ा सौ है तो महाराष्ट्र का १३५.२ है।

मद्रास का १२१.७ है।

वेस्ट बंगाल का १२०.५ है।

केरल का १२०.३ है।

पंजाब का ११५.१ है।

गुजरात का १०९.७ है।

और आसाम का १०६.६ है।

तो इसलिए......

श्री भैरोंसिंह : बाकी के, बिहार, मध्यप्रदेश जो हमारे बराबर हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं खत्म तो नहीं कर रहा हूं, मुखियाजी। मैंने आसाम का इसलिए बताया कि आप हमेशा कमैन्ट किया करते हैं कि यह तो पश्चिम की तरफ है बोर्डर पर और उसका कम्पेरिजन करते हैं राजस्थान से कि वह पूर्व की तरफ है बोर्डर पर। इसलिए मैंने आसाम क्वोट किया।

इसके अलावा अब नीचे देखिए :

आन्ध्र का ९६.८ है।

जी. एण्ड के. का ९५.७ है।

मध्यप्रदेश का ८९ है।

(श्री मथुरादास माथुर)

मैसोर का ८० है।

उड़ीसा का ७५ है।

यू. पी का ७७.७ है।

बिहार का ६५.५ है।

अब गौर करिए, देखिए। आप कहते हैं टैक्सेशन स्ट्रक्चर भारी है। पर-कैपिटा टैक्स ज्यादा थे। राजस्थान मीडिओकर स्टेट है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अन्डर कल्टीवेशन कितना लैण्ड है ?

श्री मथुरादास माथुर : बहुत सी बातें जानने की होती हैं, बोलने की नहीं होतीं। माननीय सदस्य को सन्तोष है इससे और इसलिए चुपचाप बैठे हैं।

सैल्स टैक्स के बारे में चर्चा हुई कि बहुत भारी है और हर साल फाइनेन्स मिनिस्टर उसे बढ़ाते जाते हैं। इसके बारे में भी मैं निवेदन करूं कि अगर उस पर भी हमारा नम्बर मल्टीप्लाई किया जावे तो देश में दसवां आता है। तो जहां राजस्थान का सौ है तो वहां :

महाराष्ट्र का है ३१९.३

मद्रास का २३९.२

केरल का २३८

गुजरात का २१८

वेस्ट बंगाल का २१२

मैसोर का १४८

पंजाब का १४४

आंध्र प्रदेश का १३५

और मुखियाजी आसाम का है ११५।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : "मुखियाजी" क्या बला है ?

श्री मथुरादास माथुर : यानी लीडर। तो यह जो बात उठाई गई थी कि हमारे यहां पर पर-कैपिटा सैल्सटैक्स हाइएस्ट है वह भी ठीक नहीं है, यह मैंने समझाने की कोशिश की है आंकड़ों से, जो मेरे नहीं हैं। यह स्टेटिस्टिकल विभाग ने तैयार किये हैं।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह भी कहा गया कि हमारे यहां पर हम लोग स्कूलों में, अस्पतालों में सोश्यल सर्विसेज में कम खर्च करते हैं। विकास कम है और पिछड़े हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि राजस्थान एक बहुत पुराना, सदियों पुराने फ्यूडल लीगेसी को लेकर बना है और इस राजस्थान में दस-पन्द्रह वर्षों में हजारों वर्षों की परम्पराओं और रूढ़ियों को तोड़ना सरल काम नहीं है। राजस्थान आज उन पुरानी परम्पराओं और रूढ़ियों को तोड़ कर अन्धकार से निकल कर उजाले में जा रहा है। तो इसलिये जो बात आज हम किसी से मुकाबले की करते है तो हमें यह पृष्ठभूमि भी देखनी होगी। अगर उसका मुकाबला हम बम्बई से करने जावें तो कठिन समस्या हो जावेगी। बंगाल से करने लगें तो कठिन समस्या हो जावेगी। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सोश्यल सर्विस में जो एक्सपेन्डीचर हुआ है उसमें अगर राजस्थान का अंक १०० है तो केरल का १५४.६ है।

(श्री मथुरादास माथुर)

मैं नीचे वाली स्टेज बताता हूँ उससे आइडिया होगा। गुजरात जिसे प्रगतिशील कहा जाता है, ९९.५ है। आन्ध्र प्रदेश ९७.७ है, जो दक्षिण स्टेट में प्रगतिशील गिनी जाती है। वेस्ट बंगाल जो बहुत प्रगतिशील है ९४.७, उड़ीसा में ९४.२ है और मध्यप्रदेश में ८८.१ है।

श्री अब्दुलजब्बार : इसमें ताज्जुब की बात थोड़ी ही है। वे तो विकसित हैं। उनको विकास की आवश्यकता क्या है कि वे अधिक खर्च करें? उसकी तो आपको आवश्यकता है। अन्धेरे में बल्ब लगाने की जरूरत है, उजाले में नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा नहीं है।

महाराष्ट्र में ८७,

बिहार में ९८,

और यू पी में ९१.५,

तो हिन्दुस्तान की इन बड़ी बड़ी आठ स्टेटों के ये आंकड़े हैं। वे सोश्यल सर्विस में कम खर्च कर रहे हैं। इसलिये आपने जो यह कहा कि हम वेलफेयर कन्सेप्ट को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उनके उत्तर में आंकड़े देकर यह मैंने नम्र निवेदन किया है।

श्री नत्थीसिंह : खर्चा आपने बताया; पर सोश्यल एमिनिटीज़ वहां कितनी हैं, यह नहीं देखते।

श्री मथुरादास माथुर : वह भी आ रहा है। फिर स्कूलें तो रुपयों से चलेंगी, या तसें चलती हों तो तुम लोग खोल लो बहुत सी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वहां डॉक्टर यहां आते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अभी मैं मेडिकल पर भी चला आता हूं। सोशियल सर्विस का मैंने आपको जनरल ट्रैण्ड बताया है। कितनी इम्पोर्टेन्स सोशियल सर्विस को दे रहे हैं दूसरी स्टेट्स के मुकाबिले में, उसके लिए मैंने आपको बताया......

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, यह जो आप कम्पेरीज़न कर रहे हैं यह किसी पर्टीक्युलर ईयर का दिया है या राजस्थान में पिछले दस-बारह साल में जितना सोशियल सर्विस में खर्च किया है उसका कम्पेरिजन वहां के १२ साल से कर रहे हैं? कौन से ईयर के हैं?

श्री मथुरादास माथुर : ये आंकड़े १९६२--६३ के हैं। उसके अलावा आंकड़े बन नहीं पाये। मेरे आंकड़े १९६३--६४ के हैं, चाहे तो मैं आपको दे सकता हूं।

उसके अलावा जो माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां पर डाक्टर ज्यादा हैं, यह फैक्ट है। इसीलिए तो हमने हमारे यहां कमी पूरी करने के लिए मेडिकल कॉलेज ज्यादा खोले हैं। भर्ती ज्यादा है। इसलिए बाइलोजी सब्जेक्ट्स को पढ़ाना पड़ता है और इसके बारे में हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने बयान किया। हायर सैकन्डरी स्कूल्स भी ज्यादा खोलने पड़ते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हमको सोशियल सर्विसेज के लिए

(श्री मथुरादास माथुर)

ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा । राजस्थान हमारा २ करोड़ की आबादी का प्रान्त है. इसमें ५ मेडिकल कॉलेज खुले हैं और इसको जरा गौर कीजिए कि सीरियसनेस कितनी है और एक डाक्टर का इनपुट ५,३५ है । तो इसलिए इसके लिए एफर्ट्स करने की कोई कोशिश नहीं रखी जा रही है । इसको डिमोन्सट्रेट करने के लिए जो कहा गया था कि यह बात ठीक नहीं हो रही है उसका जवाब मैंने दिया है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि दूसरी जगहों पर जो प्राइवेट इन्सटीट्यूशन्स हैं वो इतने अधिक हैं कि सरकार को उन्हें एड देने में बहुत कम खर्चा करना पड़ता है । इसलिए इस फैक्टर को भी मंत्री महोदय ध्यान में रखें और भावना में न बह जायें और यदि इन आंकड़ों के जंजाल में फंसे रहे तो गलती करेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है उसका मैं उत्तर दे ही रहा था । पर-कैपिटा इन्कम एक्सपेन्डीचर एजुकेशन के ऊपर हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा है, और जगह कम है । इसका जवाब आज आपने दे दिया । इसकी वजह यह है कि राजस्थान में जितने भी इन्स्टीट्यूशन्स चल रहे हैं वे ६८ पर्सेन्ट, ६७ पर्सेन्ट सरकार चलाती है । प्राइवेट एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स हमारे यहां पर बहुत लिमिटेड हैं । इसके कारण हैं-कुछ तो ऐतिहासिक कारण हैं; वे यह हैं कि हमारे राजाओं ने नहीं खोलने दीं, दूसरे, इन्डस्ट्रीज नहीं हुईं, इसलिए प्राइवेट कैपीटल इसमें इन्वेस्ट नहीं हो पाई । ऐसी संस्थायें गुजरात, अहमदाबाद आदि जगह पर खुल जाती हैं; लेकिन हमारे यहां पर यह स्थिति पैदा नहीं हुई । हमारे यहां जागीरदारों ने इन्स्टीट्यूशन्स के लिए पैसा नहीं दिया और यही पैसे वाले थे और हमारा प्रान्त इन्डस्ट्रियलाइज़ नहीं हो पाया इसलिए हमारे यहां तो कुछ मिशनरी स्कूल्स हैं । इसलिए हमारे यहां पर सरकार का खर्चा ज्यादा पड़ता है और जो बात आपने उठाई है हम उसको मानते हैं कि प्राइवेट लोगों को छोड़कर यहां सभी स्कूल्स सरकारी हैं और दूसरी जगह ये प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स होने की वजह से उनके ऊपर बोझ कम पड़ा और इतना विकास कर सके ।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं और भी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं; वे यह हैं कि मैं शिक्षा के बारे में आंकड़े देकर समय नहीं लेना चाहता हूं । यह मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर १०० शिक्षण संस्थायें हैं स्कूल और कॉलेज मिलाकर, तो राजस्थान में हिस्सा ५ है । फिर भी शिक्षा मंत्रीजी ने यह बात आपको कही होगी । शिक्षा मंत्रीजी और डिटेल में वक्त पर जब डिमाण्ड शिक्षा की आयेगी तब कहेंगे । मैं यह भी बताता हूँ और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि रोड्स के ऊपर बात चली थी । अब जितना मेन्टीनेन्स अपना डिपार्टमेन्ट करता है, मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान

(श्री मथुरादास माथुर)

मैं कोई नहीं करता है क्योंकि सब लोकल सेल्फ इन्स्टीट्यूशन्स वाले लोग उस काम को करते हैं। मैं बताऊं कि हमारे यहां पर जो मैसूर स्टेट है वह ३४ मील रोड को मेन्टेन करती है और बिल्ट करती है और उसके बाद में राजस्थान है और बाकी सब स्टेट्स उसके नीचे हैं। इसलिए आप इसका अन्दाजा लगायें कि कितना स्टेट के एक्स-चेकर पर बर्डन है और इसके लिए ज्यादा एफर्ट्स करते हैं टैक्स लगा कर और कोई नॉन-टैक्स रेवेन्यू करके।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): आप जो सड़कों के ऊपर खर्च करते हैं वह सही तौर से खर्च होता है या उसमें भी घोटाले होते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : कम से कम डूंगरपुर में तो सही तौर से होता है, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति निगरानी करने वाले रहते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मंत्री महोदय को डूंगरपुर का ही सब पता है, दूसरी जगह शायद बिल्कुल चिराग गुल दिखता है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा न तो यह चिराग गुल है और न यह और न नजर कम है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप डूंगरपुर के इलाके में गुजरते हैं।

मेरा ख्याल है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं और विरोधी दल के नेता से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सड़क अमूमन किसी खास जगह खराब हो तो दूसरी बात है वर्ना वह हिन्दुस्तान के किसी भी दूसरे प्रान्त के मुकाबिले में खराब नहीं है। थोड़ा यहां हाथ रख कर देख लीजिए। बीकानेर वालों की बात अलग है वह म्युनिसिपल लिमिट में है। आप दिल्ली चले जाइये; राजस्थान के बाहर ज्यों ही आप अलवर से निकलते हैं और पंजाब टेरीटरी में जाते हैं तो आप खुद ही मुकाबिला कर लें कि क्या हालत है।......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : दिल्ली से चन्डीगढ़ चले जाइये और राजस्थान से मुकाबिला कर लें।

श्री मथुरादास माथुर : आप यहां से अहमदाबाद चले जाइये और देख लीजिए। क्या बात है? मैं तो औसत तौर पर कह रहा हूं कि कम नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : भरतपुर से जयपुर तक भारत सेवक समाज हो रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : अब तो ऐसी बन रही है कि मत पूछो बात।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : १४ मील तक धूल ही उड़ती है।

श्री मथुरादास माथुर : अब नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास आंकड़े तो बहुत हैं। अगर मेरे पास से हॉस्पीटल और बैड्स के आंकड़े लिये जायें तो वे भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रिसिटी के देखे जायें तो वे भी मौजूद हैं। उसके अलावा सेन्ट्रल टैक्स में अपना शेयर कितना है, उसके

(श्री मथुरादास माथुर)

आंकड़े भी मेरे पास हैं 'Per Capita share in our Central Tax' वे तो दिये हुए हैं, आपने पढ़े होंगे ।

श्री भैरोंसिंह : एक आंकड़े और दे दें, राजस्थान की पर-एकड़ आउटपुट कितनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह मैं आगे दूंगा ।

श्री मथुरादास माथुर : आंकड़े मेरे पास में है, पर-एकड़ प्रोडक्शन के भी हैं, सब क्रॉप्स के हैं और अलग अलग लेण्ड के भी हैं । मैं इस प्रश्न का अपनी मेमोरी से जबाब नहीं देना चाहता हूं क्योंकि डेंजरस होता है । आप प्रश्न पूछ लीजिए , जितने सोइल की क्लासीफिकेशन है उसका पर-कैपिटा प्रोडक्शन कितना है, क्रोपवाइज़ मैं उसके आंकड़े देने के लिए तैयार हूं और उसमें मैं निवेदन करता हूँ कि राजस्थान को भी इस मामले में दूसरे रियासतों से प्रगति कम हो, यह बात नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि पर-कैपिटा प्रोडक्शन बढ़ा ही हो, लेकिन मैं यह भी कहने के लिए तैयार हूं कि घटने की गुंजाइश नहीं है । बड़ी अच्छी तरह से गाड़ी चल रही है ।......

श्री भैरोंसिंह : यह सब ठीक है, लेकिन यह सही है कि हमारा राजस्थान में पर-एकड़आउट पुट हिन्दुस्तान के बाकी सब राज्यों के मुकाबिले में कम है ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं यह सही नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल सही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सही नहीं है । अभी बहुत मौके हैं । मैं काफी आंकड़ों का संकलन कर रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आपकी जो सूचना है, आप खुद कनविन्स हो जायेंगे कि यह जो दृष्टिकोण है वह सही नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड रिसर्च की, उसके आधार पर कह रहा हूं जिसमें सारे फिगर्स दिए हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने उन पैरेग्राफ्स को देखा है जिसके लिए आप कह रहे हैं । आपने एक-दो बार पहले भी सवाल उठाया है । डिमाण्ड के वक्त में मैं आपको बताऊंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह आपकी सुन्दर तस्वीर को भैरोंसिहजी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पर-एकड़ का झगड़ा डालकर ।

श्री मथुरादास माथुर : न तो मैं सुन्दर तस्वीर बनाना चाहता हूँ और न बदसूरत । यह तो खुदा ने बनाई है ।

श्री भैरोंसिंह : वह कौल साहब करते हैं । राजस्थान का सुन्दर नक्शा खींचते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : वह तस्वीर नहीं है, नक्शा है ।

श्री नत्थीसिंह : उन्होंने तस्वीर लिखा है उसमें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी राजस्थान की इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वह टोटल स्टेट इन्कम के मुकाबले में कितने पर्सेन्ट है ?

श्री भैरोंसिंह : १.६५ पर्सेन्ट है ।

श्री मथुरादास माथुर : अभी बता देता हूं । राजस्थान में अपने यहां की स्टेट इन्कम है उसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी फेक्टर्स को सब को बढ़ा देते हैं, अगर १०० तक तो–

एग्रीकल्चर एनीमल हस्बैन्ड्री का	४५.८२	पर्सेन्ट
माइनिंग एण्ड फैक्ट्रीज का	२.२३	,,
स्माल एन्टरप्राइजेज... ...	३१.८४	,,
कॉमर्स...	१४.७२	,,
पब्लिक ऑथोरिटीज... ...	८.९६	,,
ट्रान्सपोर्टेशन...	६.६०	,,
डोमेस्टिक सर्विस	६.४०	,,
हाउस प्रॉपर्टी	३.७६	,,

इसका जोड़ १०० बैठता है ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने पूछा, उसका जवाब नहीं आया है ।

श्री मथुरादास माथुर : वह आ गया है । आपकी समझ में आया नहीं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माइनिंग और फैक्ट्रीज में २.२३ में क्या क्या दिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इन्ड्रस्ट्रियल सैक्टर का अलग कह दूं ।

माइनिंग एण्ड फैक्ट्रीज	२.२३
स्माल एन्टरप्राइजेज, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज, कॉटेज इन्डस्ट्रीज वगैरह	३१.८४
इन्डस्ट्रीज क्लोज्ड ।	
कामर्स	१४.७२

आपसे कौन सी चिमनी से धूआं निकलता है, वह छिपा हुआ नहीं है । आप जानते हैं । मैं फीगर्स बता रहा हूँ । पहले कितने थे और आप विधान सभा में आये तो कितने थे और अब धुआं कितना निकलने लगा है । जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं कि एयर पोल्यूट हो रही है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अभी भी धुआं नहीं निकलता है, अफसोस तो यही है ।

श्री मथुरादास माथुर : लेटेस्ट मशीनें हैं, उनमें धुआं नहीं निकलता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जयपुर से आने वाले जन संघ के मुखियाजी ने सोडियम सल्फेट का भी जिक्र किया था—

मै हिन्दी का मिनिस्टर हूँ, उसके लफ्ज़ काम में लेता हूँ । उसका मतलब आप समझ लें कि क्या है । अब लीडर का ट्रान्सलेशन आप बताइये; विरोधी दल के नेता ! लीडर का ट्रांसलेशन तो मुखिया ही होगा । अगर नेता कहूं तो इस सदन का नेता तो एक ही है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्षजी, मुखिया का अर्थ हुआ–मन्दिर में पूजा करने वाला भी मुखिया होता है ।

श्री मथुरादास माथुर : वह यहां पर नहीं है सदन में।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): इसका असली मतलब आप बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : सोडियम सल्फेट के बारे में मेरा निवेदन है कि जो यह कहा गया कि हम लोगों ने जो वेस्ट जर्मनी की बड़ी भारी कम्पनी है जिसके जरिये से हमने जो पाइलोट प्रोजेक्ट डीडवाने में कायम किया है वह पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। यह बात ठीक है। इसका कारण जो यह बताया गया कि हमने उस कम्पनी को हमारे यहां के जो टेम्प्रेचर के फीगर्स दिये थे वे गलत दिए थे। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि उस कम्पनी को ५० साल के फीगर्स भेजे गये थे रेनफाल के और जो मुखतलिफ महीनों के टेम्प्रेचर के फीगर्स भेजे गए थे। उसके बाद उस कम्पनी ने सोडियम सल्फेट का पाइलोट प्रोजेक्ट जिसकी केपेसिटी २० टन पर डे है, कायम किया, क्योंकि यह प्रोजेक्ट पाइलोट प्रोजेक्ट है और हिन्दुस्तान में इस तरह का प्रोसेस जो बाइन्स से सोडियम सल्फेट बनाया जाता है वह पहला प्रोजेक्टहै, इसलिए वह कॉमिशयल प्रोजेक्ट ही कहा गया है और उसको पाइलोट प्रोजेक्ट कहेंगे। इसकी सक्सेस के बाद कॉमर्शियल एन्टरप्राइज़ बनाने का फैसला था। इसीलिए जब काम शुरू किया शुरू शुरू के अन्दर, तो प्रोडक्शन तो शुरू हो गया, फिर हमने कहा कि इसको आखिर करने से पहले हम प्रोडक्शन २० टन चाहते हैं, लेकिन वह प्रोडक्शन दो, तीन, चार टन ही चलता रहा। उसके ऊपर कम्पनी को लिखा गया। उसके इंजीनियर्स आये जो कि अभी तक हैं। उसके अन्दर मोडिफिकेशन जितना हो किया है और करने के बाद मैं सदन को सूचित करता हूँ कि वे मुझसे परसों ही मिले हैं और रिपोर्ट भी आई है कि १३ टन तक तो उन्होंने उसी मोडिफिकेशन के अन्दर कर दिया है, लेकिन मैंने कहा है कि जब तक २० टन प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक इनका पूरा खर्चा कम्पनी को देना पड़ेगा और जितना भी मोडिफिकेशन करना होगा वह एग्रीमेंट के अनुसार करना पड़ेगा। उन्होंने इसको स्वीकार किया है। उन्होंने इन्जीनियर्स भेजे हैं। वे कहते हैं, इसमें ही चैन्ज करके और खास तौर से कूलिंग टॉवर के अन्दर चैन्ज करना है; उसके बाद में २० टन का प्रोडक्शन करके देंगे। उसके बाद कॉमर्शियल का सवाल पैदा होगा। इसमें १० महीने की देरी हुई। उसके कारण मुझे खेद है कि उससे आमदनी कम हुई है, परन्तु साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यह हमारे हाथ की बात नहीं है। कम्पनी ने जो पाइलोट प्रोजेक्ट बनाकर भेजा था वह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जब सक्सेसफुल बनेगा तब अपन टेक ओवर करेंगे, वर्ना कम्पनी के आदमी काम कर रहे हैं।

इसके अलावा लिग्नाइट के बारे में कुछ चर्चा की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी सदन में बताया था कि पलाना लिग्नाइट की माइन के बारे में जो रशियन एक्सपर्ट्स आये हैं। उन्होंने काम पूरा परसों कर दिया है और उसके बाद रिपोर्ट भेज दी है। वह मेरे पास कल पहुंची है। उस रिपोर्ट का प्लानिंग कमीशन और राज्य सरकार अध्ययन करने के बाद आगे क्या करना है--उसके ऊपर पॉवर हाउस लगाना या पेट्रो केमिकल्स इन्डस्ट्रीज लगानी हैं, किस

(श्री मथुरादास माथुर)

तरह से माइनिंग करना है वह सब रिपोर्ट पर विचार करने के बाद में फैसला करेंगे ।

मैं समझता हूँ उपाध्यक्षजी, कि समय भी करीब करीब ५ बजे का होने जा रहा है और मेरे विषय के जो सवाल उठाये गये थे उनका मैंने उत्तर देने की कोशिश की है; और कोई प्रश्न माननीय सदस्य के रह गये हों तो फिर मौका आयेगा । इनकी डिमाण्ड्स भी आयेंगी, उनके ऊपर उत्तर दे दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : उपाध्यक्ष महोदय, टाइम तो कम है, मैं कल कन्टीन्यू करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : इनका भाषण तो ८ बजे तक भी हो तो हम सुनना चाहते हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : टाइम एक्स्टेन्ड कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप १० मिनट में समाप्त कर दें तो ५-७ मिनट हाउस का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री जुझारसिंह : कोशिश तो मैं करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मन्शा के अनुसार टाइम ५ मिनिट बढ़ाया जाता है ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उनका कल खत्म हो जायेगा । कल के लिए एक्स्टेन्ड कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष : Now it has been extended.

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट की भूमिका में बजट बनाने के प्रावधानों के बारे में कुछ जिक्र किया है और उन्होंने यह फर्माया है, यह बजट बनाने की भूमिका दी है और कहा है कि किस भूमिका में और किस परिस्थिति में उन्होंने इस बजट को तैयार किया है । तो मैं आपकी मार्फत सदन को बताना चाहता हूं कि वे परिस्थितियां क्या हैं, जिसमें यह बजट बना है । आज देश की क्या परिस्थिति है, किन परिस्थितियों में वह गुजर रहा है; उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या यह बजट वाजिब तरीके से बना हुआ है ? आप जानते हैं कि अभी एमर्जेन्सी का पीरियड खत्म नहीं हुआ है । ६२ में चीन का हमला हुआ हमारे देश पर और उस कॉन्टेक्स्ट में हमें बहुत सी बातें देखनी पड़ती हैं ।

मैं इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो एसेन्शियल खर्चे हैं उस एमर्जेन्सी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उनका इस बजट में ध्यान नहीं रखा है; जैसे कि आपने जो पुलिस का बजट है उसमें ४६.५२ लाख की इसी बजट में कमी बताई है । उसमें कम खर्चा हुआ है; इस वजह से कम खर्चा हुआ है कि जो ऐसेन्शियल एम्यूनिशन्स और आर्म्स और गाड़ियां पुलिस के लिए खरीदनी चाहिए थीं वे ये खरीद नहीं पाये हैं । उसकी वजह से ४६ लाख की बचत हुई है ।

उसी प्रकार इसी राज्य में अल्पकालीन समय के लिए जो एमर्जेन्सी के लिए एसेन्शियल एम्यूनिशन्स वगैरह खरीदने थे उसमें

(श्री जुझारसिंह)

भी ११.१० लाख रुपये की बचत हुई है। तो इस प्रकार से यह डिफेन्स के मामले में जिसका कि हमारी रक्षा से सम्बन्ध है उसमें ५७.७२ लाख की राज्य सरकार ने बचत की है। तो ऐसी चीजों पर बचत करने से आप अन्दाजा कर सकते हैं कि हमारे सुरक्षा के प्रयत्नों में कितनी कमी हुई है ?

(५.०० म.प.)

इसी प्रकार जो दूसरे एसेन्शियल खर्चे हैं जैसे शिक्षा, उसमें १०.०५ लाख की बचत है, वैज्ञानिक विभाग में १४.०४ लाख की बचत है, सोश्यल सिक्यूरिटी में, जिसमें गरीब आदमियों और बूढ़े आदमियों की पेन्शन का प्रावधान रखा था, उसमें १२.०७ लाख की बचत है। आपके मार्फत में वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो खर्चे, आज की हमारी देश की परिस्थिति में करना बहुत आवश्यक है उनमें बचत करना और जिनमें बचत करनी चाहिए थी उनको खर्च कर देना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। जिन चीजों में ज्यादा खर्चा हुआ है, उसमें से ६.८७ लाख रुपये एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा किया है, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को जो सरप्लस थे उनको टाइम पर एब्जोर्ब नहीं किया जा सका और उसकी वजह से सरकार को १० लाख रुपये ज्यादा खर्च करना पड़ा। इसी तरह से वन विभाग पर तीन लाख इसीलिए खर्चा किया है। यह वन विभाग जो पेइंग विभाग होना चाहिए था उसमें आमदनी के मुकाबले में हर साल खर्चा बढ़ता जा रहा है।

सदन को बताने की मेरी मन्शा है कि जो एसेन्शियल खर्चे हैं जिन पर बचत नहीं करनी चाहिए थी वहां हमारी सरकार पूरा खर्चा नहीं कर सकती है और सुरक्षा के सम्बन्ध में जैसे हमारा सैनिक स्कूल है जिसमें हमारे यहां के बच्चे पढ़कर निकलेंगे और फौजी ऑफीसर्स बनेंगे, उस तरफ राज्य सरकार ने अच्छी तवज्जोह नहीं दी है। जितना कोटा राज्य के लिए चितौड़गढ़ सैनिक स्कूल में निर्धारित है, उतने लड़के सैनिक स्कूल में नहीं बैठ पा रहे हैं। उसकी वजह से आगे जाकर यह जो फौजी एरिया है और जहां से बहुत से सैनिक आर्मी में जाते हैं उस अनुपात में अगर यहां ऑफिसर्स नहीं तैयार किए जाते तो उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार पर है।

उसी तरह से होर्स ब्रीडिंग की स्कीम भारत सरकार ने एप्रूव की थी। आज करीब ३५-४० लाख के घोड़े दूसरे देशों से इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं और इस परिस्थिति में जब खच्चरों और घोड़ों की हिमालय पर जरूरत पड़ती है उसमें भारत सरकार की स्कीम थी और राजस्थान सरकार द्वारा किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, उसका पूरा उपयोग नहीं उठा पाए हैं। ऐसा समय था जब भारत सरकार से सेंट पर्सेंट सब्सिडी मिलती थी, उस वक्त भी कोई फायदा नहीं उठाया और आज भी उसी दिशा में हैं। होर्स ब्रीडिंग का जो ऑक्युपेशन है, सेन्चुरीज से चला आया है, उस दिशा में फायदा नहीं उठा पाए हैं। उसके अलावा जो बोर्डर सिक्योरिटीज हैं, जहां पर बोर्डर कमिश्नर भी लगा हुआ है वहां पर भी हमें देखना है कि जिस रेश्यो में पाकिस्तान ने सड़कें बनाई

Page No 121

(श्री जुझारसिंह)

हैं, सक्यूलर रोड्स बनाए हैं, उस अनुपात में हमारी सिक्योरिटी को मजबूत नहीं किया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हुआ।

श्री जुझारसिंह : I shall continue my speech tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५. ५ बजे कल, दिनांक १३ मार्च, १९६५ के म.पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३२३ का उत्तर देखिये)

No. 500/Misc-2/58-1954
Government of India,
Central Water & Power Commission,
(Flood Wing)

New Delhi-2, the 27 th October, 1958

From
The Director,
Silt & Construction Materials Directorate.

To

The Executive Engineer,
Ajmer Irrigation Division,
Ajmer.

Ref:- Your No. 3428 dated 30th September, 1958.
Dear Sir,

The results of the total salt contant (percent) in the soil samples received from you are given below:-

S. No.	Sample No. given by Ex. Engineer.	Percent total soluble Salts.
1	7	0.140
2	9	0.150
3	11	0.160
4	13	0.190
5	15	0.180
6	17	0.200
7	19	0.135
8	20	0.130
9	21	0.640
10	23	0.567
11	24	0.190
12	25	0.750

It will be seen from the above that the soil represented by S. Nos. 9,10 and 12 contain a fair amount of salt contant and should be avoided for use in the construction of earth dam please.

Yours faithfully,

Sd/-R. C. Hoon,
Director.

———

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १२ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२८१५	३	सतीशन्द्र	सतीशचन्द्र
२८२४	१६	रघुनाथसिह बिश्नोई	रघुनाथ बिश्नोई
२८२९	१८	राशनकार्डों	राशन कार्डों
२८३४	२२	भैरोंसिह	भैरोंसिह
२८३५	८	भैरोंसिह	भैरोंसिह
२८४८	स्कम्भ	८४८	२८४८
,,	४	नाथूाम	नाथूराम
२८५६–२८५७	शीर्षक	मार्क	मार्च
२८५८–२८५९	,,	माच	मार्च
२८५९	१०	क्य ा	क्या
२८६०–२८६१	शीर्षक	मा	मार्च
२८६४	११	श्र अध्यक्ष :	श्री अध्यक्ष
,,	अन्तिम से ३	सिकरान	सिकराय
२८६५	शीर्षक	अ० स० तारांकित	अ० स० के तारांकित
२८६८	७	ब ध	बांध
२८७५	१२	डिस्पसरी	डिस्पेंसरी
२८८६	१३	एडवाण्सेज़	एडवान्सेज
२८८७	२	रीप्रेमेन्ट	रीपेमेन्ट
,,	२१	रुपमे	रुपया।
२८८८	१७	इन्ट्रेस्टेटड	इस्ट्रेस्टेड
२८९१	२५	दर आया	दर से आया
२९००	९	श्री मथुरेश बीहारी	श्री मथुरेशबिहारी
२९१२	शीर्ष	श्री ना राम	श्री नाथूराम
२९१८	,,	श्री रामीनवास	श्री नाथूराम
२९२५	२१	घूमाकर	घुमाकर

१	२	३	४
२६२७	२३	नाथूाम	नाथूराम
२६३१	१	स	से
२६३२	शीर्ष	ना राम	नाथूराम
२६३४	१३	नाथू ाम	नाथूराम
२६४१	२५	इन्स्ट्रुमेन्ट्स	इन्स्ट्रूमेन्ट्स
२६४२	शीर्ष	मिघा	मिर्धा
२६४३	८	व्यक्स्था	व्यवस्था
२६५१	८	बातीत	बातचीत
२६५७	शीर्षक	अग्रतर	अग्रेत्तर
२६६०	१	खा ो-पिओ	खाओ-पिओ
२६६०-६१	शीर्षक	१ मार्च	१२ मार्च
२६६८-६६	शीर्षक	माच	मार्च
२६७२	शीर्ष	केसरसिह	केसरीसिंह
२६८०	,,	न थीसिह	नत्थीसिंह
२६८२-८३	शीर्षक	१२ ार्च	१२ मार्च
२६६२	१	श्री पाघ्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
२६६५	२	दे रही है	दे रखी है
३००५	शीर्षक	अग्रतर	अग्रेत्तर
,,	२६	लड़कियों	लड़कियां
३००७	शीर्षक	अग्रतर	अग्रेत्तर
३०१६	१	१२'।	१२।।
३०१८	अन्तिम से ६	२ पर्सेंट	पर २ परसेंट
,,	,,	जोतीन	जो तीन
३०२०	८	राजवथान	राजस्थान
३०२१	२४	यहु	यह
३०२३	२४	माधुर	माथुर
३०२६	२३	चाहिते	चाहिये
३०२७	८	इ जब तक	इसलिये जब तक
,,	६	विका ।	विकास
३०३०	१	मंत्रीली	मंत्रीजी
३०३१	अन्तिम से ४	मा रादास	मथुरादास
३०३४	३	सब ो	सबसे
३०३७	अन्तिम से ५	समफ्या	समस्या

१	२	३	४
३०३८	अन्तिम से २	स्कूलें	स्कूलें
,,	अन्तिम से १	बा तसों	बातों से
३०४४	अन्ति ४	पर–एकड़अउट पुट	पर–एकड़ आउटपुट
३०४५	१	विल्कल	बिल्कुल
,,	६	जायेंगे	जायेंगे
३०४८	२४	कॉमिशयल	कॉमर्शियल
३०५०	२१	जुझासिह	जुझारसिंह
३०५०–६०५१	शीर्षक	मच	मार्च